RNI No. DELHIN/2012/48773 मासिक, जून 2026 वर्ष 14, अंक 6 ₹100

फेम इंडिया

सोच बदलें, समाज बदलेगा

सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी

एशिया पोस्ट - फेम इंडिया सर्वे

फेम इंडिया

www.thefameindia.com

वर्ष 14, अंक 6, जून 2026

एडिटर इन चीफ – धीरज कुमार
मैनेजिंग एडिटर – अनिल सिंह

एडिटोरियल टीम –
राकेश चौधरी, नीलम शुक्ला, सुनील सिंह, नम्रता नारायण, मनीष सिंह, देवेश मिश्रा, कल्पना पुंडीर, विजय पांडेय, अमरनाथ, दिलीप सिंह, हेमंत सिंह, रोहित रोहण, विकास सिंह, नीरज सहाय, सुधा पांडेय संतोष कुमार सिंह, संजय बाली

आर्ट डायरेक्टर – स्वर्ण लता

वेब टीम – मानवेंद्र प्रताप, रश्मि सिंह

सेल्स – अनामिका गौतम
मार्केटिंग – सुनील पुंडीर
सर्कुलेशन – प्रवीण मिश्रा

कानूनी सलाहकार
अमित खेमका, पुष्पेंदु शुक्ला, नंदन झा

(स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक राजश्री द्वारा ज्योति प्रिंटर्स, ई–94, सेक्टर 6, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर से मुद्रित एवं ए–533, जीडी कालोनी, मयूर विहार फेज–3, दिल्ली से प्रकाशित, संपादक – धीरज कुमार)

संपादकीय एवं मार्केटिंग ऑफिस
फेम इंडिया पब्लिकेशन प्रा.लि।
एफ 6, सेक्टर–50, नोएडा 201304 (उ.प्र.)
फोन नं. – +91– 9717727501 / 9451587800 / 0120 315 4572
ई मेल: fameindia.publication@gmail.com

RNI No. DELHIN/2012/48773

संपादकीय

2026 सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी

सकारात्मक पत्रकारिता : समय की सबसे बड़ी आवश्यकता

आज का भारत परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है। विज्ञान, तकनीक, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्टार्टअप, महिला सशक्तिकरण और डिजिटल क्रांति जैसे अनेक क्षेत्रों में देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया भारत को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में देख रही है। लेकिन इस विकास यात्रा के बीच एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि क्या समाज तक पहुँचने वाली सूचनाएँ संतुलित और सकारात्मक हैं? यही प्रश्न हमें सकारात्मक पत्रकारिता की आवश्यकता की ओर ले जाता है।

पत्रकारिता का मूल उद्देश्य केवल समाचार देना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक, प्रेरित और दिशा प्रदान करना भी है। दुर्भाग्य से वर्तमान समय में मीडिया का एक बड़ा हिस्सा नकारात्मक खबरों, विवादों, सनसनी और आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित होता जा रहा है। अपराध, राजनीतिक टकराव और सामाजिक तनाव की खबरें लगातार प्रमुखता से दिखाई जाती हैं, जबकि समाज में हो रहे रचनात्मक कार्य अक्सर चर्चा से बाहर रह जाते हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि लोगों के मन में निराशा और अविश्वास बढ़ने लगता है।

सकारात्मक पत्रकारिता का अर्थ यह नहीं है कि समस्याओं को छिपाया जाए या सत्ता से सवाल न पूछे जाएँ। बल्कि इसका वास्तविक अर्थ है—समस्याओं के साथ-साथ समाधान और प्रेरणादायक प्रयासों को भी समाज के सामने लाना। यदि कोई शिक्षक दूरदराज गांव में शिक्षा की अलख जगा रहा है, कोई जिलाधिकारी जल संरक्षण से हजारों लोगों का जीवन बदल रहा है, कोई डॉक्टर गरीबों के लिए नि:शुल्क सेवा दे रहा है या कोई युवा नवाचार से रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है, तो इन कहानियों को भी उतनी ही प्रमुखता मिलनी चाहिए जितनी नकारात्मक घटनाओं को मिलती है।

आज देश में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहाँ सकारात्मक सोच ने असंभव दिखने वाले कार्यों को संभव बनाया है। जल संरक्षण, महिला स्वयं सहायता समूह, डिजिटल शिक्षा, स्वच्छता अभियान, स्टार्टअप संस्कृति और ग्रामीण नवाचार जैसे क्षेत्रों में लाखों लोग चुपचाप परिवर्तन की नई कहानी लिख रहे हैं। सकारात्मक पत्रकारिता इन प्रयासों को समाज तक पहुँचा कर न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि विकास की प्रक्रिया को भी गति प्रदान करती है।

वर्तमान समय में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव ने सूचनाओं की गति तो बढ़ा दी है, लेकिन इसके साथ भ्रम, अफवाह और नकारात्मकता भी तेजी से फैलने लगी है। ऐसे समय में जिम्मेदार और सकारात्मक पत्रकारिता लोकतंत्र की मजबूती के लिए और भी आवश्यक हो जाती है। मीडिया यदि समाज में आशा, विश्वास और रचनात्मक सोच को बढ़ावा दे, तो वह केवल सूचना का माध्यम नहीं रहेगा, बल्कि राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण सहभागी बन जाएगा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि पत्रकारिता केवल "क्या गलत है" तक सीमित न रहे, बल्कि यह भी बताए कि "क्या बेहतर हो रहा है" और "कैसे बदलाव संभव है।" यही सकारात्मक पत्रकारिता की वास्तविक शक्ति है, और यही एक विकसित, जागरूक और आत्मविश्वासी भारत की पहचान भी बन सकती है।

धीरज

सर्वश्रेष्ठ
जिलाधिकारी 2026

सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी

32 **दीपेश कुमार**
विकास, नवाचार और जनसरोकारों को समर्पित एक संवेदनशील प्रशासक

50 **विशाल मिश्रा**
संघर्ष, साधना और सेवा की असाधारण प्रशासनिक यात्रा

58 **स्वरूपा टी के**
उडुपी में जनसंवेदनशील प्रशासन की सशक्त पहचान

06
रविंद्र कुमार
संकल्प, संवेदनशीलता और सुशासन के अधिकारी

12
राजेंद्र पैंसिया
संवेदनशील प्रशासन और जनसेवा का मजबूत चेहरा

24
मयूर दीक्षित
नवाचार, जल-संरक्षण और जन-केंद्रित शासन के प्रणेता

38
लक्ष्य सिंघल
युवा ऊर्जा, दूरदृष्टि और जनसेवा का प्रतीक

40
अस्मिता लाल
सस्टेनेबल गवर्नेंस, जनभागीदारी और संवेदनशीलता की नई पहचान

44
कोमल मित्तल
दूरदर्शी नेतृत्व, जनकेंद्रित प्रशासन और समावेशी विकास की मिसाल

48 **रोसेटा मैरी कुर्बाह**
संवेदनशील और जनकेंद्रित प्रशासन की सशक्त पहचान

52 **गौरव कुमार सिंह**
जनसेवा, नवाचार और सुशासन का सशक्त चेहरा

57 **जी. लक्ष्मीशा**
एनटीआर जिले में सुशासन और विकास के संवाहक

सर्वश्रेष्ठ
2026 **जिलाधिकारी**

सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026

उत्कृष्ट प्रशासकों को सम्मान देने की एक खास पहल

भारत एक विशाल देश है। यहाँ करोड़ों लोग रहते हैं — अलग-अलग भाषाएँ, अलग-अलग जरूरतें, अलग-अलग चुनौतियाँ। सरकार चाहे कितनी भी अच्छी योजनाएँ बनाए, लेकिन जब तक वे योजनाएँ जमीन पर नहीं उतरतीं — तब तक उनका कोई मतलब नहीं। और यह काम करता है जिला प्रशासन। और जिला प्रशासन की धुरी होता है — जिलाधिकारी।

जिलाधिकारी यानी कलेक्टर या डिप्टी कमिश्नर वह इंसान है जो सरकार की नीतियों और आम आदमी के बीच की कड़ी है। वह न सिर्फ एक अफसर है, बल्कि एक मैनेजर भी है, एक योजनाकार भी, और एक ऐसा नेता भी — जिसे संवेदनशीलता के साथ काम करना होता है। एक अच्छा जिलाधिकारी वह होता है जो सुनिश्चित करे कि विकास का फायदा समाज के उस आखिरी इंसान तक पहुँचे, जो खुद अपनी आवाज उठाने में सक्षम नहीं है।

लेकिन हमारे देश में अक्सर ऐसा होता है कि नेताओं की चर्चा तो खूब होती है, लेकिन वे अफसर जो रोजाना चुपचाप, बिना किसी शोर के, कठिन हालातों में काम करते हैं — वे अनदेखे रह जाते हैं। उनकी मेहनत, उनकी लगन, और उनकी उपलब्धियाँ आम जनता तक पहुँच ही नहीं पातीं।

इसी कमी को पूरा करने के लिए फेम इंडिया मैगजीन ने एक सराहनीय पहल की है। फेम इंडिया अपने विशेष अंक "सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026" के जरिए उन जिलाधिकारियों को देश के सामने लाना चाहता है, जिन्होंने अपने कार्यकाल में न केवल बेहतरीन प्रशासनिक काम किया, बल्कि नवाचार, संवेदनशीलता और जनसेवा की एक नई मिसाल भी पेश की।

यह काम आसान नहीं था। आज देश में लगभग 800 जिले हैं और हजारों प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं। इनमें से सर्वश्रेष्ठ 25 का चयन करना एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए फेम इंडिया ने देश की जानी-मानी सर्वे एजेंसी एशिया पोस्ट के साथ मिलकर एक व्यापक और निष्पक्ष सर्वेक्षण किया। इस सर्वे में विशेषज्ञों की राय, जमीनी रिपोर्ट, मीडिया विश्लेषण और विभिन्न स्रोतों से मिली जानकारी को आधार बनाया गया।

चयनित अधिकारियों को अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है और हर श्रेणी से एक सबसे बेहतर और लोकप्रिय जिलाधिकारी को इस विशेष अंक में जगह दी जा रही है।

यह सर्वे मुख्य रूप से 10 अहम मानदंडों पर आधारित है —उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमता, प्रभावी गवर्नेंस, दूरदर्शिता और नवाचार, जवाबदेह कार्यशैली, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, संकट प्रबंधन कौशल, संवेदनशीलता और गंभीरता, व्यवहार कुशलता, जनसंपर्क और संवाद क्षमता, और विकासोन्मुख सोच।

ये मानदंड बताते हैं कि यह सर्वे केवल कागजी उपलब्धियों को नहीं देखता — बल्कि यह देखता है कि एक अधिकारी असल में जमीन पर कैसे काम करता है, वह मुश्किल वक्त में कैसे फैसले लेता है, और आम लोगों से उसका रिश्ता कैसा है।

फेम इंडिया की यह पहल एक जिम्मेदार मीडिया संस्थान का बेहतरीन उदाहरण है। जब पूरी दुनिया में मीडिया का ध्यान सनसनी और विवाद पर होता है, तब इस तरह का सर्वे उन लोगों को रोशनी में लाता है जो चुपचाप देश बनाने में लगे हैं।

यह सर्वे सिर्फ सम्मान देने तक सीमित नहीं है। यह उन तमाम अधिकारियों के लिए एक प्रेरणा भी है जो कम संसाधनों में, कठिन परिस्थितियों में, दूर-दराज के इलाकों में काम करते हैं और सोचते हैं कि शायद उनके काम को कोई नहीं देखता। यह सर्वे उन्हें बताता है — देश देख रहा है, और देश को उन पर गर्व है।

विकासशील

संकल्प, संवेदनशीलता और सुशासन के अधिकारी

रविंद्र कुमार (आजमगढ़)

वर्ष 2011 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयन के बाद उन्होंने सिक्किम, उत्तर प्रदेश तथा भारत सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। जुलाई 2019 से अक्टूबर 2021 तक बुलंदशहर में जिलाधिकारी के रूप में सेवा देने के बाद वे अक्टूबर 2021 में झांसी स्थानांतरित हुए, जहाँ अक्टूबर 2023 तक कार्यरत रहे। इसके बाद बरेली में पदभार संभाला और फिर अप्रैल 2025 में आजमगढ़ के जिलाधिकारी और कलेक्टर के रूप में तैनात किए गए। प्रत्येक जिले की अपनी अनूठी चुनौतियाँ थीं — और प्रत्येक बार उनकी प्रशासनिक प्रतिक्रिया ने स्थायी छाप छोड़ी।

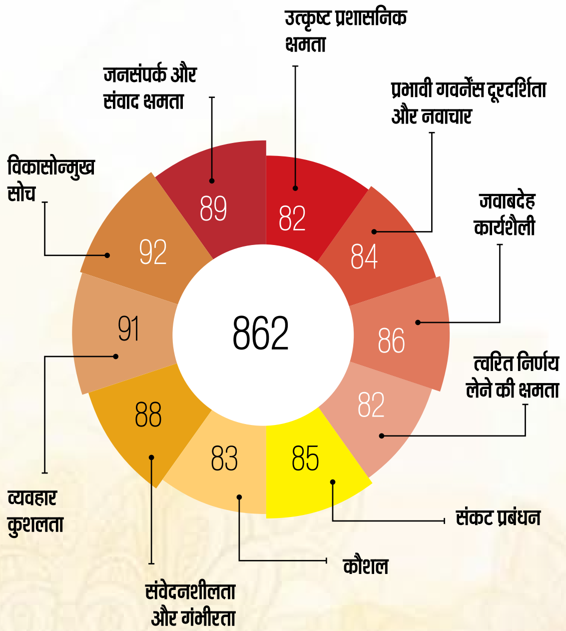

फेम इंडिया-एशिया पोस्ट के 'सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026' के वार्षिक सर्वे में प्रशासनिक अधिकारी रविंद्र कुमार को 'विकासशील' श्रेणी में प्रमुख पाया गया है।

रविंद्र कुमार की प्रशासनिक यात्रा यह सिद्ध करती है कि एक जिलाधिकारी केवल सरकारी आदेशों का क्रियान्वयन करने वाला अधिकारी नहीं, बल्कि समाज में वास्तविक और स्थायी परिवर्तन लाने वाला उत्प्रेरक भी हो सकता है। रविंद्र कुमार जैसे अधिकारी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को न केवल मजबूत बनाते हैं, बल्कि आम नागरिक के जीवन में बदलाव की उम्मीद भी जगाते हैं।

रविंद्र कुमार, उत्तर प्रदेश कैडर के 2011 बैच के उन विशिष्ट आईएएस अधिकारियों में शामिल हैं जिन्होंने प्रशासनिक सेवा को महज एक सरकारी दायित्व नहीं, बल्कि जनसेवा और सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बनाया है। आम जनमानस में वे एक असाधारण पर्वतारोही के रूप में जाने जाते हैं — दो बार एवरेस्ट फतह करने वाले, 11 पुस्तकों के लेखक और एक पूर्व नाविक। लेकिन प्रशासनिक जगत में उनकी पहचान कहीं अधिक गहरी है — एक ऐसे अधिकारी के रूप में जो जल संरक्षण, कानून-व्यवस्था प्रबंधन और विकासोन्मुख शासन को एक साथ साधने में सिद्धहस्त हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में जिलाधिकारी के रूप में उनके कार्यकाल ने यह बार-बार सिद्ध किया है कि यदि प्रशासनिक इच्छाशक्ति दृढ़ हो, तो सीमित संसाधनों में भी बड़े और स्थायी बदलाव लाए जा सकते हैं।

यदि कोई एक सूत्र है जो रविंद्र कुमार के सभी जिलों के कार्यकाल को एकता के धागे में पिरोता है, तो वह है जल संरक्षण के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता। उन्होंने इसे केवल एक विभागीय औपचारिकता नहीं माना, बल्कि इसे एक व्यापक जनआंदोलन का रूप दिया — जिसमें प्रशासन, स्थानीय निकाय और आम नागरिक सभी सक्रिय भागीदार बने।

बुलंदशहर में उन्होंने नीम नदी के पुनर्जीवन का बीड़ा उठाया, जो वर्षों से प्रदूषण और अतिक्रमण की शिकार थी। प्रशासन, ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों को एक साझा मंच पर लाकर नदी की सफाई, जलधारा की बहाली, अतिक्रमण हटाने और वर्षा जल संरक्षण के ठोस कदम उठाए गए। इसका परिणाम केवल पर्यावरणीय सुधार तक सीमित नहीं रहा — किसानों और ग्रामीणों को बेहतर जल उपलब्धता के रूप में इसका प्रत्यक्ष लाभ मिला।

झांसी का कार्यकाल जल संरक्षण के संदर्भ में सबसे चर्चित और प्रशंसित माना जाता है। बुंदेलखंड दशकों से गंभीर जल संकट और सूखे की त्रासदी झेलता आया है। ऐसे चुनौतीपूर्ण भूगोल में रविंद्र कुमार ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तकनीक-आधारित निगरानी और जनसहभागिता के त्रिकोणीय मॉडल पर काम किया। उनके नेतृत्व में चार नदियों के पुनर्जीवन का कार्य हुआ, तालाबों की सफाई की गई, जल संरचनाओं का निर्माण हुआ और पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया गया। इन समग्र प्रयासों के परिणामस्वरूप जिले के कई हिस्सों में भूजल स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई — एक ऐसी उपलब्धि जो न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी दूरगामी महत्व रखती है।

आजमगढ़ में उन्होंने तमसा नदी के पुनरुद्धार को प्राथमिकता दी। गंगा की यह प्राचीन सहायक नदी रामायण में उल्लिखित है और स्थानीय जनजीवन की आस्था से गहराई से जुड़ी है। दशकों की उपेक्षा ने इसे गाद, खरपतवार और कचरे से भर दिया था। 2025 में रविंद्र कुमार ने एक गहन माह-भर का पुनर्जीवन अभियान शुरू किया जिसमें अंतर-विभागीय समन्वय, सतत निगरानी और मजबूत जमीनी भागीदारी को केंद्र में रखा गया। स्थानीय निवासियों, श्रद्धालुओं और ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता ने इस अभियान को एक शासकीय परियोजना से एक जनआंदोलन में रूपांतरित कर दिया। यह अभियान आज प्रशासनिक संकल्प, सांस्कृतिक संवेदनशीलता और पर्यावरणीय चेतना के सफल संयोजन का एक प्रेरक उदाहरण बन चुका है।

रविंद्र कुमार की कानून-व्यवस्था प्रबंधन शैली सख्ती और सामुदायिक संवाद के बीच एक सुचिंतित संतुलन को दर्शाती है। सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान उन्होंने स्थिति को संयम और दृढ़ता से नियंत्रित किया। हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने मुआवजा वसूली भी सुनिश्चित की — जो प्रशासनिक जवाबदेही और कानून के प्रति सख्त प्रतिबद्धता का स्पष्ट संदेश था।

बरेली जैसे सामाजिक रूप से संवेदनशील जिले में उनका कार्यकाल विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा। नियमित सामुदायिक संवाद, पुलिस-प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय और सक्रिय फील्ड उपस्थिति के बल पर उन्होंने जिले में शांति और सौहार्द का वातावरण कायम रखा। उनके नेतृत्व में बरेली ने विकास के मोर्चे पर भी उल्लेखनीय प्रगति की और 2024-25 में समग्र विकास श्रेणी में प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया — जो उनके कार्यकाल की व्यापक सफलता का प्रमाण है।

आजमगढ़ में संगठित अपराध और आपराधिक गिरोहों के विरुद्ध उनके प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत व्यापक और कठोर अभियान चलाया। रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2026 में इस कानून के तहत उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कार्रवाई आजमगढ़ में दर्ज की गई — जो अपराध नियंत्रण के प्रति उनकी दृढ़ और अडिग नीति को रेखांकित करता है।

रविंद्र कुमार का शासन दर्शन कार्यालय की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। वे नियमित फील्ड दौरों, संरचित समीक्षा बैठकों और समयबद्ध कार्यान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। डिजिटल निगरानी और तकनीकी उपकरणों का उपयोग करते हुए वे परियोजनाओं की प्रगति पर कड़ी नजर रखते हैं और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। उनके नेतृत्व वाले जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण अवसंरचना और जनकल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन के मामले में राज्य स्तरीय रैंकिंग में निरंतर सुधार दर्ज हुआ।

मुख्यमंत्री युवा अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा विशेष रूप से सम्मानित किया गया। यह सम्मान युवाओं को रोजगार, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता से जोड़ने के उनके सतत प्रयासों की स्वीकृति है। वे मानते हैं कि युवाओं की सक्रिय भागीदारी के बिना कोई भी विकास योजना अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकती।

असरदार

दक्षता और संवेदनशील प्रशासन का सशक्त संगम

राघवेंद्र सिंह (जबलपुर)

वर्ष 1984 में यूपी के महाराजगंज में जन्मे राघवेंद्र सिंह ने अपने जीवन की शुरुआत सामान्य परिवेश से की, लेकिन मेहनत, अध्ययनशीलता और स्पष्ट लक्ष्य के बल पर उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित सेवा में स्थान प्राप्त किया। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से बी.एससी. की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान जेएनयू से राजनीति विज्ञान में एम.ए. तथा एम.फिल. किया। राजनीति विज्ञान जैसे विषय का गहन अध्ययन उनके प्रशासनिक दृष्टिकोण में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शासन, समाज, लोकतंत्र और जनभागीदारी के प्रति उनकी समझ उन्हें एक व्यवहारिक एवं दूरदर्शी प्रशासक बनाती है।

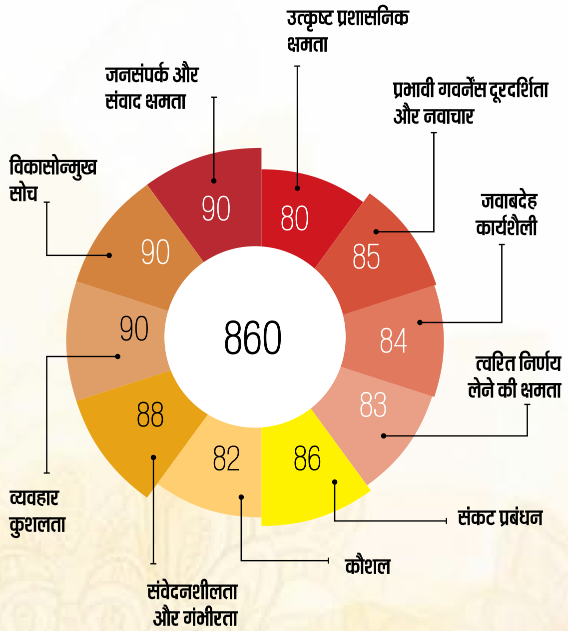

फेम इंडिया-एशिया पोस्ट के 'सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026' के वार्षिक सर्वे में प्रशासनिक अधिकारी राघवेंद्र सिंह को 'असरदार' श्रेणी में प्रमुख पाया गया है।

कलेक्टर के रूप में अलीराजपुर और आगर मालवा जैसे जिलों में उनका कार्यकाल विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है। आदिवासी बहुल और विकास की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में कार्य करते हुए उन्होंने प्रशासन को केवल कार्यालयों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि गांवों और आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होने बुजुर्गों के लिये ऑपरेशन स्माइल शुरू किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया। उनके कार्यकाल में जनसुनवाई और संवाद व्यवस्था को मजबूत बनाने की कोशिशें भी देखने को मिलीं। वे ऐसे अधिकारी माने जाते हैं जो फाइलों के साथ-साथ फील्ड विजिट को भी समान महत्व देते हैं।

राघवेंद्र सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों में गिने जाते हैं जिन्होंने अपनी कार्य-शैली, संवेदनशील सोच और विकासोन्मुख दृष्टिकोण से प्रशासन को केवल सरकारी व्यवस्था तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि उसे आम नागरिकों के जीवन से जोड़ने का प्रयास किया। बिहार कैडर के वर्ष 2013 बैच के आईएएस अधिकारी राघवेंद्र सिंह वर्तमान में मध्यप्रदेश कैडर में जबलपुर जिले के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनका व्यक्तित्व एक ऐसे प्रशासक का उदाहरण प्रस्तुत करता है जो कठोर प्रशासनिक क्षमता के साथ-साथ मानवीय संवेदनाओं को भी समान महत्व देता है।

राघवेंद्र सिंह की प्रशासनिक यात्रा विविध अनुभवों से भरी रही है। उन्होंने अलग-अलग राज्यों, जिलों और विभागों में कार्य करते हुए प्रशासन के कई महत्वपूर्ण आयामों को निकट से समझा। बिहार कैडर में उन्होंने अपना प्रोबेशन पीरियड मोतिहारी से शुरू किया। भागलपुर एवं मधुबनी एसडीएम रहे। फिर उनकी तैनाती गया में जिला पंचायत के सीईओ के रूप में हुई। बक्सर के जिलाधिकारी के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवायें दीं। मार्च 2020 वे मध्य प्रदेश कैडर में आ गये। यहां वाणिज्य कर विभाग, इंदौर में अपर आयुक्त के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने प्रशासनिक अनुशासन, वित्तीय प्रबंधन और विभागीय दक्षता पर विशेष ध्यान दिया। इसके बाद अपर कलेक्टर के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें जमीनी प्रशासन के और अधिक निकट पहुंचाया।

उनकी कार्यशैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समस्याओं को केवल आंकड़ों के आधार पर नहीं देखते, बल्कि उनके सामाजिक और मानवीय पक्ष को भी समझने का प्रयास करते हैं। प्रशासनिक पद पर रहते हुए भी उनकी भाषा और व्यवहार में सरलता दिखाई देती है। यही गुण उन्हें एक लोकप्रिय और प्रभावी अधिकारी बनाते हैं।

जबलपुर मध्यप्रदेश का एक प्रमुख शहर है, जहां शहरी विकास, यातायात व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण, कानून-व्यवस्था, राजस्व प्रशासन और नागरिक सुविधाओं जैसे विषय यहां अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में राघवेंद्र सिंह ने संतुलित और योजनाबद्ध प्रशासनिक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास किया है।

उनकी प्रशासनिक सोच में "जनभागीदारी" का विशेष महत्व दिखाई देता है। वे मानते हैं कि किसी भी योजना की सफलता तभी संभव है जब उसमें जनता की भागीदारी और विश्वास जुड़ा हो। इसी सोच के कारण वे विभिन्न सामाजिक संगठनों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के साथ संवाद स्थापित करने को प्राथमिकता देते हैं।

राघवेंद्र सिंह शिक्षा और युवाओं से जुड़े विषयों के प्रति भी विशेष रूप से संवेदनशील माने जाते हैं। वे यह समझते हैं कि किसी भी समाज के विकास में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण आधार होती है। इसलिए वे विद्यालयों की स्थिति, विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षण गुणवत्ता और युवाओं के कौशल विकास जैसे मुद्दों को गंभीरता से लेते रहे हैं। कई अवसरों पर उन्होंने विद्यार्थियों और युवाओं से सीधे संवाद कर उन्हें प्रेरित करने का प्रयास भी किया है।

प्रशासनिक जीवन में चुनौतियां हर अधिकारी के सामने आती हैं, लेकिन राघवेंद्र सिंह की पहचान उन अधिकारियों में की जाती है जो दबाव की परिस्थितियों में भी शांत और संतुलित निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं। संकट प्रबंधन और त्वरित कार्रवाई की उनकी क्षमता प्रशासनिक तंत्र को प्रभावी बनाने में सहायक रही है। चाहे प्राकृतिक आपदा की स्थिति हो, कानून-व्यवस्था की चुनौती हो या विकास योजनाओं का क्रियान्वयन—उन्होंने हर परिस्थिति में जिम्मेदारीपूर्ण भूमिका निभाने का प्रयास किया है।

उनकी कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही का भाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वे प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक सरल और आम नागरिकों के अनुकूल बनाने के पक्षधर रहे हैं। आम जनता की शिकायतों के त्वरित समाधान और अधिकारियों-कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

राघवेंद्र सिंह की एक और विशेषता उनकी अध्ययनशील प्रवृत्ति है। राजनीति विज्ञान जैसे विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के कारण वे सामाजिक और प्रशासनिक मुद्दों को गहराई से समझते हैं। उन्होंने छात्र जीवन पर आधारित '615 पूर्वांचल हास्टल' नामक उपन्यास भी लिखा है।

उनकी प्रशासनिक यात्रा यह संदेश देती है कि एक अधिकारी यदि इच्छाशक्ति, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करे तो वह शासन व्यवस्था को लोगों के लिए अधिक उपयोगी और प्रभावी बना सकता है। राघवेंद्र सिंह ऐसे ही अधिकारियों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को केवल पद के रूप में नहीं, बल्कि समाज के प्रति दायित्व के रूप में स्वीकार किया है। उनकी कार्यशैली में अनुशासन है, लेकिन कठोरता नहीं; संवेदनशीलता है, लेकिन कमजोरी नहीं; और विकास की दृष्टि है, लेकिन दिखावे की राजनीति नहीं। यही संतुलन उन्हें एक प्रभावी, विश्वसनीय और जनप्रिय प्रशासक के रूप में स्थापित करता है।

अपने अब तक के प्रशासनिक अनुभव, बौद्धिक क्षमता और जनसेवा के प्रति समर्पण के आधार पर राघवेंद्र सिंह भविष्य में भी प्रशासनिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखते हैं। वे उन युवा अधिकारियों के लिए भी प्रेरणा हैं जो प्रशासन को केवल करियर नहीं, बल्कि समाज परिवर्तन का माध्यम मानते हैं।

दूरदर्शी

बदलाव, दूरदर्शिता और जवाबदेही के संवाहक

आनंद शर्मा (मधुबनी)

वर्ष 2013 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शर्मा की गतिशील, तकनीक-आधारित और परिणामोन्मुख प्रशासनिक शैली ने उन्हें जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय और विश्वसनीय अधिकारी के रूप में स्थापित किया है। वे उन दुर्लभ प्रशासकों में से हैं जो कार्यालय की चारदीवारी से निकलकर जनता के बीच जाते हैं, उनकी पीड़ा सुनते हैं और उसे नीति तथा क्रियान्वयन में बदलने का संकल्प लेकर लौटते हैं। यही कारण है कि मधुबनी की जनता उनमें केवल एक अधिकारी नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद साथी देखती है।

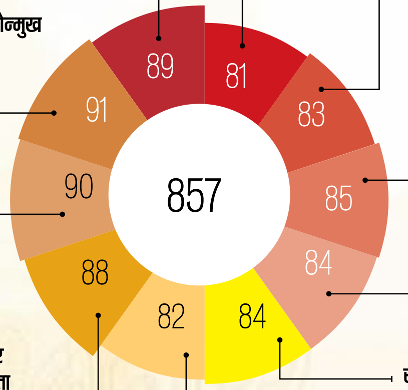

फेम इंडिया-एशिया पोस्ट के 'सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026' के वार्षिक सर्वे में प्रशासनिक अधिकारी आनंद शर्मा को 'दूरदर्शी' श्रेणी में प्रमुख पाया गया है।

डिजिटल प्रशासन के क्षेत्र में आनंद शर्मा को बिहार के अग्रणी और दूरदर्शी अधिकारियों में गिना जाता है। उन्होंने ई-पंचायत एवं ई-ग्राम कचहरी जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में निर्णायक भूमिका निभाई। उनके कुशल नेतृत्व में सहरसा बिहार का पहला पूर्णतः पेपरलेस जिला प्रशासन बना — यह उपलब्धि न केवल तकनीकी दृष्टि से अभूतपूर्व थी, बल्कि इसने सामान्य नागरिक और सरकारी व्यवस्था के बीच की दूरी को भी कम किया। इसके साथ ही, सहकारिता विभाग को राज्य का पहला पूर्णतः पेपरलेस विभाग बनाने का ऐतिहासिक श्रेय भी उन्हें प्राप्त है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं में तकनीक के सुनियोजित उपयोग ने न केवल कार्यों की गति और दक्षता बढ़ाई, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही को भी एक नई और ठोस मजबूती प्रदान की।

मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा एक ऐसे अधिकारी हैं, जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता, नवाचार की अदम्य भावना और निष्कलंक कार्यशैली के बल पर जिले के प्रशासनिक परिदृश्य को एक नई दिशा दी है। उनका नाम आज उन अधिकारियों की उस विशिष्ट श्रेणी में शुमार है, जो यह सिद्ध करते हैं कि प्रशासन केवल शक्ति का माध्यम नहीं, बल्कि समाज-परिवर्तन का सबसे सशक्त औज़ार हो सकता है।

फेम इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी जनमत सर्वेक्षण में आनंद शर्मा को देश के सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारियों में शामिल किया जाना उनकी कार्यक्षमता, संवेदनशीलता और जनविश्वास का एक प्रामाणिक प्रमाण है। यह सम्मान केवल प्रशासनिक उपलब्धियों का प्रतीक नहीं है, बल्कि उस गहरे जनविश्वास का दर्पण है जो आम नागरिक उनके नेतृत्व में अनुभव करते हैं। जनता का यह प्रेम और सम्मान किसी भी पुरस्कार से बड़ा होता है और आनंद शर्मा ने इसे अर्जित किया है — अपने कर्मों से, अपनी निष्ठा से।

आनंद शर्मा की प्रशासनिक यात्रा अनुभव और उपलब्धियों की एक समृद्ध गाथा है। वे मुंगेर और सहरसा के जिलाधिकारी, भागलपुर के उप विकास आयुक्त तथा पटना के अनुमंडल पदाधिकारी जैसे अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर चुके हैं। प्रत्येक पद पर उन्होंने प्रशासन को केवल फाइलों और बैठकों तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि उसे जनभागीदारी और जनविश्वास का जीवंत माध्यम बनाया। उनका यह दृढ़ विश्वास रहा है कि शासन व्यवस्था तभी वास्तव में प्रभावी होती है, जब वह पारदर्शी, जवाबदेह और आम नागरिक के लिए सहज रूप से उपलब्ध हो।

उनकी नवीनतम और अत्यंत चर्चित पहल है — 'मधुबनी फर्स्ट डैशबोर्ड', जो एक एकीकृत रीयल-टाइम निगरानी मंच के रूप में कार्य करता है। इस नवाचारी मंच के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं, निरीक्षणों, भूमि प्रबंधन, शिकायत निवारण और जवाबदेही से जुड़े समस्त कार्यों की सतत और पारदर्शी मॉनिटरिंग संभव हो सकी है। यह पहल इस बात का प्रमाण है कि प्रशासनिक सुधार केवल नीतियों और वक्तव्यों से नहीं, बल्कि प्रभावी तकनीकी क्रियान्वयन और दृढ़ इच्छाशक्ति से भी संभव होते हैं। जब डैशबोर्ड पर प्रत्येक योजना की प्रगति दिखती है, तो जनता को यह विश्वास होता है कि उनका पैसा और उनकी उम्मीदें दोनों सही हाथों में हैं।

लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त और जीवंत बनाने में भी आनंद शर्मा का योगदान अत्यंत उल्लेखनीय रहा है। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में उन्होंने चुनावी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और जनविश्वास के अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। उनके नेतृत्व में स्थापित व्यवस्थाओं ने मतदाताओं का विश्वास और अधिक मजबूत किया। उनके इसी सुदृढ़ नेतृत्व का परिणाम था कि वर्ष 2026 में मधुबनी जिले को माननीय राष्ट्रपति द्वारा सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन जिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया — यह पुरस्कार पूरे जिले की उस लोकतांत्रिक चेतना का सम्मान था, जिसे आनंद शर्मा ने अपने प्रयासों से जागृत और पोषित किया था।

पंचायती राज व्यवस्था को जमीनी स्तर पर सुदृढ़ और सार्थक बनाने के क्षेत्र में उनके अथक प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर भी भरपूर सराहना मिली। वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रदान किया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार इसी राष्ट्रीय स्वीकृति का प्रतीक है। जब गाँव के आखिरी व्यक्ति तक शासन की योजनाएँ पहुँचती हैं, तो यही असली लोकतंत्र होता है — और यही आनंद शर्मा का सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है।

आनंद शर्मा की इन प्रशासनिक सफलताओं के पीछे एक अत्यंत उत्कृष्ट और प्रेरणास्पद शैक्षणिक यात्रा भी रही है। उन्होंने इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रदेश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया और उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल से स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इसके पश्चात उन्होंने हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय, कानपुर से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित एफएमएस संस्थान से एमबीए की उपाधि अर्जित की। उनकी असाधारण बौद्धिक क्षमता का परिचय इस एक तथ्य से मिलता है कि उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा को प्रथम प्रयास में ही उत्तीर्ण किया।

परंतु जो बात आनंद आनंद शर्मा को वास्तव में विशिष्ट और स्मरणीय बनाती है, वह है जनसेवा के प्रति उनकी वह अटूट, निस्वार्थ और अडिग प्रतिबद्धता जो उनके प्रत्येक कार्य में झलकती है। वे केवल योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित रहने वाले अधिकारी नहीं हैं — वे एक ऐसे प्रशासक हैं जो शासन को जन-आंदोलन में रूपांतरित करने की अपूर्व क्षमता रखते हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने से लेकर प्रशासन के डिजिटलीकरण और नागरिक-केंद्रित सुधारों तक, उन्होंने अनवरत यह सिद्ध किया है कि सुशासन केवल कठोर नियमों से नहीं, बल्कि संवेदनशीलता, नवाचार और अडिग प्रतिबद्धता से संभव होता है। मधुबनी की जो नई इबारत वे लिख रहे हैं, वह केवल एक जिले की कहानी नहीं — वह उस भारत की कहानी है जो बदलाव को संभव मानता है।

सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026
13

कर्मठ

संवेदनशील प्रशासन और जनसेवा का मजबूत चेहरा

राजेंद्र पैंसिया (संभल, वर्तमान में मुरादाबाद)

भारतीय प्रशासनिक सेवा में कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं, जो केवल अपने पद के कारण नहीं, बल्कि अपने कार्यों और व्यवहार के कारण लोगों के बीच अलग पहचान बनाते हैं। उत्तर प्रदेश कैडर के कर्तव्यनिष्ठ आईएएस अधिकारी और उन्हीं में से एक माने जाते हैं राजेंद्र पैंसिया। प्रशासनिक दक्षता, संवेदनशील सोच, शिक्षा और समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण ने उन्हें एक लोकप्रिय और प्रभावशाली अधिकारी के रूप में स्थापित किया है।

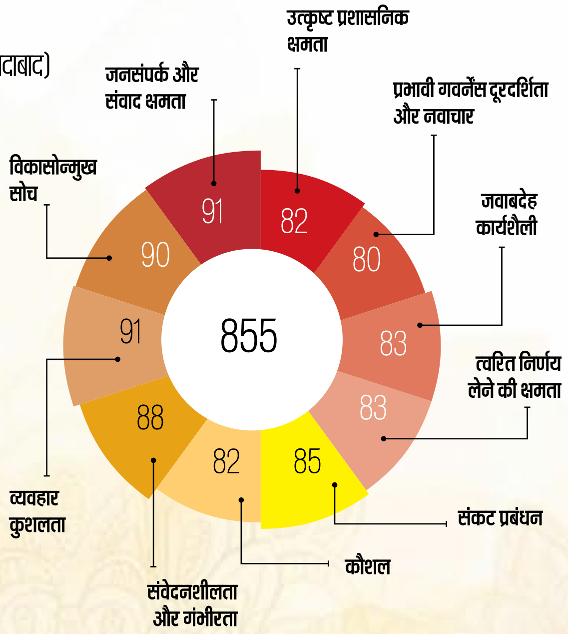

फेम इंडिया-एशिया पोस्ट के 'सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026' के वार्षिक सर्वे में प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र पैंसिया को 'कर्मठ' श्रेणी में प्रमुख पाया गया है।

राजेंद्र पैंसिया शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और जनभागीदारी को प्रशासन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। उनके कार्यकाल में जिले में शिक्षा और जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं को गति देने का प्रयास किया गया है। उनका मानना रहा है कि किसी भी समाज के विकास का सबसे मजबूत आधार शिक्षा और जागरूक नागरिक होते हैं। यही सोच उनके प्रशासनिक निर्णयों और सामाजिक कार्यों में भी दिखाई देती है।

राजेंद्र पैंसिया का प्रशासनिक सफर केवल सरकारी जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने समाज और शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी विशेष पहचान बनाई है। वे उन अधिकारियों में शामिल हैं, जिन्होंने हमेशा यह प्रयास किया कि प्रशासन का वास्तविक लाभ आम लोगों तक पहुंचे। उनकी कार्यशैली में अनुशासन, पारदर्शिता और जनता के प्रति संवेदनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

उनकी प्रारंभिक शिक्षा और व्यक्तित्व निर्माण में सामाजिक मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यही कारण है कि प्रशासनिक सेवा में आने के बाद भी उन्होंने अपने कार्यों में मानवीय दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी। वे हमेशा इस बात पर जोर देते रहे हैं कि प्रशासन का उद्देश्य केवल नियमों का पालन कराना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाना भी है।

राजेंद्र पैंसिया ने अपने प्रशासनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। विभिन्न जिलों और विभागों में कार्य करते हुए उन्होंने विकास कार्यों को गति देने, सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनसमस्याओं के समाधान पर विशेष ध्यान दिया। उनके नेतृत्व में कई क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में कार्य हुए।

एक जिलाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनकी सबसे बड़ी विशेषता जनता से जुड़ाव रही है। वे फील्ड विजिट्स, जनसुनवाई और सीधा संवाद स्थापित करने में विश्वास रखते हैं। यही वजह है कि आम लोगों के बीच उनकी छवि एक सहज और संवेदनशील अधिकारी की रही है। वे समस्याओं को केवल फाइलों तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें जमीन पर जाकर समझने और समाधान निकालने का प्रयास करते हैं।

प्रशासनिक सेवा में कार्य करते हुए उन्होंने तकनीक और नवाचार को भी महत्व दिया। बदलते समय के साथ प्रशासन को आधुनिक और जवाबदेह बनाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहा। डिजिटल माध्यमों के उपयोग, बेहतर प्रबंधन और समयबद्ध कार्यप्रणाली के जरिए उन्होंने प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में प्रयास किए।

राजेंद्र पैंसिया का व्यक्तित्व केवल एक अधिकारी तक सीमित नहीं है। वे प्रेरणादायक वक्ता और सकारात्मक सोच रखने वाले व्यक्तित्व के रूप में भी पहचाने जाते हैं। युवाओं, छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के बीच उनके विचारों को काफी सराहा जाता है। वे मेहनत, ईमानदारी और निरंतर सीखने को सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार मानते हैं।

उनके कार्यकाल में जनता से संवाद और समस्याओं के त्वरित समाधान को विशेष महत्व दिया गया। आज जब लोग प्रशासन से पारदर्शिता और जवाबदेही की अपेक्षा करते हैं, तब राजेंद्र पैंसिया जैसे अधिकारी प्रशासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करने का कार्य करते हैं। उनका मानना है कि प्रशासन तभी सफल माना जाएगा, जब आम नागरिक स्वयं को व्यवस्था से जुड़ा हुआ महसूस करे।

उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाते हुए उन्होंने विकास योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया। वर्तमान में संभल जिले में उनकी कार्यशैली विकासोन्मुख प्रशासन की मिसाल मानी जा रही है। जिले में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने, सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने तथा जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान की दिशा में लगातार प्रयास किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों की निगरानी, जनसुनवाई के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुनना और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहा है।

उनकी कार्यशैली में अनुशासन और मानवीय दृष्टिकोण का संतुलन दिखाई देता है। यही कारण है कि वे प्रशासनिक सेवा में कार्यरत युवा अधिकारियों और विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। वे इस बात का उदाहरण हैं कि एक अधिकारी यदि सकारात्मक सोच और जनहित की भावना के साथ काम करे, तो वह समाज में वास्तविक परिवर्तन ला सकता है।

आज के समय में प्रशासनिक अधिकारियों के सामने अनेक चुनौतियां हैं। तेजी से बदलती सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में जनता की अपेक्षाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे समय में राजेंद्र पैंसिया जैसे अधिकारी यह संदेश देते हैं कि प्रशासन का मूल उद्देश्य केवल शासन चलाना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर और सुरक्षित बनाना है।

राजेंद्र पैंसिया की पहचान एक ऐसे अधिकारी के रूप में बनी है, जिन्होंने प्रशासनिक जिम्मेदारियों को ईमानदारी, संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच के साथ निभाया। उनकी कार्यशैली यह दिखाती है कि प्रशासनिक सेवा केवल पद और अधिकार का माध्यम नहीं, बल्कि समाज और देश की सेवा करने का एक बड़ा अवसर है।

निस्संदेह, राजेंद्र पैंसिया का प्रशासनिक और सामाजिक योगदान आने वाले समय में भी लोगों के लिए प्रेरणा बना रहेगा।

जिम्मेदार

दूरदर्शी नेतृत्व, संवेदनशील प्रशासन और विकास के प्रति समर्पण

नितिन भदौरिया (उधमसिंह नगर)

नितिन भदौरिया एक ऐसे ऊर्जावान, दूरदर्शी और जन केंद्रित प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में सुशासन, विकास और मानवीय संवेदनाओं का अद्भुत संतुलन प्रस्तुत किया है। उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता, विविध अनुभव और सेवा के प्रति समर्पण उन्हें समकालीन प्रशासनिक अधिकारियों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करता है। नितिन भदौरिया की प्रारंभिक शिक्षा कानपुर के प्रतिष्ठित जयपुरिया स्कूल में हुई, जहाँ उन्होंने वर्ष 1988 से 2000 तक अध्ययन किया।

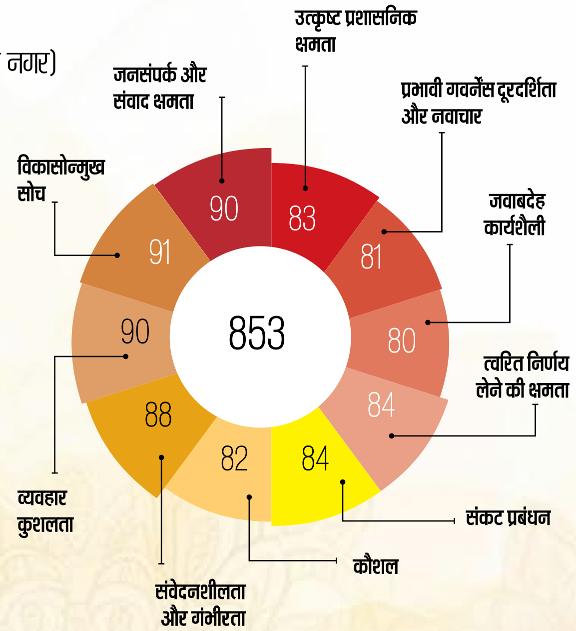

फेम इंडिया-एशिया पोस्ट के 'सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026' के वार्षिक सर्वे में प्रशासनिक अधिकारी नितिन भदौरिया को 'जिम्मेदार' श्रेणी में प्रमुख पाया गया है।

वर्तमान में नितिन भदौरिया उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। उनके नेतृत्व में जिला प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। पीएम.जनमन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उन्हें भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट के सम्मान से नवाजा गया। यह उपलब्धि उनके नेतृत्व, योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और अंतिम व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुँचाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य के लिए जिले को दो सिल्वर मेडल भी प्राप्त हुए हैं। यह सम्मान शिक्षाए स्वास्थ्य, पोषण, आधारभूत संरचना और समग्र विकास के क्षेत्र में प्रशासनिक उत्कृष्टता का प्रतीक हैं।

नितिन भदौरिया छात्र जीवन से ही वे मेधावी, अनुशासित और बहुआयामी प्रतिभा के धनी रहे। उन्होंने देश के अग्रणी तकनीकी संस्थानों में से एक बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। तकनीकी शिक्षा ने उनके व्यक्तित्व में तार्किक सोच, विश्लेषणात्मक क्षमता और समस्या समाधान की दक्षता विकसित की। आगे उन्होंने आईआईएम, बेंगलुरु से एमबीए किया, जिसने उन्हें प्रबंधन, नेतृत्व और नीति निर्माण की आधुनिक समझ प्रदान की। ज्ञान के प्रति उनकी निरंतर जिज्ञासा यहीं नहीं रुकी और उन्होंने मैसेचुसेट्स के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से उच्च शिक्षा कार्यक्रम भी पूरा किया। यह उपलब्धि उनके वैश्विक दृष्टिकोण और सतत सीखने की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

प्रशासनिक सेवा में आने से पहले नितिन भदौरिया ने इनवेस्टमेंट बैंकर के रूप में भी कार्य किया। कॉर्पोरेट जगत का यह अनुभव उन्हें आर्थिक व्यवस्थाओं, वित्तीय प्रबंधन और रणनीतिक निर्णयों की व्यावहारिक समझ प्रदान करता है। किंतु उन्होंने निजी क्षेत्र की आकर्षक संभावनाओं से आगे बढ़कर जनसेवा का मार्ग चुना और वर्ष 2011 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तराखंड कैडर में शामिल हुए।

उत्तराखंड जैसे संवेदनशील और भौगोलिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण राज्य में कार्य करते हुए नितिन भदौरिया ने अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं। वर्ष 2013 में आई विनाशकारी केदारनाथ आपदा के दौरान उन्होंने ज्वाइंट रिलीफ कमिश्नर, केदारनाथ के रूप में कार्य किया। यह समय उत्तराखंड के इतिहास के सबसे कठिन दौरों में से एक था। प्राकृतिक आपदा ने हजारों लोगों के जीवन को प्रभावित किया था और प्रशासन के सामने राहत एवं पुनर्वास की बड़ी चुनौती थी। ऐसे कठिन समय में नितिन भदौरिया ने संवेदनशीलताए त्वरित निर्णय क्षमता और कुशल समन्वय का परिचय देते हुए राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संकट की घड़ी में उनका नेतृत्व और समर्पण प्रशासनिक सेवा के वास्तविक मानवीय स्वरूप को सामने लाता है।

इसके बाद उन्होंने रुड़की और मसूरी में ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट के रूप में कार्य किया। इन पदों पर रहते हुए उन्होंने प्रशासनिक पारदर्शिता, जनसुनवाई और विकास कार्यों को गति देने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए। नगर प्रशासन की जटिलताओं को समझते हुए उन्होंने देहरादून और हरिद्वार में म्युनिसिपल कमिश्नर के रूप में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। शहरी विकासए स्वच्छता, जल प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए उनके प्रयासों की व्यापक सराहना हुई।

नितिन भदौरिया के प्रशासनिक जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय अल्मोड़ा के जिलाधिकारी के रूप में उनका कार्यकाल रहा। लगभग साढ़े तीन वर्षों तक उन्होंने इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जिले में विकास और नवाचार की नई मिसालें स्थापित कीं। उनके नेतृत्व में अल्मोड़ा ने जल संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जिला अल्मोड़ा को लगातार तीन वर्षों तक विभिन्न श्रेणियों में नैशनल वॉटर अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। यह उपलब्धि केवल प्रशासनिक सफलता नहीं थी, बल्कि स्थानीय समुदायों की भागीदारी, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और सतत विकास की सोच का परिणाम थी।

अल्मोड़ा में उनके कार्यकाल के दौरान जल संरक्षण, पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन, ग्रामीण विकास और सामुदायिक सहभागिता पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि यदि प्रशासन जनता के साथ मिलकर कार्य करे तो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े परिवर्तन संभव हैं। उनके नेतृत्व में अल्मोड़ा ने कई अन्य राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सम्मान भी प्राप्त किए, जिसने जिले को विकास के मॉडल के रूप में स्थापित किया।

नितिन भदौरिया केवल एक कुशल प्रशासक ही नहीं, बल्कि एक संवेदनशील विचारक और लेखक भी हैं। अल्मोड़ा की संस्कृति, प्रकृति, इतिहास और सामाजिक जीवन पर कई पुस्तकों की रचना की है। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनके अनुभव और एक लेखक के रूप में उनकी संवेदनशील दृष्टि इन कृतियों को विशेष बनाती है। यह उनकी बहुआयामी प्रतिभा का प्रमाण है कि वे प्रशासनिक व्यस्तताओं के बीच भी साहित्य और ज्ञान सृजन के लिए समय निकालते हैं।

उन्होंने उत्तराखंड सरकार में अतिरिक्त सचिव एवं निदेशक, शहरी विकास तथा मिशन डायरेक्टर, जल जीवन मिशन जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया। इन भूमिकाओं में उन्होंने राज्य के शहरी विकास, पेयजल आपूर्ति और आधारभूत संरचना को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वच्छ पेयजल पहुँचाने की दिशा में उनके प्रयास उल्लेखनीय रहे। उनकी कार्यशैली में तकनीक, डेटा आधारित नीति निर्माण और परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

नितिन भदौरिया की पहचान एक ऐसे अधिकारी के रूप में है, जो तकनीकी दक्षता, मानवीय संवेदनशीलता और दूरदर्शी नेतृत्व का अद्भुत संगम प्रस्तुत करते हैं। वे प्रशासन को केवल आदेश और नियंत्रण का माध्यम नहीं मानते, बल्कि इसे समाज के साथ साझेदारी में विकास का उपकरण मानते हैं। उनकी कार्यशैली में पारदर्शिता, नवाचार, टीमवर्क और जनभागीदारी को विशेष महत्व प्राप्त है।

आज जब प्रशासनिक व्यवस्था के सामने नई चुनौतियाँ लगातार उभर रही हैं, तब नितिन भदौरिया जैसे अधिकारी यह विश्वास जगाते हैं कि समर्पित नेतृत्व, आधुनिक सोच और जनसेवा की भावना से सकारात्मक परिवर्तन संभव है। उनकी उपलब्धियाँ केवल व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं हैं, बल्कि यह उस प्रशासनिक आदर्श का उदाहरण हैं जिसमें विकास, संवेदनशीलता और सुशासन साथ.साथ चलते हैं।

क्षमतावान

विकास को नई दिशा देने वाला प्रशासनिक नेतृत्व

अजय कुमार

(गुरुग्राम, वर्तमान में सीएमओ)

वर्ष 2013 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अजय कुमार मूल रूप से उना, हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं, और तकनीकी व प्रबंधन पृष्ठभूमि से आते हैं। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग और आईआईएम कोजिकोड से प्रबंधन शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने प्रशासनिक सेवा को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। यही कारण है कि उनकी कार्यशैली में आधुनिक प्रबंधन, तकनीकी सोच और जमीनी प्रशासन का संतुलित समावेश दिखाई देता है।

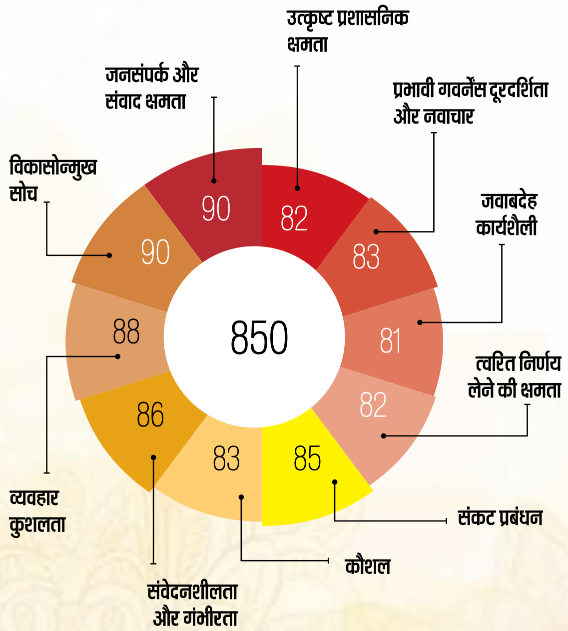

फेम इंडिया-एशिया पोस्ट के 'सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026' के वार्षिक सर्वे में प्रशासनिक अधिकारी अजय कुमार को 'क्षमतावान' श्रेणी में प्रमुख पाया गया है।

गुरुग्राम जैसे तेजी से विकसित होते जिले में प्रशासनिक नेतृत्व केवल सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं होता, बल्कि नागरिकों, उद्योगों, शहरी निकायों और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। अजय कुमार ने अपने कार्यकाल में इसी समन्वित प्रशासनिक मॉडल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। हाल ही में उनका तबादला मुख्यमंत्री कार्यालय में हो गया है और वह एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। आज जब शहरी प्रशासन देश के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुका है, तब अजय कुमार जैसे अधिकारी यह संदेश देते हैं कि प्रभावी प्रशासन केवल कठोर आदेशों से नहीं, बल्कि दूरदर्शी सोच, जनसंवाद और सक्रिय कार्यसंस्कृति से स्थापित होता है।

हरियाणा का गुरुग्राम आज केवल एक शहर नहीं, बल्कि आधुनिक भारत की आर्थिक शक्ति, कॉर्पोरेट संस्कृति और तीव्र शहरी विकास का प्रतीक बन चुका है। ऐसे समय में उपायुक्त के रूप में अजय कुमार ने गुरुग्राम के विकास को अधिक व्यवस्थित, उत्तरदायी और जनकेंद्रित दिशा देने का प्रयास किया है।

गुरुग्राम में कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से यह संकेत दिया कि उनका ध्यान केवल पारंपरिक प्रशासन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शहर की वास्तविक समस्याओं के स्थायी समाधान पर केंद्रित होगा। गुरुग्राम जैसे शहर में विकास का अर्थ केवल ऊँची इमारतें और कॉर्पोरेट कार्यालय नहीं, बल्कि सुगम यातायात, सुरक्षित सड़कें, बेहतर जल निकासी, स्वच्छ वातावरण और नागरिक सुविधाओं का विस्तार भी है। अजय कुमार ने अपने कार्यकाल में इसी व्यापक विकास दृष्टि को आगे बढ़ाने का प्रयास किया।

गुरुग्राम लंबे समय से ट्रैफिक जाम की समस्या से भी जूझता रहा है। अजय कुमार ने ट्रैफिक प्रबंधन को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न विभागों—यातायात पुलिस, नगर निगम और शहरी विकास एजेंसियों—के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर बल दिया।

मुख्य सड़कों के सुधार, ट्रैफिक बॉटलनेक की पहचान, सड़क सुरक्षा उपायों और यातायात व्यवस्था को अधिक वैज्ञानिक बनाने की दिशा में प्रशासनिक सक्रियता बढ़ाई गई। उनका मानना रहा कि गुरुग्राम जैसे आधुनिक शहर की पहचान केवल आर्थिक गतिविधियों से नहीं, बल्कि व्यवस्थित नागरिक सुविधाओं से भी होती है।

अजय कुमार के कार्यकाल में गुरुग्राम की आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में कई प्रयास किए गए। सड़कों की मरम्मत, जल निकासी व्यवस्था में सुधार, सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार और नागरिक सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर प्रशासन ने विशेष ध्यान दिया।

विशेष रूप से मानसून के दौरान जलभराव की समस्या को कम करने के लिए विभिन्न विभागों के साथ समन्वित कार्ययोजना पर बल दिया गया। गुरुग्राम में हर वर्ष बारिश के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याएँ राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनती रही हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा ड्रेनेज सिस्टम, पंपिंग व्यवस्था और निगरानी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयास महत्वपूर्ण माने गए।

अजय कुमार ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में भी कार्य किया। डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन माध्यम से अधिक सुलभ बनाने का प्रयास किया गया। शिकायत निवारण तंत्र को सक्रिय करने और नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान पर विशेष जोर दिया गया।

गुरुग्राम जैसे तकनीकी रूप से उन्नत शहर में प्रशासन का डिजिटलीकरण अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इसी सोच के साथ प्रशासन ने नागरिक सेवाओं को अधिक सरल और प्रभावी बनाने की दिशा में पहल की। इससे लोगों का समय बचा और प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ी।

तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच पर्यावरण संरक्षण गुरुग्राम की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। अजय कुमार ने विकास और पर्यावरणीय संतुलन के बीच सामंजस्य बनाए रखने पर बल दिया। हरित क्षेत्र बढ़ाने, स्वच्छता अभियानों को गति देने और सार्वजनिक स्थानों की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में प्रशासनिक प्रयास किए गए।

स्वच्छता और कचरा प्रबंधन से जुड़े विषयों पर जनभागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। उनका दृष्टिकोण यह रहा कि किसी भी शहर का विकास केवल निर्माण कार्यों से नहीं, बल्कि उसकी स्वच्छता, हरित वातावरण और नागरिक अनुशासन से भी मापा जाना चाहिए।

अजय कुमार की कार्यशैली का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उनकी संवाद क्षमता और जनसंपर्क रहा है। वे उन अधिकारियों में माने जाते हैं जो केवल कार्यालयों तक सीमित न रहकर फील्ड विज़िट और प्रत्यक्ष निरीक्षण को प्राथमिकता देते हैं। आम नागरिकों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान खोजने के लिए प्रशासनिक तंत्र को अधिक सक्रिय बनाने का प्रयास उनके कार्यकाल में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

गुरुग्राम जैसे जिले में, जहाँ ग्रामीण क्षेत्र और आधुनिक कॉर्पोरेट संस्कृति दोनों साथ-साथ मौजूद हैं, प्रशासनिक संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता। लेकिन उन्होंने विकास को केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रखकर ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं और सुविधाओं पर भी ध्यान देने की कोशिश की।

उनकी प्रशासनिक शैली में अनुशासन और पारदर्शिता का विशेष महत्व दिखाई देता है। उन्होंने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को निष्पक्ष और जवाबदेह बनाए रखने पर जोर दिया। सरकारी तंत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करने और कार्यसंस्कृति को अधिक परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में उनके प्रयास उल्लेखनीय रहे। उनकी कार्यशैली में संवेदनशीलता और दृढ़ता का संतुलन दिखाई देता है। वे विकास कार्यों को केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं मानते, बल्कि आम नागरिकों के जीवन में वास्तविक सुधार को प्राथमिकता देते हैं। यही कारण है कि वे एक शांत, व्यवहारकुशल और परिणामोन्मुख अधिकारी के रूप में पहचाने जाते हैं।

अजय कुमार का कार्यकाल इस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि उन्होंने गुरुग्राम के विकास को केवल भौतिक निर्माण तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सुशासन, प्रशासनिक पारदर्शिता और जनसुविधाओं को भी समान महत्व दिया। उनका प्रयास रहा कि गुरुग्राम केवल आर्थिक राजधानी के रूप में ही नहीं, बल्कि बेहतर शहरी प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं वाले शहर के रूप में भी अपनी पहचान बनाए।

विलक्षण

नई सोच वाले जन-केंद्रित प्रशासन का प्रेरक चेहरा

मंजुनाथ भाजंत्री

(रांची)

झारखंड प्रशासनिक व्यवस्था में यदि किसी अधिकारी का नाम जनविश्वास, पारदर्शिता और संवेदनशील शासन के प्रतीक के रूप में लिया जाता हैए तो उनमें मंजुनाथ भाजंत्री का नाम अत्यंत सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ शामिल होता है। वर्ष 2011 बैच के झारखंड कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी मंजुनाथ भाजंत्री वर्तमान में रांची जिले के उपायुक्त एवं जिलाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

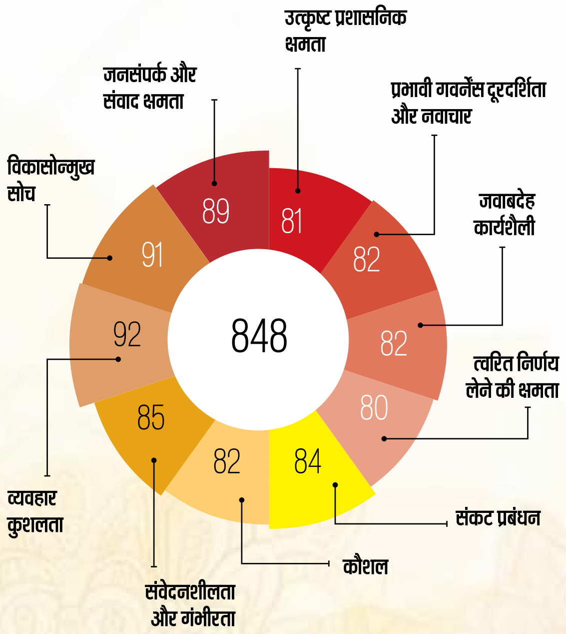

फेम इंडिया-एशिया पोस्ट के 'सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026' के वार्षिक सर्वे में प्रशासनिक अधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री को 'विलक्षण' श्रेणी में प्रमुख पाया गया है।

पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) में उपायुक्त रहते हुए उन्होंने स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए 'विश्वकर्मा पॉइंट' जैसी अभिनव पहल शुरू की। इस विशेष केंद्र का उद्देश्य स्थानीय शिल्पकारों को सम्मानजनक बाजार उपलब्ध कराना था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बोड़ाम प्रखंड के अंधारझोर गांव के दौरे के दौरान उन्होंने देखा कि पारंपरिक वाद्य यंत्र बनाने वाले कारीगर संसाधनों और बाजार के अभाव में संघर्ष कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कारीगरों की सोसायटी का गठन करवाया, बैंक खाते खुलवा, और सरकारी सहायता सुनिश्चित करवाई। यह कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पारंपरिक कला को नई ऊर्जा देने वाला माना गया।

कर्नाटक के बेलगाम (बेलागावी) से आने वाले भाजंत्री ने आईआईटी, मुंबई से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बी.टेक. की शिक्षा प्राप्त की। वे उन अधिकारियों में शामिल हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी और प्रशासन का प्रभावी समन्वय स्थापित कर शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शीए उत्तरदायी और जनोन्मुख बनाया। एक दशक से अधिक के प्रशासनिक अनुभव में उन्होंने झारखंड के कई जिलों में कार्य करते हुए विकास और सुशासन की नई मिसालें कायम की हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, आजीविका संवर्धन, प्रशासनिक सुधार और संकट प्रबंधन जैसे अनेक क्षेत्रों में उनके कार्य उल्लेखनीय माने जाते हैं। उनकी कार्यशैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे प्रशासन को केवल सरकारी प्रक्रिया नहीं, बल्कि समाज परिवर्तन का माध्यम मानते हैं।

मंजुनाथ भाजंत्री 'फील्ड एडमिनिस्ट्रेशन' में गहरी आस्था रखते हैं। वे कार्यालयों तक सीमित रहने वाले अधिकारी नहीं, बल्कि गांवों, दूरस्थ इलाकों और आम लोगों के बीच जाकर समस्याओं को समझने वाले प्रशासक हैं। यही कारण है कि उनकी योजनाएं और पहलें सीधे जनता के जीवन को प्रभावित करती हैं।

देवघर जिले में उपायुक्त के रूप में उनका कार्यकाल उनकी प्रशासनिक क्षमता और संकट प्रबंधन कौशल का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। देवघर रोपवे हादसा झारखंड के सबसे गंभीर आपदा घटनाक्रमों में से एक था। इस दौरान मंजुनाथ भाजंत्री ने भारतीय वायुसेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन के साथ अभूतपूर्व समन्वय स्थापित कर बचाव अभियान का सफल संचालन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वे लगातार घटनास्थल पर मौजूद रहे और हर स्तर पर राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी करते रहे। उनकी इस भूमिका की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई।

वर्तमान में रांची के उपायुक्त के रूप में मंजुनाथ भाजंत्री ने प्रशासन को अधिक पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 'अबुआ साथी' जन शिकायत निवारण प्रणाली उनकी सबसे चर्चित पहलों में से एक है। इस व्यवस्था के माध्यम से लोग व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस, पोर्टल और हस्तलिखित आवेदन के जरिए सीधे उपायुक्त कार्यालय तक अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए जिला स्तर से लेकर प्रखंड और पंचायत स्तर तक अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस पहल को 'डिजिटल और संवेदनशील प्रशासन का उत्कृष्ट मॉडल' बताया गया है।

उन्होंने जनता दरबार की व्यवस्था को भी अत्यंत प्रभावी बनाया। प्रत्येक सोमवार वे स्वयं आम नागरिकों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और संबंधित अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश देते हैं। इस प्रक्रिया में जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मॉडल को प्रखंड और अंचल स्तर तक भी विस्तारित किया, जहां प्रत्येक मंगलवार को स्थानीय जनता दरबार आयोजित किए जाते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला मुख्यालय तक आने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

भूमि विवादों के समाधान के क्षेत्र में भी उनका कार्य अत्यंत उल्लेखनीय रहा है। झारखंड में छोटे भूमि विवाद वर्षों तक लंबित रहते हैं और कई बार सामाजिक तनाव का कारण बनते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने 10 डिसमिल तक की जमीन से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान का विशेष अभियान चलाया। अधिकारियों ने लगातार कार्य करते हुए बड़ी संख्या में लंबित मामलों का निपटारा किया। मीडिया रिपोर्ट्स में इसे आम लोगों को राहत देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया गया।

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में 'मइया स्वावलंबन' अभियान उनकी दूरदर्शी सोच का उदाहरण है। इस पहल के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को पोल्ट्री, बकरी पालन, बतख पालन और छोटे उद्योगों से जोड़कर स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया। हजारों महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह अभियान अत्यंत सफल माना गया।

युवाओं के लिए शुरू किया गया '100 एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम' भी उनकी अभिनव सोच को दर्शाता है। इस कार्यक्रम के तहत चयनित युवाओं को प्रशिक्षण, मेंटरशिप, निवेशकों से संपर्क और सीड फंडिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। विशेष रूप से महिलाओं और वंचित वर्गों को प्राथमिकता देकर यह कार्यक्रम समावेशी विकास का प्रभावी उदाहरण बनकर उभरा है।

मंजुनाथ भाजंत्री प्रशासनिक कर्मचारियों के नैतिक और मानवीय विकास पर भी विशेष जोर देते हैं। उन्होंने राजस्व और अंचल कर्मियों के लिए क्षमता विकास कार्यशालाओं की शुरुआत की, जिनमें कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण के साथ साथ संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

उनकी कार्यशैली की सबसे बड़ी पहचान है - सीधा संवाद, त्वरित निर्णय और पारदर्शिता। वे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनता से लगातार जुड़े रहते हैं और लोगों की समस्याओं पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हैं। यही कारण है कि आम नागरिकों के बीच उनकी छवि एक सुलभ, संवेदनशील और कर्मठ अधिकारी की बनी हुई है।

मंजुनाथ भाजंत्री आज उन चुनिंदा प्रशासनिक अधिकारियों में गिने जाते हैं जिन्होंने यह साबित किया है कि यदि प्रशासनिक इच्छाशक्ति मजबूत हो और जनसेवा के प्रति समर्पण सच्चा हो, तो शासन व्यवस्था समाज में वास्तविक और सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। उनकी प्रशासनिक यात्रा केवल सफलता की कहानी नहीं, बल्कि संवेदनशील नेतृत्व, नवाचार और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाले प्रशासन की प्रेरक गाथा है।

प्रेरक

सुशासन, विकास और जवाबदेही का सशक्त चेहरा

अविनाश सिंह (बरेली)

बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ऐसे ही ऊर्जावान, कर्मठ और परिणामोन्मुखी प्रशासक हैं, जिन्होंने अपने प्रशासनिक जीवन में विकास, सुशासन और जनसेवा को नई दिशा देने का कार्य किया है। उनकी पहचान एक ऐसे अधिकारी के रूप में बनी है, जो प्रशासनिक कठोरता और मानवीय संवेदनशीलता के बीच अद्भुत संतुलन बनाए रखते हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मूल निवासी अविनाश सिंह शिक्षा और संस्कारों से समृद्ध पृष्ठभूमि से आते हैं। छात्र जीवन से ही वे अनुशासित, मेहनती और नेतृत्व क्षमता से संपन्न रहे।

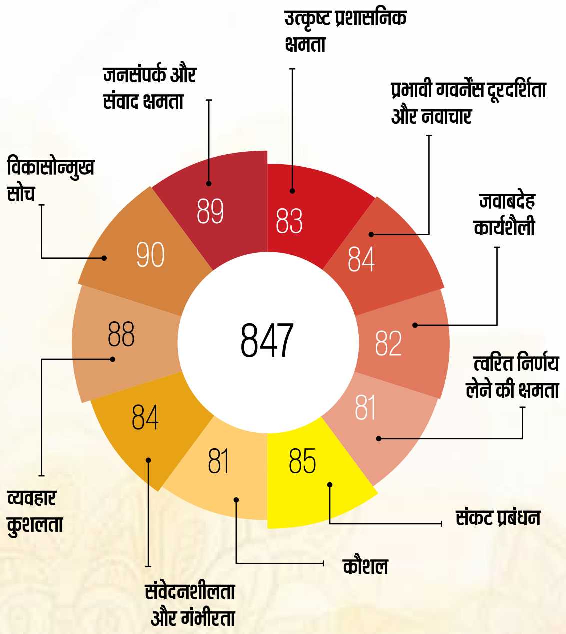

फेम इंडिया-एशिया पोस्ट के 'सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026' के वार्षिक सर्वे में प्रशासनिक अधिकारी अविनाश सिंह को 'प्रेरक' श्रेणी में प्रमुख पाया गया है।

वर्ष 2023 में उन्हें पहली बार स्वतंत्र प्रभार के रूप में अंबेडकरनगर जिले का जिलाधिकारी बनाया गया। यह उनके प्रशासनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। अंबेडकरनगर में उन्होंने प्रशासनिक पारदर्शिता, जनसुनवाई व्यवस्था और विकास योजनाओं के प्रभावी संचालन पर विशेष ध्यान दिया। किसानों की समस्याओं के समाधान, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किए। महिला सशक्तिकरण, सामाजिक कल्याण और शिक्षा से जुड़े अभियानों को भी उन्होंने प्राथमिकता दी। उनके नेतृत्व में प्रशासन अधिक सक्रिय और जनोन्मुख दिखाई दिया।

अविनाश सिंह ने अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के बल पर प्रशासनिक सेवा में स्थान बनाया और उत्तर प्रदेश कैडर के वर्ष 2014 बैच के आईएएस अधिकारी बने। प्रशासनिक सेवा में आने के बाद उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करते हुए शासन-प्रशासन की जमीनी चुनौतियों को निकट से समझा। यही अनुभव आगे चलकर उनकी प्रशासनिक शैली की सबसे बड़ी शक्ति बना।

अपने प्रशासनिक करियर में अविनाश सिंह ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाईं। वे गोरखपुर में नगर आयुक्त के पद पर तैनात रहे, जहाँ उन्होंने शहरी विकास, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। नगर प्रशासन की जटिलताओं को समझते हुए उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनसुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया। इसके बाद वे मिर्जापुर में मुख्य विकास अधिकारी के रूप में भी कार्यरत रहे। इस दौरान ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण, पंचायत व्यवस्था और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को गति देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही।

अप्रैल 2025 में अविनाश सिंह ने बरेली के जिलाधिकारी एवं कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला। बरेली जैसे बड़े और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले की जिम्मेदारी संभालना किसी भी अधिकारी के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन उन्होंने अपने अनुभव, नेतृत्व क्षमता और त्वरित निर्णय लेने की योग्यता से इस जिम्मेदारी को प्रभावी ढंग से निभाया। उनके नेतृत्व में बरेली में विकास कार्यों को नई गति मिली और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनी।

जिलाधिकारी बरेली के रूप में अविनाश सिंह ने आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया। सड़क, स्वच्छता, पेयजल और शहरी विकास से जुड़ी कई योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया गया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि विकास केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहे, बल्कि ग्रामीण इलाकों तक भी समान रूप से पहुँचे। गाँवों में सड़क, जलापूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की गई।

स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी उनके प्रयास उल्लेखनीय रहे। जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने, चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने और जनस्वास्थ्य अभियानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उन्होंने निरंतर समीक्षा की। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में उनके प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव दिखाई दिया। वे मानते हैं कि किसी भी जिले के समग्र विकास के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ अत्यंत आवश्यक हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में भी अविनाश सिंह ने कई प्रभावी पहल कीं। विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने, छात्र उपस्थिति बढ़ाने और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर विशेष ध्यान दिया गया। उनका मानना रहा कि शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और जागरूकता की सबसे मजबूत नींव है। इसी सोच के साथ उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में कार्य किया।

बरेली में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए। निवेशकों और उद्यमियों के साथ संवाद स्थापित कर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रयास किया गया। इससे जिले में आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिली और रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। उनका दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि वे विकास को केवल सरकारी परियोजनाओं तक सीमित नहीं मानते, बल्कि उसे समाज और अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम समझते हैं।

कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी उनका नेतृत्व प्रभावशाली रहा। प्रशासन और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए उन्होंने शांति और सुरक्षा का वातावरण बनाए रखने का प्रयास किया। संवेदनशील परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेने और प्रभावी प्रबंधन की उनकी क्षमता ने उन्हें एक मजबूत प्रशासक के रूप में स्थापित किया। उनका मानना है कि सुरक्षित वातावरण किसी भी जिले के विकास की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

अविनाश सिंह की कार्यशैली का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जनता से उनका सीधा संवाद है। वे नियमित जनसुनवाई, फील्ड विजिट और निरीक्षणों के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने में विश्वास रखते हैं। उनकी यह संवेदनशीलता उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाती है। वे प्रशासन को केवल आदेश देने वाली व्यवस्था नहीं, बल्कि जनता की सेवा और विश्वास का माध्यम मानते हैं।

तकनीक और नवाचार को प्रशासनिक कार्यशैली में शामिल करना भी उनकी विशेषताओं में से एक है। डिजिटल मॉनिटरिंग, ऑनलाइन शिकायत निवारण और डेटा आधारित समीक्षा के माध्यम से उन्होंने प्रशासनिक कार्यों को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने का प्रयास किया। उनकी आधुनिक सोच और जमीनी अनुभव का संतुलन उन्हें समकालीन प्रशासनिक अधिकारियों में विशिष्ट बनाता है।

आज अविनाश सिंह उन प्रशासनिक अधिकारियों में गिने जाते हैं, जिन्होंने अपने कार्यों से यह साबित किया है कि समर्पित नेतृत्व, संवेदनशील प्रशासन और विकासोन्मुख सोच से किसी भी जिले की तस्वीर बदली जा सकती है। अंबेडकरनगर और बरेली में उनके कार्य केवल प्रशासनिक उपलब्धियाँ नहीं, बल्कि सुशासन और जनसेवा की प्रेरक मिसाल हैं। उनका प्रशासनिक जीवन यह संदेश देता है कि सच्चा नेतृत्व वही है, जो विकास के साथ-साथ जनता के विश्वास और उम्मीदों को भी मजबूत करे।

लगनशील

जनसरोकार, नवाचार और परिणाम आधारित प्रशासन की पर्याय

विशाखा यादव

(कुरुंग कुमे, वर्तमान में दिल्ली)

विशाखा यादव ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बी.टेक. किया। इसके बाद प्रशासनिक सेवा में आने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और प्रशिक्षण के दौरान जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की पढ़ाई की। इतना ही नहीं, उन्होंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली से कानून की पढ़ाई भी की। उनकी यह बहुआयामी शैक्षणिक पृष्ठभूमि प्रशासनिक निर्णयों में गहराई और आधुनिक सोच को दर्शाती है।

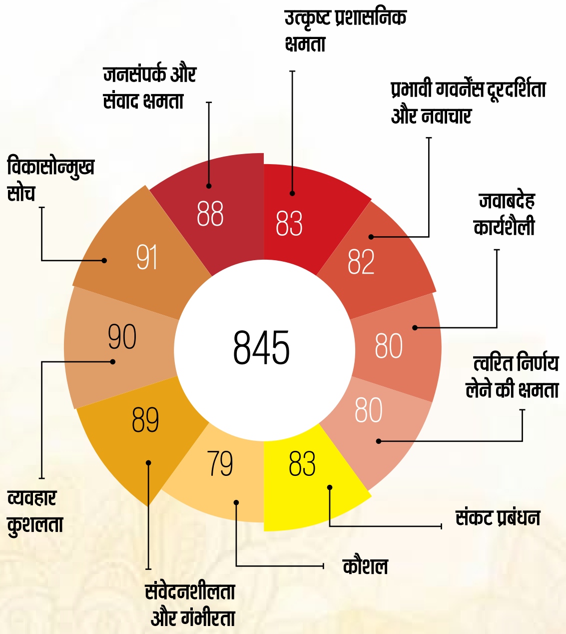

फेम इंडिया-एशिया पोस्ट के 'सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026' के वार्षिक सर्वे में प्रशासनिक अधिकारी विशाखा यादव को 'लगनशील' श्रेणी में प्रमुख पाया गया है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में हर वर्ष अनेक प्रतिभाशाली युवा अधिकारी शामिल होते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी अपनी कार्यशैली, दृष्टिकोण और नवाचारों के कारण अलग पहचान बना लेते हैं। विशाखा यादव ऐसी ही युवा और प्रेरणादायी आईएएस अधिकारियों में गिनी जाती हैं। तकनीकी शिक्षा, प्रशासनिक दक्षता और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की सोच ने उन्हें देश की उभरती हुई प्रशासनिक अधिकारियों की सूची में विशेष स्थान दिलाया है।

वर्ष 2020 बैच की आईएएस अधिकारी विशाखा यादव एजीएमयूटी कैडर से संबंधित हैं। उन्होंने वर्ष 2019 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 6वीं रैंक हासिल की थी। यह उपलब्धि अपने आप में उनकी प्रतिभा, अनुशासन और कठिन परिश्रम का प्रमाण है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी सफलता की कहानी देशभर के युवाओं, विशेषकर इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े छात्रों के लिए प्रेरणा मानी जाती है।

प्रशासनिक सेवा में आने के बाद उन्होंने दिल्ली और अरुणाचल प्रदेश जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में काम किया। उन्होंने नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली में असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में अपनी सेवाएं दीं। इसके बाद भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और ग्रामीण विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर काम किया।

उनके प्रशासनिक करियर का सबसे महत्वपूर्ण चरण अरुणाचल प्रदेश में रहा, जहां उन्होंने सीमावर्ती जिलों में कार्य करते हुए कई नवाचारी पहल शुरू कीं। उन्होंने तिराप जिले में अतिरिक्त उपायुक्त के रूप में काम किया, जो भारत-म्यांमार सीमा से जुड़ा संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। यह ज़िला भारत के उन क्षेत्रों में शामिल रहा है जहाँ सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम यानी एएफएसपीए लागू किया गया है। बाद में वे कुरुंग कुमेय जिले की डिप्टी कमिश्नर बनीं, जो भारत-चीन सीमा के निकट स्थित है। इन दुर्गम क्षेत्रों में काम करना किसी भी अधिकारी के लिए बड़ी चुनौती माना जाता है, लेकिन विशाखा यादव ने इन चुनौतियों को अवसर में बदलने का प्रयास किया।

अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले में डिप्टी कमिश्नर के रूप में उनका कार्यकाल विशेष रूप से चर्चा में रहा। वे नवगठित होलोंगी एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की पहली सीईओ बनीं। मीडिया रिपोर्ट्स में उल्लेख किया गया कि उन्होंने प्रशासनिक कार्यों को केवल सरकारी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रखा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में जमीनी बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित किया।

उनकी सबसे चर्चित पहल 'प्रोजेक्ट डिजी-कक्षा' रही, जिसके लिए उन्हें वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट प्रशासन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार जिला नवाचार श्रेणी में प्रदान किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह परियोजना भारत-चीन सीमा से लगे गांवों में शिक्षा और प्रशासन को डिजिटल माध्यम से मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम थी।

'डिजी-कक्षा' के तहत दूरदराज के सीमावर्ती गांवों में तकनीक आधारित स्मार्ट कक्षाएं विकसित की गईं। इन क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच सीमित थी और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी भी बड़ी समस्या थी। विशाखा यादव ने डिजिटल शिक्षा मॉडल तैयार कर बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया। कई राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने इसे "सीमावर्ती भारत में शिक्षा क्रांति" की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताया।

विशाखा यादव की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि "प्रोजेक्ट मातृभूमि" रही। अक्टूबर 2022 में उन्होंने इस परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुति भी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह परियोजना डिजिटल भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन से संबंधित थी, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और ग्रामीण लोगों को सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराना था।

विशाखा यादव ने बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया। पापुम पारे जिले में उन्होंने FLN सेंटर की स्थापना करवाई, जो नई शिक्षा नीति 2020 के तहत प्री-प्राइमरी बच्चों के लिए आधारभूत साक्षरता और गणितीय क्षमता विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना गया। यह अरुणाचल प्रदेश का पहला अभिनव प्रयास था।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने "मिशन फॉक्सटेल मिलेट्स" शुरू किया। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय किसानों को मोटे अनाज की खेती से जोड़ना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना था।

विशाखा यादव की कार्यशैली की सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जाती है कि वे प्रशासन को केवल सरकारी आदेशों तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि समाज के साथ संवाद स्थापित करने में विश्वास रखती हैं। वे नियमित रूप से गांवों का दौरा करती हैं, स्थानीय लोगों से बातचीत करती हैं और समस्याओं को जमीनी स्तर पर समझने का प्रयास करती हैं।

वर्तमान में वे दिल्ली के आउटर नॉर्थ जिले में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत हैं। प्रशासनिक हलकों में माना जाता है कि सीमावर्ती और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में कार्य करने का उनका अनुभव दिल्ली जैसे बड़े प्रशासनिक क्षेत्र में भी नई ऊर्जा और नवाचार लेकर आएगा।

विशाखा यादव आज उन युवा अधिकारियों में गिनी जाती हैं जिन्होंने यह साबित किया है कि आधुनिक शिक्षा, तकनीकी सोच और संवेदनशील प्रशासन मिलकर समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। उनकी सफलता और कार्यशैली न केवल युवा प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रेरणा है, बल्कि उन लाखों युवाओं के लिए भी उम्मीद का संदेश है जो देशसेवा का सपना देखते हैं।

चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया। वर्ष 2024 में उन्हें अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा 'बेस्ट इलेक्ट्रोरल रोल एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके नेतृत्व में लोकसभा और विधानसभा चुनाव पहली बार राज्य में पूरी तरह शांतिपूर्ण और शून्य हिंसा के साथ संपन्न हुए। सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में यह उपलब्धि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई। स्वास्थ्य और सामाजिक विकास के क्षेत्र में भी उनकी कई पहलें चर्चा में रहीं। उन्होंने 'आरोग्य धाम' नामक स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर विकसित कराया, जहां योग और आयुष पद्धति के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा दिया गया।

उम्दा

नवाचार, जल-संरक्षण और जन-केंद्रित शासन के प्रणेता

मयूर दीक्षित (हरिद्वार)

जिला मजिस्ट्रेट के रूप में उनकी प्रगति उल्लेखनीय रही। रुद्रप्रयाग में जिला प्रशासन संभालते हुए उन्होंने स्थानीय उद्योग कार्यशालाओं का आयोजन कर एमएसएमई विकास को गति दी। उत्तरकाशी में उन्होंने मिशन इंद्रावती शुरू कर जल स्रोतों के पुनरुत्थान, पर्यावरण संरक्षण और सतत जल प्रबंधन का अनूठा मॉडल प्रस्तुत किया। जुलाई 2023 से जून 2025 तक टिहरी गढ़वाल के जिलाधिकारी के रूप में उन्होंने अतिरिक्त प्रभार के रूप में टिहरी बांध पुनर्वास परियोजना के निदेशक तथा जिला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का कार्य भी संभाला। यहां उन्होंने विकास पहलों, शिक्षा सर्वेक्षणों (स्कूल रेसी सिस्टम) और समग्र जिला प्रगति पर विशेष ध्यान दिया।

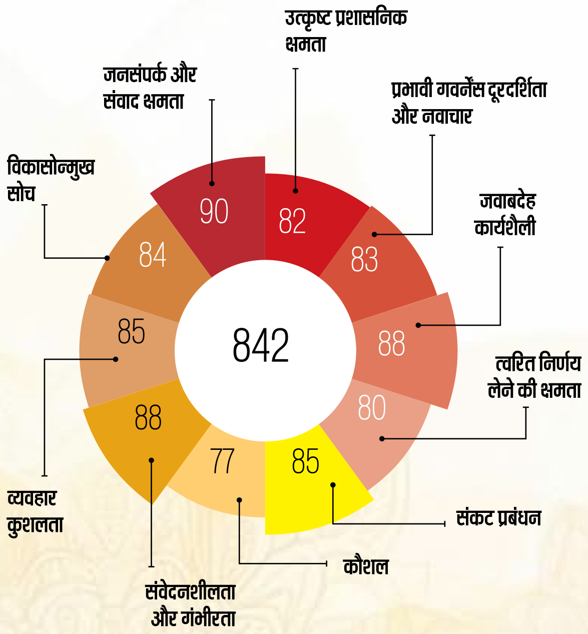

फेम इंडिया-एशिया पोस्ट के 'सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026' के वार्षिक सर्वे में प्रशासनिक अधिकारी मयूर दीक्षित को 'उम्दा' श्रेणी में प्रमुख पाया गया है।

मयूर दीक्षित की उपलब्धियां राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पुरस्कारों से सजी हुई हैं। डिजिटल इंडिया अवॉर्ड्स 2022-2023 स्टार्टअप्स के साथ सहयोग कर ई-गवर्नेंस और तकनीकी-सक्षम जन-सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पुरस्कार 2019 और राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 (भारत सरकार) उनके जल संरक्षण और ग्रामीण विकास कार्यों को समर्पित हैं। उत्तराखंड सरकार से मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं अच्छे शासन पुरस्कार (2019 तथा 2020) प्राप्त कर उन्होंने जिला प्रदर्शन में नई मिसाल कायम की। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) से 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले जिले का पुरस्कार मिला। शिक्षा सर्वेक्षण के लिए विकसित स्कूल रेसी सिस्टम जैसी नवाचारी पहल ने बाल अधिकारों और शिक्षा क्षेत्र को मजबूत किया।

उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर स्थित हरिद्वार जिले के वर्तमान जिला मजिस्ट्रेट श्री मयूर दीक्षित, आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन उज्ज्वल सितारों में से एक हैं जिनकी यात्रा बौद्धिक उत्कृष्टता, नवाचारी सोच और अटूट जन-सेवा भावना का अद्भुत संगम है। 2013 बैच के उत्तराखंड कैडर के इस अधिकारी ने आईआईटी कानपुर, आईआईएम बेंगलुरु और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त कर प्रशासनिक सेवा को चुना। आईएएस परीक्षा में प्रथम प्रयास में अखिल भारतीय रैंक 11 हासिल करने वाले श्री दीक्षित ने निजी क्षेत्र की आकर्षक संभावनाओं को त्यागकर राष्ट्र-निर्माण का मार्ग अपनाया। जून 2025 से हरिद्वार के जिलाधिकारी पद पर कार्यरत श्री दीक्षित ने अपने एक दशक से अधिक के अनुभव में ग्रामीण विकास, जल संरक्षण, डिजिटल नवाचार, संकट प्रबंधन और अच्छे शासन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनकी कार्यशैली में विश्लेषणात्मक दृष्टि, रणनीतिक सोच और टीम को प्रेरित करने की क्षमता का अनुपम मेल है। वे साबित करते हैं कि सच्चा प्रशासक वही है जो चुनौतियों को अवसर में बदलकर जनता की आवाज बने।

मयूर दीक्षित की शैक्षिक पृष्ठभूमि स्वयं में एक प्रेरणादायक कहानी है। उन्होंने आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक किया और अपनी स्ट्रीम में रैंक 1 प्राप्त की। इसके बाद आईआईएम बेंगलुरु से मैनेजमेंट में पीजीडीएम (एमबीए समकक्ष) तथा नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु से पर्यावरण कानून में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पूरा किया। विश्व बैंक, आईएमएफ, एडीबीआई और एमआईटी जैसी संस्थाओं से पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीपीपी, एनर्जी इकोनॉमिक्स और ग्लोबल पॉवर्टी जैसे क्षेत्रों में प्रमाण-पत्र प्राप्त किए। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की इस मजबूत नींव ने उन्हें जमीनी प्रशासन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और रणनीतिक योजना बनाने की क्षमता प्रदान की।

उनकी प्रशासनिक यात्रा ग्रामीण स्तर से शुरू होकर जिला और सचिवालय तक फैली हुई है। उप जिलाधिकारी (एसडीएम) के रूप में उन्होंने हरिद्वार और रुड़की में कानून-व्यवस्था, साम्प्रदायिक सद्भाव तथा आपात स्थितियों का सफल प्रबंधन किया। रुड़की में दंगे की स्थिति में कर्फ्यू लगाकर तथा समन्वय स्थापित कर उन्होंने जन-विश्वास बहाल किया। मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) के रूप में अल्मोड़ा और ऊधम सिंह नगर में ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचा निर्माण तथा आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारियां संभालीं। उन्होंने क्षेत्रीय निरीक्षण, हितधारकों के समन्वय और आपातकालीन प्रतिक्रिया में उत्कृष्टता दिखाई।

जून 2025 से हरिद्वार के जिलाधिकारी पद पर कार्यरत श्री दीक्षित ने अच्छे शासन, मानसून तैयारियों और कांवड़ मेला के सुचारू आयोजन को प्राथमिकता दी। हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थल पर लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और जन-सेवा सुनिश्चित करने में उनकी त्वरित निर्णय क्षमता सराहनीय रही। उन्होंने विभागीय समन्वय को मजबूत कर संसाधन-सीमित वातावरण में भी उत्कृष्ट परिणाम दिए।

उनके अन्य योगदानों में क्यूआर कोड आधारित कचरा ट्रैकिंग, टीम आधारित चुनाव प्रबंधन, उद्योग कार्यशालाएं तथा विकास वित्त, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और वित्तीय प्रबंधन पर फोकस शामिल है। संकट प्रबंधन में उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं, कानून-व्यवस्था और बड़े मेलों के आयोजन में अपनी क्षमता सिद्ध की।

श्री दीक्षित की कार्यशैली में कई विशेषताएं हैं। वे डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर प्रशासन को पारदर्शी और तेज बनाते हैं। जल संरक्षण को पर्यावरण संरक्षण से जोड़कर सतत विकास का मॉडल तैयार किया। शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन में नवाचार लाकर अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित की। उनकी टीम को प्रेरित करने की क्षमता और अंतर-विभागीय समन्वय ने जटिल चुनौतियों को सफलतापूर्वक हल किया। हरिद्वार में कांवड़ मेला और मानसून तैयारियों में उनकी योजनाएं जन-उन्मुखी और सुरक्षा-केंद्रित रही हैं।

उत्तराखंड जैसे भौगोलिक रूप से संवेदनशील राज्य में श्री दीक्षित ने जल स्रोतों के पुनरुत्थान, डिजिटल शिक्षा और आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता दी। उनकी पहलें "विकसित भारत 2047" के लक्ष्यों से सीधे जुड़ी हुई हैं। वे नियमित रूप से जन-संवाद कार्यक्रम आयोजित कर समस्याओं को सुनते और त्वरित समाधान देते हैं। उनकी यह शैली प्रशासन और जनता के बीच विश्वास का पुल बनाती है।

मयूर दीक्षित न केवल एक कुशल प्रशासक हैं, बल्कि एक संवेदनशील नेता भी हैं। उनका मानना है कि प्रशासन जनता की सेवा का माध्यम है। वे ईमानदारी, नवाचार और परिणामोन्मुखी नेतृत्व के प्रतीक हैं। आईआईटी टॉपर से लेकर एयर-11 तक की यात्रा और फिर हिमालयी जिलों में पुरस्कार विजेता कार्य — यह सब उनके अटूट समर्पण को दर्शाता है।

आज हरिद्वार जिला उनके नेतृत्व में अच्छे शासन, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक-केंद्रित विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री मयूर दीक्षित, आईएएस, प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में एक प्रेरणास्रोत हैं। उनकी कहानी मेहनत, बौद्धिक उत्कृष्टता और जन-सेवा की अनुपम गाथा है। वे साबित करते हैं कि सच्चा प्रशासक वही है जो लोगों की मदद करे, उनकी आवाज बने और राष्ट्र-निर्माण में अपना योगदान दे। भविष्य में भी वे और बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार हैं तथा युवा प्रशासकों के लिए आदर्श बने हुए हैं।

उर्जावान

उर्जावान

शांत नेतृत्व, जमीनी प्रशासन और सुशासन की सशक्त पहचान

अंजनी कुमार सिंह

(मैनपुरी, वर्तमान लखीमपुर खीरी)

अंजनी कुमार सिंह उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन अनुभवी अधिकारियों में गिने जाते हैं, जिन्होंने अपनी सादगी, शांत कार्यशैली और जनता से सीधे जुड़ाव के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनाने का प्रयास किया है। वर्तमान में वे लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी एवं कलेक्टर के रूप में कार्यरत हैं, लेकिन फेम इंडिया ने उन्हें मैनपुरी के योग्य जिलाधिकारी के तौर पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया है।

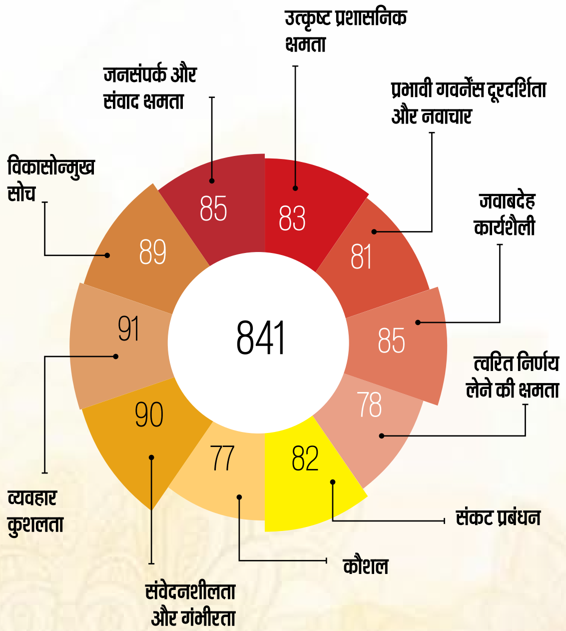

फेम इंडिया-एशिया पोस्ट के 'सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026' के वार्षिक सर्वे में प्रशासनिक अधिकारी अंजनी कुमार सिंह को 'उर्जावान' श्रेणी में प्रमुख पाया गया है।

अंजनी कुमार सिंह की कार्यशैली में कठोरता के साथ संवेदनशीलता का संतुलन दिखाई देता है। वे अधिकारियों को अनुशासन में रहने की सलाह देते हैं, लेकिन साथ ही जनता के प्रति मानवीय व्यवहार को भी उतना ही आवश्यक मानते हैं। यही कारण है कि उनकी छवि एक शांत, सुलझे हुए और जमीनी अधिकारी की बनी है। उनकी प्रशासनिक यात्रा यह दर्शाती है कि लंबे अनुभव, निरंतर फील्ड वर्क और जनता से सीधे संवाद के माध्यम से प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। उनकी सादगी, जमीनी समझ और जनकेंद्रित प्रशासनिक शैली उन्हें उत्तर प्रदेश के भरोसेमंद और अनुभवी अधिकारियों में विशिष्ट स्थान प्रदान करती है।

वर्ष 2014 बैच से संबद्ध अंजनी कुमार सिंह का जन्म 1 अगस्त 1972 को हुआ। इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से आने वाले अंजनी कुमार सिंह ने तकनीकी समझ और प्रशासनिक अनुभव का संतुलित उपयोग करते हुए उत्तर प्रदेश के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर उल्लेखनीय सेवाएँ दी हैं।

अंजनी कुमार सिंह की प्रशासनिक यात्रा राज्य प्रशासनिक सेवा से शुरू हुई। लंबे समय तक विभिन्न जिलों में जमीनी स्तर पर कार्य करने के बाद उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नत किया गया। 31 अगस्त 2020 को उन्हें औपचारिक रूप से आईएएस अवार्ड हुआ। उस समय वह गोरखपुर नगर निगम में नगर आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। उसके पहले वह लखनऊ में अपर जिलाधिकारी तथा बाराबंकी में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके थे। गोरखपुर में नगर आयुक्त रहते हुए उन्होंने शहरी प्रशासन, सफाई व्यवस्था और नगर प्रबंधन के क्षेत्र में प्रभावी कार्य किए।

गोरखपुर नगर निगम में कार्यकाल के दौरान उनकी पहचान एक ऐसे अधिकारी के रूप में बनी, जो कार्यालय तक सीमित रहने के बजाय फील्ड में जाकर वास्तविक स्थिति का आकलन करने में विश्वास रखते थे। आम नागरिकों के बीच उनकी कार्यशैली को सकारात्मक रूप से देखा गया।

उन्होंने बाराबंकी और बस्ती जैसे जिलों में जिला पंचायत से जुड़े दायित्व भी निभाए। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, पंचायत व्यवस्थाओं को मजबूत करने और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। ग्रामीण प्रशासन की चुनौतियों को निकट से समझने के कारण उनकी कार्यशैली में हमेशा जमीनी दृष्टिकोण दिखाई देता है।

2 मार्च 2021 को उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में निदेशक पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। यह उनके प्रशासनिक जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। मंडी परिषद जैसे बड़े और संवेदनशील विभाग में उन्होंने किसानों, व्यापारियों और कृषि विपणन व्यवस्था से जुड़े विषयों पर गंभीरता से कार्य किया। कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन, मंडियों के आधुनिकीकरण और किसानों को सुविधाएँ उपलब्ध कराने की दिशा में कई प्रशासनिक सुधार किए गए।

मंडी परिषद में कार्य करते हुए उन्होंने यह समझ विकसित की कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती केवल खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि कृषि विपणन व्यवस्था को पारदर्शी और प्रभावी बनाना भी उतना ही आवश्यक है। वह किसानों को बेहतर सुविधाएँ, व्यवस्थित मंडियाँ और समयबद्ध व्यवस्थाएँ उपलब्ध कराने में सफल रहे।

उनकी कार्यशैली की सबसे बड़ी विशेषता रही है—शांत नेतृत्व और परिणामोन्मुख प्रशासन। वे अनावश्यक प्रचार से दूर रहते हुए कार्य को प्राथमिकता देने वाले अधिकारी माने जाते हैं। प्रशासनिक बैठकों में वे अधिकारियों को सजग, सक्रिय और जवाबदेह रहने के निर्देश देते रहे हैं। उनका स्पष्ट मानना है कि शासन व्यवस्था का उद्देश्य केवल आदेश जारी करना नहीं, बल्कि आम नागरिक की समस्या का समाधान सुनिश्चित करना है। मंडी परिषद में निदेशक के पद पर कार्य करते हुए उन्होंने कृषकों और व्यापारियों के हित में मंडी एक्ट और नियमों में कई प्रभावी संशोधन कराए और मंडी के समस्त कार्यों को ऑनलाइन प्लेटफार्म पर लेकर आये। मंडी परिषद की आय में कई गुना वृद्धि हुई। भारत सरकार द्वारा निर्देशित विपणन सुधारों को कार्यान्वित करने में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान रहा, जिसकी भारत सरकार द्वारा सराहना की गई।

14 सितंबर 2024 को अंजनी कुमार सिंह को मैनपुरी का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया। यहाँ उन्होंने कानून व्यवस्था, जनसुनवाई और विकास कार्यों की मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान दिया। वे नियमित रूप से तहसीलों, ब्लॉकों और ग्रामीण क्षेत्रों का निरीक्षण करते थे। अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जनता की शिकायतों का समाधान केवल कागजों पर नहीं, बल्कि वास्तविक संतुष्टि के आधार पर होना चाहिए।

उनकी प्रशासनिक सोच में जनसुनवाई को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। वे मानते हैं कि किसी भी जिले का प्रशासन तभी सफल माना जा सकता है जब आम नागरिक बिना भय और परेशानी के अपनी बात प्रशासन तक पहुँचा सके। इसी कारण वे शिकायतकर्ताओं से सीधे संवाद स्थापित करने और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने पर बल देते हैं। उनके कार्य काल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के कार्यान्वयन में जनपद को उच्च स्थान प्राप्त हुआ।

मैनपुरी जनपद के सफल कार्य काल के बाद उन्हें लखीमपुर खीरी का जिलाधिकारी बनाया गया। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का विशाल और संवेदनशील जिला माना जाता है, जहाँ कानून व्यवस्था, वन क्षेत्र, कृषि, ग्रामीण विकास और सीमावर्ती प्रशासन जैसी अनेक चुनौतियाँ मौजूद रहती हैं। ऐसे जिले में अंजनी कुमार सिंह ने प्रशासनिक सक्रियता और समन्वय आधारित कार्यशैली को प्राथमिकता दी।

लखीमपुर खीरी में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनसुनवाई को प्रभावी बनाया जाए और शिकायतकर्ता की संतुष्टि सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि केवल समस्या दर्ज कर लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका समाधान भी दिखाई देना चाहिए। मीडिया के साथ सकारात्मक संवाद और पारदर्शिता को वे प्रशासनिक उत्तरदायित्व का हिस्सा मानते हैं।

जागरूक

एक समर्पित प्रशासक, ईमानदार अफसर और विकास का प्रतीक

वैभव श्रीवास्तव (सारण)

आईएएस अधिकारी वैभव श्रीवास्तव बिहार कैडर के 2018 बैच के उन प्रतिभाशाली अधिकारियों में गिने जाते हैं जिन्होंने कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है। वर्तमान में वे सारण जिले के जिलाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और अपनी पारदर्शी कार्यशैली, प्रशासनिक दक्षता तथा जनकेंद्रित सोच के कारण लगातार चर्चा में हैं। प्रशासनिक निर्णयों में स्पष्टता, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनता से सीधा संवाद उनकी पहचान बन चुका है। उनके नेतृत्व में सारण जिले में विकास, जवाबदेही और प्रशासनिक सक्रियता को नई दिशा मिली है।

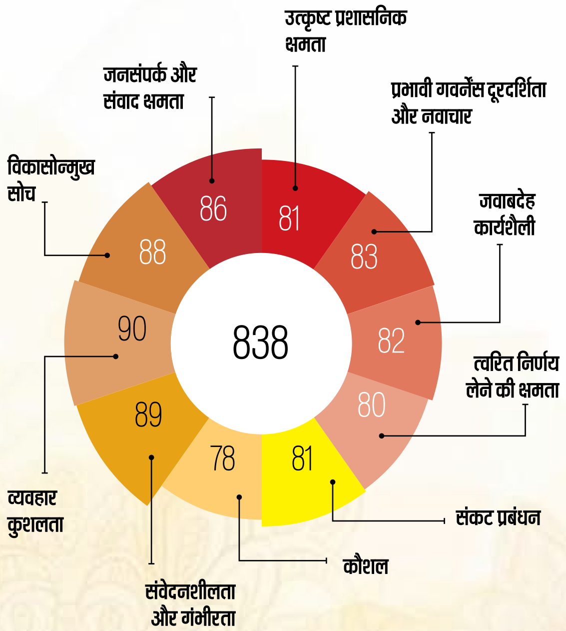

फेम इंडिया-एशिया पोस्ट के 'सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026' के वार्षिक सर्वे में प्रशासनिक अधिकारी वैभव श्रीवास्तव को 'जागरूक' श्रेणी में प्रमुख पाया गया है।

वैभव श्रीवास्तव की कार्यशैली का सबसे मजबूत पक्ष जनता से सीधा संवाद है। वे नियमित जनसुनवाई करते हैं और लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हैं। फील्ड विजिट के दौरान वे योजनाओं की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण करते हैं और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश देते हैं। यही कारण है कि लोग उन्हें संवेदनशील और सक्रिय प्रशासक के रूप में देखते हैं। उनकी प्रशासनिक शैली में पारदर्शिता, जवाबदेही और टीमवर्क स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

वैभव श्रीवास्तव का जन्म 16 दिसंबर 1989 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के गोला नगर में हुआ। उनके पिता दीपक श्रीवास्तव और माता निधि श्रीवास्तव ने बचपन से ही उन्हें अनुशासन, शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी के संस्कार दिए। पढ़ाई के दौरान वे हमेशा मेधावी छात्र रहे और विज्ञान तथा तकनीक में विशेष रुचि रखते थे। बाद में उन्होंने सूरत से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री प्राप्त की। इंजीनियरिंग शिक्षा ने उनमें तार्किक सोच, समस्या समाधान क्षमता और तकनीकी दृष्टिकोण विकसित किया, जिसका लाभ उन्हें प्रशासनिक सेवा में भी मिला।

इंजीनियरिंग के बाद उन्होंने कॉर्पोरेट क्षेत्र में कार्य किया, लेकिन उनका लक्ष्य हमेशा लोकसेवा था। उन्होंने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी पूरी गंभीरता के साथ शुरू की। वर्ष 2017 की सिविल सेवा परीक्षा में उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर 98वीं रैंक प्राप्त की। इसके साथ ही भारतीय वन सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक एक हासिल करना उनकी असाधारण प्रतिभा का प्रमाण था।

बिहार कैडर मिलने के बाद उन्होंने विभिन्न प्रशासनिक जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाया। नालंदा जिले में डेवलपमेंट डिप्टी कमिश्नर के रूप में उन्होंने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाई। उन्होंने ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी मजबूत की और कई प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रयास किया। उनके कार्यकाल में योजनाओं की नियमित समीक्षा, फील्ड निरीक्षण और समयबद्ध कार्य संस्कृति पर विशेष जोर दिया गया। इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ी और आम लोगों को योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी तरीके से मिलने लगा। उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को सुव्यवस्थित किया, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया और नवाचार के माध्यम से दक्षता बढ़ाई। उनकी कार्यशैली ने उन्हें कुशल और नवोन्मेषी प्रशासक के रूप में पहचान दिलाई।

सितंबर 2024 में उन्हें बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का निदेशक बनाया गया। इस जिम्मेदारी में उन्होंने सरकार और जनता के बीच संवाद को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण पहल कीं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने बिहार पत्रकार बीमा योजना में सुधार कर प्रीमियम कम कराया और आवेदन की समय सीमा बढ़ाने जैसे कदम उठाए। उन्होंने सरकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए आधुनिक संचार माध्यमों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग पर भी जोर दिया।

10 दिसंबर 2025 को वैभव श्रीवास्तव ने सारण जिले के जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला। सारण बिहार का ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण जिला है, जहां जलजमाव, ट्रैफिक, आधारभूत संरचना और शहरी प्रबंधन जैसी कई चुनौतियां लंबे समय से मौजूद रही हैं। पदभार संभालते ही उन्होंने विकास कार्यों की समीक्षा शुरू की और अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि योजनाओं में लापरवाही या देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने सभी प्रखंडों में चल रही योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बल दिया।

सारण में जलजमाव की समस्या को उन्होंने प्राथमिकता के साथ उठाया। खनुआ नाला परियोजना को समय पर पूरा कराने के लिए उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए। नाले की सफाई, अतिक्रमण हटाने और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अभियान चलाए गए। प्रशासनिक स्तर पर इन प्रयासों का उद्देश्य बरसात के दौरान लोगों को राहत देना और शहरी व्यवस्था को बेहतर बनाना था। मीडिया रिपोर्टों में इन पहलों को सारण के लिए महत्वपूर्ण कदम माना गया।

सड़क और आधारभूत संरचना विकास के क्षेत्र में भी उन्होंने तेजी से काम आगे बढ़ाने पर जोर दिया। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और चौड़ीकरण कार्यों की नियमित समीक्षा की गई। उनका मानना है कि बेहतर सड़क नेटवर्क व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और निवेश को बढ़ावा देता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्य गुणवत्ता और समय सीमा दोनों का पालन करते हुए पूरे किए जाएं। डबल डेकर पुल सहित कई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर भी प्रशासनिक स्तर पर सक्रियता दिखाई गई।

यातायात व्यवस्था सुधारना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहा। छपरा शहर में जाम की समस्या को देखते हुए उन्होंने ट्रैफिक नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था और सड़क अतिक्रमण हटाने पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ कई समीक्षा बैठकें कीं और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में बेहतर प्रबंधन की रणनीति तैयार कराई। आम नागरिकों को सुगम यातायात उपलब्ध कराने की दिशा में यह प्रयास महत्वपूर्ण माना गया।

वे डिजिटल प्रशासन और तकनीकी समाधानों के समर्थक माने जाते हैं। इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि होने के कारण वे परियोजनाओं की निगरानी में तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देते हैं। वे मानते हैं कि डिजिटल टूल्स और पारदर्शी व्यवस्था से भ्रष्टाचार कम होता है तथा योजनाओं का लाभ तेजी से जनता तक पहुंचता है। प्रशासनिक पारदर्शिता, आरटीआई व्यवस्था को मजबूत करना और जवाबदेह शासन उनकी कार्यशैली के प्रमुख आधार हैं।

वैभव श्रीवास्तव केवल एक कुशल प्रशासक ही नहीं बल्कि प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी हैं। उन्हें यात्रा और फोटोग्राफी का शौक है तथा वे युवाओं को निरंतर सीखने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनकी सफलता की कहानी बताती है कि ईमानदारी, अनुशासन और दूरदर्शिता के साथ कोई भी व्यक्ति समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। वैभव श्रीवास्तव जैसे अधिकारी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाते हैं और विकास की नई संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने का कार्य करते हैं। वे सकारात्मक और समाधानमुखी प्रशासनिक दृष्टिकोण अपनाते हैं।

जवाबदेह

विकास की नई राह गढ़ते प्रशासनिक नेतृत्व का नाम

दिव्या उमेश मिश्रा (बालोद)

दिव्या उमेश मिश्रा छत्तीसगढ़ की उन ऊर्जावान और दूरदर्शी प्रशासनिक अधिकारियों में शामिल हैं जिन्होंने कम समय में विकास को जन-आंदोलन का स्वरूप देकर प्रशासनिक सफलता की नई मिसाल स्थापित की है। वर्ष 2012 बैच की इस आईएएस अधिकारी ने अप्रैल 2025 में बालोद की कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी का कार्यभार संभालते ही जिले को जल-सुरक्षित, पर्यावरण-अनुकूल, आर्थिक रूप से सशक्त और सामाजिक रूप से जागरूक बनाने का व्यापक अभियान शुरू किया। केवल एक वर्ष के भीतर अप्रैल 2026 तक बालोद राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल जिले के रूप में पहचाना जाने लगा।

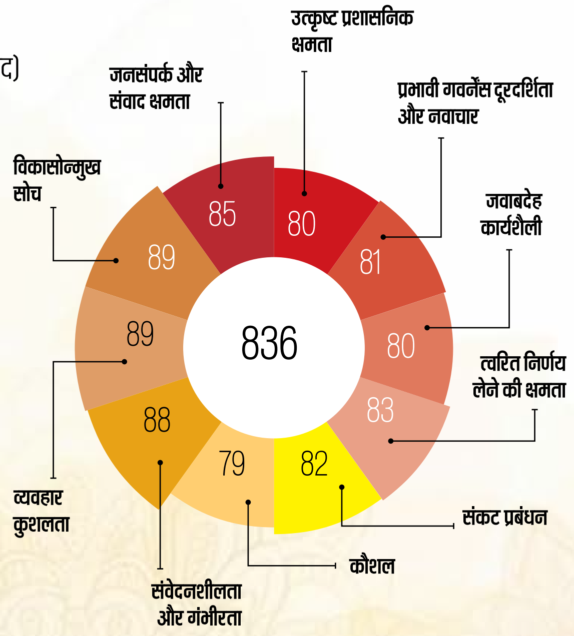

फेम इंडिया-एशिया पोस्ट के 'सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026' के वार्षिक सर्वे में प्रशासनिक अधिकारी दिव्या उमेश मिश्रा को 'जवाबदेह' श्रेणी में प्रमुख पाया गया है।

पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में "हरित बालोद अभियान" ने पूरे राज्य का ध्यान आकर्षित किया। इस अभियान को "एक पेड़ मां के नाम" से जोड़ा गया, जिससे लोगों का भावनात्मक जुड़ाव बढ़ा। दिव्या उमेश मिश्रा ने सिंचाई और जल उपयोग के क्षेत्र में भी अभिनव प्रयोग किए। "मिशन ओला सिंचाई" के अंतर्गत मिट्टी के छिद्रित घड़ों से कम लागत वाली ड्रिप सिंचाई प्रणाली विकसित की गई। लगभग 15 हजार घड़ों के माध्यम से पौधों को निरंतर नमी उपलब्ध कराई गई। यह प्रणाली पर्यावरण-अनुकूल होने के साथ-साथ पक्षियों और जानवरों के लिए भी जल स्रोत बन गई।

दिव्या उमेश मिश्रा की प्रशासनिक कार्यशैली चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित रही—जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि उन्होंने योजनाओं को सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें जनभागीदारी के साथ जोड़कर व्यापक सामाजिक अभियान बना दिया।

कार्यभार संभालते ही उन्होंने सबसे पहले जल संकट और गिरते भूजल स्तर पर ध्यान केंद्रित किया। "जल शक्ति जन भागीदारी अभियान" उनके नेतृत्व में बालोद की सबसे बड़ी सफलता बनकर उभरा। 6 सितंबर 2024 से 18 नवंबर 2025 तक चले इस अभियान के दौरान जिले में 1.06 लाख से अधिक जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण किया गया। इनमें लगभग 46 हजार संरचनाएं सीधे जनता की भागीदारी से बनीं। इस व्यापक प्रयास का परिणाम यह हुआ कि जिले में भूजल स्तर औसतन 1 मीटर तक बढ़ गया। बालोद को जोन स्तर पर प्रथम तथा राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। इस उपलब्धि पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा जिला प्रशासन को विशेष सम्मान प्रदान किया गया।

जल संरक्षण के अगले चरण में उन्होंने पुराने बोरवेलों के रिचार्ज, पारंपरिक जल स्रोतों—कुओं, तालाबों और नालों—के पुनर्जीवन तथा वर्षा जल संचयन को अभियान का मुख्य आधार बनाया। जिले की जीवनरेखा माने जाने वाले तांदुला जलाशय के पुनरुद्धार के लिए आईआईटी भिलाई के साथ साझेदारी की गई। गाद सफाई, खरपतवार हटाने, रिटेनिंग वॉल्स को मजबूत करने और वेटलैंड विकास जैसे कार्यों ने इस परियोजना को वैज्ञानिक आधार दिया। पहले चरण में ही 3 किलोमीटर क्षेत्र का सफल पुनर्जीवन किया गया।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उन्होंने फसल विविधीकरण कार्यक्रम पर विशेष बल दिया। धान आधारित खेती के स्थान पर दालें, तिलहन, मक्का और बागवानी को प्रोत्साहित किया गया। लगभग 55,353 हेक्टेयर क्षेत्र इस कार्यक्रम से जुड़ा। इससे किसानों की आय में वृद्धि हुई और जल उपयोग का दबाव भी कम हुआ।

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में "लखपति दीदी मॉडल" विशेष रूप से सफल रहा। औराटोला गांव को छत्तीसगढ़ का पहला "लखपति दीदी गांव" घोषित किया गया। स्वयं सहायता समूहों को मजबूत कर कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण और लघु उद्यमों से जुड़कर महिलाओं ने आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए।

कृषि आधारित उद्योगों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से उन्होंने गन्ना उत्पादन को बढ़ावा दिया। लगभग 500 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में गन्ना खेती शुरू कराई गई तथा 1,200 किसानों को हार्वेस्टर, ट्रैक्टर और लोडर जैसी आधुनिक मशीनरी उपलब्ध कराई गई। इससे किसानों की लागत कम हुई और उत्पादन क्षमता बढ़ी।

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में "प्रोजेक्ट दिनकर" उनकी सबसे दूरदर्शी पहलों में गिना जाता है। इस परियोजना के पहले चरण में 28 गांवों के पंचायत भवनों को पूरी तरह सौर ऊर्जा आधारित बनाया गया। इसके परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष लगभग 14 लाख यूनिट बिजली की बचत होने लगी। वर्चुअल नेट मीटरिंग आधारित यह मॉडल राज्य और देश दोनों स्तरों पर एक अभिनव उदाहरण बन गया।

सामाजिक सुधारों में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि बालोद को "बाल विवाह मुक्त जिला" घोषित करना रही। जिले की 437 पंचायतों और 9 नगरपालिकाओं में शून्य बाल विवाह दर्ज किए गए। यह उपलब्धि केवल प्रशासनिक सख्ती का परिणाम नहीं थी, बल्कि सामुदायिक जागरूकता और जनभागीदारी का प्रभाव भी थी।

कुपोषण से लड़ने के लिए "मिशन गोद पोषण" अभियान शुरू किया गया। पहले चरण में मध्यम और गंभीर कुपोषण से प्रभावित लगभग 15 प्रतिशत बच्चों में सुधार दर्ज किया गया। अगले चरण में 25 प्रतिशत सुधार का लक्ष्य रखा गया। इस अभियान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, महिला समूहों और पंचायतों की सक्रिय भागीदारी रही।

शिक्षा और युवा विकास के क्षेत्र में उन्होंने "नीट-जेईई आवासीय कोचिंग" कार्यक्रम शुरू किया, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिला। डिजिटल लर्निंग, पुस्तकालय और टेस्ट सीरीज जैसी सुविधाएं छात्रों को उपलब्ध कराई गईं।

"टेक्नोफेस्ट" जैसे आयोजनों के माध्यम से विज्ञान, रोबोटिक्स और नवाचार को बढ़ावा दिया गया। हर वर्ष 250 से अधिक छात्र इसमें भाग लेते हैं। 10 परियोजनाएं राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुईं और धनेली स्कूल को राष्ट्रीय पहचान मिली। इससे ग्रामीण छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवाचार की भावना विकसित हुई।

व्यवहार परिवर्तन आधारित अभियानों ने उनकी प्रशासनिक शैली को और प्रभावशाली बनाया। "नो हेलमेट, नो पेट्रोल" अभियान ने सड़क सुरक्षा को नई मजबूती दी। पेट्रोल पंपों पर हेलमेट के बिना ईंधन न देने की व्यवस्था लागू की गई, जिससे लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी।

उन्होंने 440 सूखे बोरवेलों को रिचार्ज संरचना में परिवर्तित कराया। "जल वाहिनी नेटवर्क" के अंतर्गत 436 महिला समितियों का गठन किया गया। ये समितियां गांव स्तर पर जल संरक्षण की निगरानी और जागरूकता का कार्य करती हैं।

दिव्या उमेश मिश्रा की प्रशासनिक शैली में तकनीक, पर्यावरणीय संवेदनशीलता और जनभागीदारी का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। वह आज केवल एक सफल प्रशासक नहीं, बल्कि संवेदनशील नेतृत्व, हरित विकास और जनसेवा की सशक्त प्रतीक बन चुकी हैं। बालोद में उनके प्रयास आने वाले वर्षों तक विकास और सुशासन के प्रेरणादायी उदाहरण के रूप में याद किए जाएंगे।

व्यवहारकुशल

विकास, नवाचार और जनसरोकारों को समर्पित एक संवेदनशील प्रशासक

दीपेश कुमार (सहरसा)

बिहार के अररिया जिले के बथनाहा में जन्मे दीपेश कुमार का बचपन विभिन्न सामाजिक और प्रशासनिक अनुभवों के बीच बीता। उनके पिता सिंचाई विभाग में अधिकारी थे, जिसके कारण परिवार को बिहार और झारखंड के अलग-अलग जिलों में रहना पड़ा। इस दौरान उन्हें विभिन्न क्षेत्रों की सामाजिक परिस्थितियों, ग्रामीण जीवन और प्रशासनिक चुनौतियों को नजदीक से देखने का अवसर मिला।

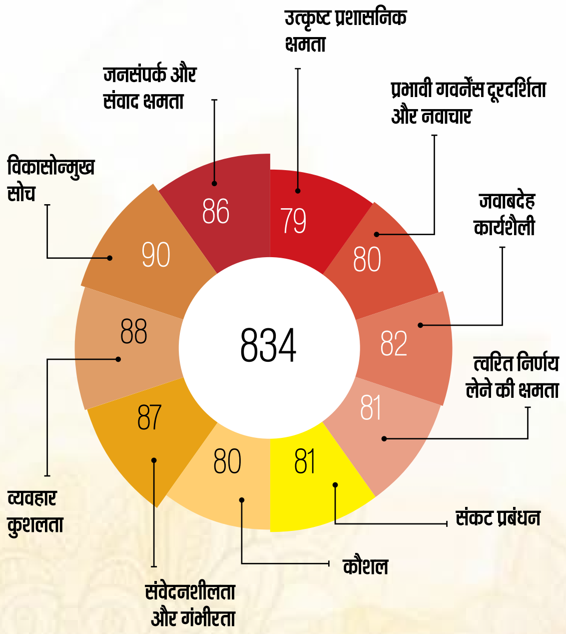

फेम इंडिया-एशिया पोस्ट के 'सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026' के वार्षिक सर्वे में प्रशासनिक अधिकारी दीपेश कुमार को 'व्यवहारकुशल' श्रेणी में प्रमुख पाया गया है।

एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनकी पहचान ऐसे अधिकारी की है जो विकास, नवाचार और संवेदनशील प्रशासन के बीच संतुलन बनाकर काम करते हैं। उनका विश्वास है कि प्रशासन का वास्तविक उद्देश्य आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। इसी सोच के साथ वे सहरसा को बिहार के एक विकसित और मॉडल जिले के रूप में स्थापित करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। आज वे उन अधिकारियों में गिने जाते हैं जो आधुनिक सोच, तकनीकी समझ और मानवीय दृष्टिकोण के साथ प्रशासन को अधिक प्रभावी और जनोन्मुख बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं।

दीपेश कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन अनुभवी अधिकारियों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी सादगी, शांत स्वभाव और व्यावहारिक कार्यशैली के माध्यम से प्रशासन को अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनाने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि प्रशासन का उद्देश्य केवल सरकारी योजनाओं को लागू करना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना भी है।

उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से सिविल इंजीनियरिंग में एम.टेक की डिग्री प्राप्त की और निर्माण कार्यों, इंफ्रास्ट्रक्चर व परियोजना प्रबंधन की अच्छी समझ विकसित की। अपने पेशेवर जीवन में उत्कृष्ट सिविल कार्यों के लिए उन्हें मुख्यमंत्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जो उनकी तकनीकी दक्षता और कार्यकुशलता को दर्शाता है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में आने से पहले उन्होंने बिहार इंजीनियरिंग सेवा में कार्य किया। इस दौरान उन्होंने सड़क, भवन और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं पर काम किया तथा प्रशासन और शासन के व्यावहारिक पहलुओं को करीब से समझा। वर्ष 2017 बैच के आईएएस अधिकारी बनने के बाद उन्होंने मधुबनी में उप विकास आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला। यहाँ उन्होंने कई विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मधुबनी में सफल कार्यकाल के बाद उन्हें सहरसा का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया। वर्तमान में वे सहरसा जिले के समग्र विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। सहरसा कोसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित कोसी प्रमंडल का मुख्यालय है। यह क्षेत्र लंबे समय से बाढ़ और कमजोर संपर्क व्यवस्था जैसी समस्याओं से प्रभावित रहा है। इन चुनौतियों के बीच दीपेश कुमार ने कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया।

क्षेत्र की संपर्क व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए रेलवे ओवरब्रिज परियोजना की शुरुआत कराई गई। इसके अलावा सहरसा-मधेपुरा और सहरसा-सुपौल सड़क परियोजनाओं में भी तेजी लाई गई। कोसी क्षेत्र में बाढ़ के दौरान पुलों के बह जाने की समस्या लंबे समय से लोगों के लिए परेशानी का कारण रही है। ऐसे में कोसी नदी पर देंगराही पुल निर्माण कार्य की शुरुआत को स्थानीय लोग एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते हैं, क्योंकि इससे क्षेत्र की आवाजाही और संपर्क व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने कई नई पहलें शुरू कीं। सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति की नियमित निगरानी के लिए साप्ताहिक मूल्यांकन परीक्षा की व्यवस्था लागू की गई। साथ ही छात्रों के शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों के अंतिम पीरियड को खेलकूद के लिए आरक्षित किया गया। यह पहल इतनी प्रभावी साबित हुई कि बाद में बिहार सरकार ने इसे पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी सोच केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है।

महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार को बढ़ावा देना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। जीविका समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए पतरघट, सलखुआ और सिमरी बख्तियारपुर जैसे क्षेत्रों में जीविका वेंडिंग जोन स्थापित किए गए। इन केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला। इसके अलावा सहरसा में मखाना क्लस्टर के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा लगभग 2.34 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे किसानों और महिलाओं के लिए नए आर्थिक अवसर पैदा होने की संभावना है। महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सिलाई केंद्रों की स्थापना भी की गई।

स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने "कायाकल्प" पहल के तहत अस्पतालों की स्वच्छता, आधारभूत सुविधाओं और बायो-मेडिकल वेस्ट प्रबंधन में सुधार पर विशेष ध्यान दिया। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप सहरसा सदर अस्पताल राज्य के बेहतर अस्पतालों में शामिल हुआ और उसे वित्तीय प्रोत्साहन के साथ राज्य स्तरीय सम्मान भी प्राप्त हुआ। यह उपलब्धि स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार का एक महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जाती है।

शहरी विकास और पर्यटन के क्षेत्र में भी उनके प्रयास उल्लेखनीय रहे हैं। बिहार सरकार ने सहरसा में मत्स्यगंधा झील और उसके आसपास पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 98 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इसे क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जिले में कई नए पार्कों का निर्माण कराया गया है। साथ ही 8वीं शताब्दी के प्रसिद्ध दार्शनिक पंडित मंदन मिश्र के जन्मस्थान मंदन धाम के विकास और पुनर्जीवन के लिए भी पहल की गई है।

मंडन धाम ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। मान्यता है कि लगभग बारह सौ वर्ष पूर्व यहीं आदि शंकराचार्य और पंडित मंडन मिश्र के बीच प्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ था। वर्तमान में इस स्थान को एक प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा जिला स्टेडियम के आधुनिकीकरण का कार्य भी आगे बढ़ाया गया है ताकि युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें।

दीपेश कुमार की कार्यशैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह केवल योजनाओं की घोषणा तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी समान रूप से ध्यान देते हैं। उनकी तकनीकी पृष्ठभूमि उन्हें परियोजनाओं की गुणवत्ता, समयबद्धता और परिणामों पर विशेष ध्यान देने में मदद करती है। यही कारण है कि उनके नेतृत्व में कई विकास कार्य अपेक्षाकृत तेज गति से आगे बढ़े हैं।

सर्वश्रेष्ठ 2026 जिलाधिकारी
FAME INDIA

कर्तव्यनिष्ठ

जनसेवा, संवेदनशीलता और दूरदृष्टि के पर्याय

मनमोहन शर्मा (सोलन)

मनमोहन शर्मा हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के उन प्रतिष्ठित अधिकारियों में गिने जाते हैं जिन्होंने अपनी शांत कार्यशैली, जनसरोकार और परिणामोन्मुख दृष्टिकोण से प्रशासनिक जगत में विशेष पहचान बनाई है। वर्ष 2013 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी मनमोहन शर्मा वर्तमान में हिमाचल के सबसे महत्वपूर्ण जिलों में से एक सोलन के उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।

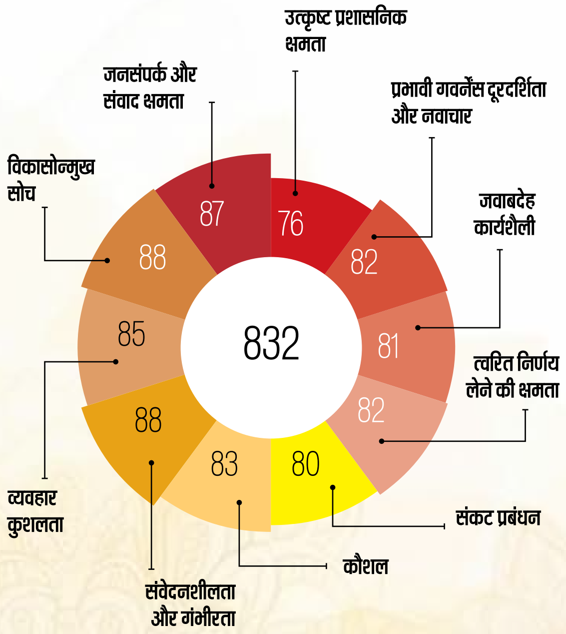

फेम इंडिया-एशिया पोस्ट के 'सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026' के वार्षिक सर्वे में प्रशासनिक अधिकारी मनमोहन शर्मा को 'कर्तव्यनिष्ठ' श्रेणी में प्रमुख पाया गया है।

मनमोहन शर्मा की सबसे बड़ी विशेषता उनकी संतुलित और संवेदनशील कार्यशैली है। वे केवल आदेश देने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि संवाद, समन्वय और जनभागीदारी के माध्यम से शासन व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में विश्वास रखते हैं। नियमित फील्ड विजिट और जनसंवाद के जरिए उन्होंने प्रशासन को जनता के और करीब लाने का प्रयास किया है। आज जब देश को ऐसे अधिकारियों की आवश्यकता है जो विकास, पर्यावरण संरक्षण और जनहित के बीच संतुलन स्थापित कर सकें, तब मनमोहन शर्मा एक प्रेरक उदाहरण के रूप में सामने आते हैं। उनकी कार्यशैली यह दर्शाती है कि यदि दृष्टिकोण जनकेंद्रित हो और इच्छाशक्ति मजबूत हो, तो प्रशासन समाज में वास्तविक और सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।

हिमाचल प्रदेश के ठियोग क्षेत्र से संबंध रखने वाले मनमोहन शर्मा की जीवन यात्रा संघर्ष, धैर्य और निरंतर मेहनत की प्रेरक कहानी है। विज्ञान में स्नातक करने के बाद उन्होंने विधि की शिक्षा प्राप्त की तथा पर्सोनल मैनेजमेंट एवं लेबर वेलफेयर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के पीछे उनका अथक परिश्रम और दृढ़ इच्छाशक्ति रही। उनका मानना है कि सफलता का मार्ग कठिनाइयों से होकर गुजरता है और जो निरंतर प्रयास करते हैं, वही अंततः सफलता प्राप्त करते हैं।

अपने प्रशासनिक जीवन में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण दायित्व निभाए हैं। वे नालागढ़ में एसडीएम और नाहन में अतिरिक्त उपायुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा शिमला में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, शहरी विकास निदेशक, शिमला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कार्मिक एवं वित्त निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। इन सभी दायित्वों में उनकी कार्यशैली का मूल केंद्र रहा—जनसरोकार, पारदर्शिता और परिणाम आधारित प्रशासन।

सोलन के उपायुक्त के रूप में उनका कार्यकाल बहुआयामी विकास और सुशासन का उदाहरण बनकर सामने आया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ उन्होंने जनशिकायतों के त्वरित समाधान, राजस्व प्रशासन को मजबूत करने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाने पर विशेष ध्यान दिया। नियमित जनसुनवाई, राजस्व लोक अदालतों और फील्ड निरीक्षणों के माध्यम से उन्होंने आम लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का प्रयास किया।

सोलन जिले में अतिक्रमण हटाने और सरकारी भूमि की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने प्रभावी कदम उठाए। अवैध कब्जों को हटाने, राजस्व अभिलेखों को व्यवस्थित करने और प्रशासनिक निगरानी को मजबूत करने से भूमि प्रबंधन व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। हथियार लाइसेंस, पेट्रोल पंप एनओसी, सिनेमा लाइसेंस और सोसायटी पंजीकरण जैसे कार्यों को भी अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाया गया।

कालका-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग-5 के फोरलेन निर्माण कार्य की निगरानी भी उनके महत्वपूर्ण दायित्वों में शामिल रही। परियोजना से जुड़े मुआवजा, क्षति और पुनर्वास मामलों की नियमित समीक्षा कर उन्होंने प्रभावित लोगों की समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभाई।

पर्यावरण संरक्षण और कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में भी उनका कार्य उल्लेखनीय रहा है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण से जुड़े मामलों, प्रदूषण नियंत्रण और गैर-जैविक कचरे के प्रबंधन पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। हिमाचल प्रदेश गैर-जैविक कचरा नियंत्रण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन से जिले में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिली।

युवा सशक्तिकरण और कौशल विकास को लेकर उनकी दृष्टि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके नेतृत्व में विभिन्न कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को गति मिली। अंग्रेजी रोजगार क्षमता, उद्यमिता, टेलीकॉम, प्लंबिंग, निर्माण कार्य, स्वास्थ्य सेवा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, ब्यूटी एवं वेलनेस जैसे अनेक क्षेत्रों में युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक समर्थित परियोजनाओं के माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। "अपना विद्यालय : हिमाचल स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम" के अंतर्गत उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोठों को गोद लेकर वहां शैक्षिक और आधारभूत सुविधाओं के विकास पर कार्य किया। उनका मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही समाज को दीर्घकालिक रूप से मजबूत बना सकती है।

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मनमोहन शर्मा का कार्य विशेष रूप से सराहनीय रहा है। वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश में आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के बाद उन्होंने पुनर्वास और आपदा प्रतिरोधी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। "मॉडल रेजिलिएंट विलेज" परियोजना के अंतर्गत नालागढ़ क्षेत्र के सुनानी गांव में पुनर्निर्माण, आधारभूत ढांचे की बहाली और आजीविका सुदृढ़ीकरण का कार्य शुरू किया गया। यह परियोजना जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से संचालित की जा रही है।

भूस्खलन और मिट्टी का कटाव एक आम समस्या है, जो लगातार विकराल हो रही है, लेकिन इससे निपटने के लिए उन्होंने जैव-इंजीनियरिंग आधारित समाधान को प्रोत्साहित किया। सोलन के बार्टी कृषि फार्म में वेटिवर घास नर्सरी की स्थापना इसी दिशा में एक अभिनव पहल रही जिसका उद्देश्य पारंपरिक संरचनात्मक उपायों पर निर्भरता कम कर पर्यावरण-अनुकूल और टिकाऊ समाधान विकसित करना है। चिन्हित भूस्खलन क्षेत्रों में वेटिवर घास का रोपण भी कराया गया, जिससे मिट्टी स्थिरीकरण और आपदा जोखिम न्यूनीकरण में मदद मिली।

आपदा जागरूकता को जन-आंदोलन बनाने के लिए उनके नेतृत्व में मॉक ड्रिल, प्रशिक्षण कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक और जागरूकता अभियान भी आयोजित किए गए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और विभिन्न विभागों के सहयोग से संचालित इन कार्यक्रमों ने लोगों को आपदा के प्रति अधिक सजग बनाया। ग्रामीण विकास योजनाओं की निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा है। मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी योजनाओं को उन्होंने बेहतर समन्वय और निगरानी के माध्यम से गति प्रदान की।

महिला एवं बाल विकास योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, मिशन वात्सल्य, पोषण अभियान और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया।

कर्मयोद्धा

नवाचार, पर्यावरण और जनसशक्तिकरण से नई दिशा देने वाली अधिकारी

हरिचंदना दासरी

(हैदराबाद, वर्तमान में श्रम मंत्रालय)

हरिचंदना दासरी भारतीय प्रशासनिक सेवा की उन चुनिंदा अधिकारियों में शामिल हैं जिन्होंने प्रशासन को केवल सरकारी व्यवस्था तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे सामाजिक परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और नागरिक सहभागिता का प्रभावी माध्यम बनाया। वर्ष 2010 बैच की तेलंगाना कैडर की इस अधिकारी ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व, संवेदनशील सोच और नवाचार आधारित प्रशासनिक शैली से राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान बनाई है। वर्तमान में वे हैदराबाद की जिला कलेक्टर के रूप में कार्यरत हैं और राजधानी हैदराबाद में प्रशासनिक सुधारों तथा नागरिक-केंद्रित विकास कार्यों को नई दिशा दे रही हैं।

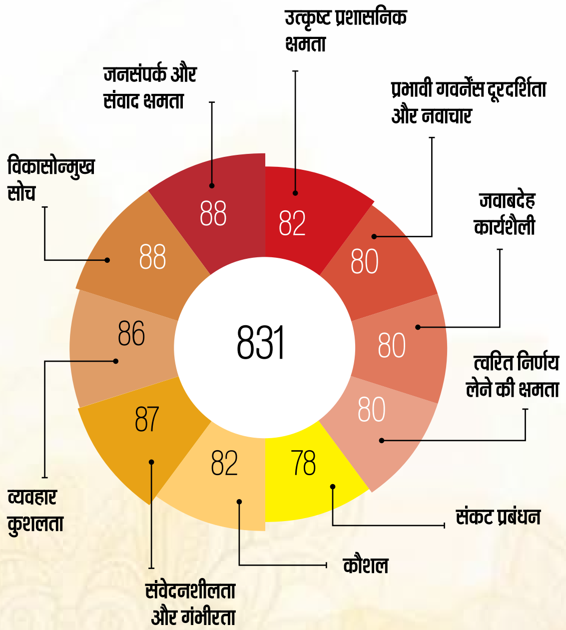

फेम इंडिया-एशिया पोस्ट के 'सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026' के वार्षिक सर्वे में प्रशासनिक अधिकारी हरिचंदना दासरी को 'कर्मयोद्धा' श्रेणी में प्रमुख पाया गया है।

वर्तमान में उनकी पोस्टिंग तेलंगाना के श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कारखाना विभाग में सचिव के पद पर हुई है। एक अधिकारी के तौर पर उनकी प्रशासनिक उपलब्धियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक मान्यता मिली है। उनकी कार्यशैली यह सिद्ध करती है कि यदि प्रशासन संवेदनशीलता, नवाचार और जनभागीदारी के साथ कार्य करे तो शासन व्यवस्था केवल नीतियों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समाज में वास्तविक और स्थायी परिवर्तन का माध्यम बन जाती है। पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल शिक्षा, शहरी सुधार और जनकेंद्रित प्रशासन के क्षेत्र में उनके प्रयास आज हैदराबाद ही नहीं, बल्कि पूरे देश के प्रशासनिक तंत्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं।

हरिचंदना दासरी की शैक्षणिक और प्रशासनिक यात्रा अत्यंत प्रेरणादायक रही है। हैदराबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने लंदन की आकर्षक नौकरी छोड़कर भारतीय प्रशासनिक सेवा का मार्ग चुना। उनका मानना रहा है कि प्रशासन केवल शासन चलाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि समाज के जीवन में स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन लाने का माध्यम है।

अपने प्रशासनिक जीवन में उन्होंने विशाखापट्टनम में सहायक कलेक्टर, विजयवाड़ा में उप कलेक्टर, ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में जोनल कमिश्नर, नारायणपेट और नलगोंडा की जिला कलेक्टर, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, आयुष निदेशक, नगर प्रशासन निदेशक तथा राष्ट्रीय निर्माण अकादमी की महानिदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। प्रत्येक जिम्मेदारी में उनकी कार्यशैली नवाचार, पारदर्शिता और जमीनी भागीदारी पर आधारित रही।

हैदराबाद में उनकी भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। एक महानगर के रूप में हैदराबाद तेजी से बढ़ते शहरीकरण, यातायात दबाव, प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण और नागरिक सुविधाओं जैसी अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। हरिचंदना दासरी ने इन चुनौतियों को केवल प्रशासनिक समस्या के रूप में नहीं देखा, बल्कि उन्हें नागरिक सहभागिता और पर्यावरणीय सुधारों के अवसर में बदला।

ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में जोनल कमिश्नर के रूप में उन्होंने प्लास्टिक कचरे के पुनर्चक्रण की एक अभिनव पहल शुरू की। इस परियोजना के अंतर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग कर पावर टाइल्स और सड़क निर्माण सामग्री तैयार की गई। हजारों वर्गफुट क्षेत्र में इन टाइल्स का उपयोग किया गया। यह पहल केवल स्वच्छता अभियान तक सीमित नहीं रही, बल्कि शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के एक टिकाऊ मॉडल के रूप में सामने आई। इस प्रयोग ने पर्यावरण संरक्षण और शहरी आधारभूत संरचना विकास के बीच एक नया संतुलन स्थापित किया।

हैदराबाद में उनके नेतृत्व में दुर्गम चेरुवु झील के पुनर्जीवन का कार्य भी व्यापक रूप से चर्चा में रहा। कभी उपेक्षित और प्रदूषित हो चुकी यह झील उनके प्रयासों से एक आधुनिक, स्वच्छ और पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक स्थल के रूप में विकसित हुई। झील के आसपास हरित क्षेत्र, पैदल पथ, प्रकाश व्यवस्था और पर्यावरणीय संरचना विकसित की गई, जिससे यह स्थान नागरिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। यह परियोजना शहरी पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक उपयोगिता का उत्कृष्ट उदाहरण मानी गई।

हरिचंदना दासरी ने शहरी जीवन में पशु-अनुकूल सार्वजनिक स्थलों की आवश्यकता को भी समझा। उनके नेतृत्व में गाचीबोवली में भारत का पहला प्रमाणित "पेट पार्क" विकसित किया गया। इस पार्क में पालतू पशुओं के लिए विशेष गतिविधि क्षेत्र, जलक्रीड़ा क्षेत्र और अलग-अलग सुरक्षित स्थान बनाए गए। यह पहल आधुनिक शहरी जीवन शैली और नागरिक सुविधाओं के क्षेत्र में एक अभिनव प्रयोग के रूप में देखी गई।

हैदराबाद में जिला कलेक्टर के रूप में उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी और नागरिक-अनुकूल बनाने पर विशेष बल दिया है। भूमि प्रबंधन, राजस्व प्रशासन, नागरिक शिकायत निवारण और शहरी समन्वय से जुड़े कार्यों में तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया गया। वे नियमित जनसुनवाई और क्षेत्रीय निरीक्षण के माध्यम से प्रशासन को सीधे जनता से जोड़ने का प्रयास करती हैं।

उनकी कार्यशैली का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है—समावेशी विकास। वे मानती हैं कि किसी भी महानगर का वास्तविक विकास तभी संभव है जब समाज का अंतिम व्यक्ति भी विकास की प्रक्रिया से जुड़ सके। इसी सोच के तहत उन्होंने महिला समूहों, शहरी गरीबों, युवाओं और छोटे उद्यमियों को प्रशासनिक योजनाओं से जोड़ने पर बल दिया।

नारायणपेट में शुरू की गई "आरुण्य" पहल का प्रभाव आज भी चर्चा में है। इस मंच के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं, बुनकरों और कारीगरों को राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा गया। हथकरघा उत्पाद, हस्तशिल्प और स्थानीय खाद्य उत्पादों को डिजिटल मंच उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दी गई। यह मॉडल आज शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बीच समन्वय का प्रेरक उदाहरण माना जाता है।

महिला गरिमा और सार्वजनिक स्वच्छता के क्षेत्र में उनकी "शी टॉयलेट" पहल अत्यंत प्रभावशाली रही। महिलाओं के लिए विशेष मोबाइल शौचालय बस की यह व्यवस्था तेलंगाना की पहली ऐसी पहल थी। इसके अंतर्गत हजारों घरेलू शौचालयों का निर्माण कराया गया और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए गए। इस अभिनव परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली और प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया।

शिक्षा और डिजिटल सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी हरिचंदना दासरी का योगदान उल्लेखनीय है। "अर्ली कोडर्स" कार्यक्रम के माध्यम से सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों और शिक्षकों को आधुनिक तकनीकी शिक्षा से जोड़ा गया। प्रोग्रामिंग और डिजिटल शिक्षा की यह पहल ग्रामीण और साधारण पृष्ठभूमि के छात्रों को नई संभावनाओं से जोड़ने का माध्यम बनी।

कोविड महामारी के दौरान उन्होंने "टी-कंसल्ट" नामक टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत कर दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की। इस व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को फोन और वीडियो कॉल के जरिए चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराया गया। आयुष चिकित्सकों को भी इससे जोड़कर उन्होंने समग्र स्वास्थ्य मॉडल को बढ़ावा दिया।

सर्वश्रेष्ठ
जिलाधिकारी 2026

हौसलामंद

युवा ऊर्जा, दूरदृष्टि और जनसेवा का प्रतीक

लक्ष्य सिंघल (दक्षिण दिल्ली)

लक्ष्य सिंघल भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन युवा और ऊर्जावान अधिकारियों में शामिल हैं जिन्होंने कम समय में अपनी कार्यशैली, संवेदनशीलता और परिणामोन्मुख नेतृत्व से अलग पहचान बनाई है। वर्ष 2019 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी लक्ष्य सिंघल वर्तमान में दक्षिण दिल्ली जिला के जिलाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राजधानी दिल्ली जैसे जटिल और बहुआयामी प्रशासनिक क्षेत्र में कार्य करते हुए उन्होंने जिस प्रकार जनहित, पारदर्शिता और विकास को प्राथमिकता दी है, वह उन्हें नई पीढ़ी के प्रभावी अधिकारियों में शामिल करता है।

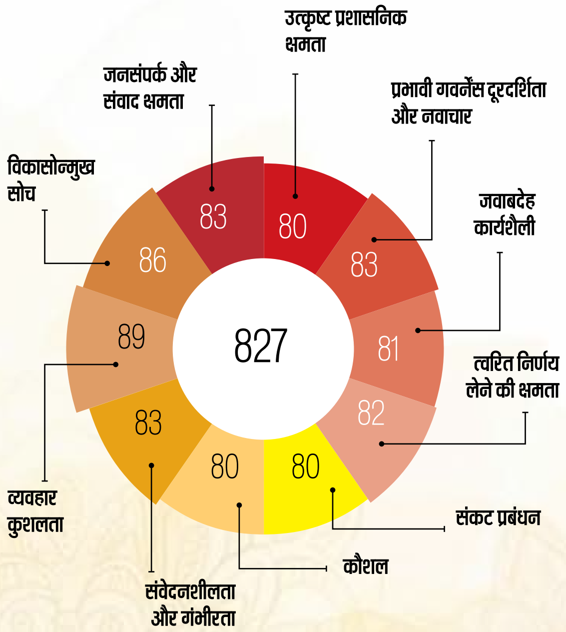

सर्वश्रेष्ठ
2026 जिलाधिकारी

फेम इंडिया-एशिया पोस्ट के 'सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026' के वार्षिक सर्वे में प्रशासनिक अधिकारी लक्ष्य सिंघल को 'हौसलामंद' श्रेणी में प्रमुख पाया गया है।

युवा सोच, आधुनिक कार्यदृष्टि और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता ने लक्ष्य सिंघल को ऐसे अधिकारी के रूप में स्थापित किया है, जिन्हें एक सकारात्मक और परिणामोन्मुख प्रशासक माना जाता है। चाहे सीमावर्ती लद्दाख का कठिन भूभाग हो या देश की राजधानी दिल्ली की जटिल चुनौतियां, उन्होंने हर जिम्मेदारी को संवेदनशीलता और दृढ़ता के साथ निभाया है। उनकी कार्यशैली यह दर्शाती है। वो यह कि जमीनी जुड़ाव, स्पष्ट दृष्टि और मजबूत इच्छाशक्ति प्रशासन को वास्तव में प्रभावी बना सकते हैं।

लक्ष्य सिंघल उन अधिकारियों में माने जाते हैं जो शासन व्यवस्था को केवल दफ्तरों और फाइलों तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे सीधे आम लोगों के जीवन से जोड़ने का प्रयास करते हैं। चाहे राजस्व मामलों का निपटारा हो, भूमि प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, वरिष्ठ नागरिकों को राहत दिलाना या विकास परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा कराना—हर क्षेत्र में उन्होंने सक्रिय और संवेदनशील नेतृत्व का परिचय दिया है।

दक्षिण दिल्ली में जिलाधिकारी का दायित्व संभालने के बाद उनका सबसे चर्चित कार्य सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का रहा। वर्षों से अवैध कब्जों का सामना कर रही कई महत्वपूर्ण सरकारी जमीनों को मुक्त कराकर दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंपा गया, जिससे योजनाबद्ध शहरी विकास को गति मिली। यह कार्य केवल प्रशासनिक कार्रवाई भर नहीं था, बल्कि इसके लिए कानूनी समझ, रणनीतिक समन्वय और दृढ़ इच्छाशक्ति की आवश्यकता थी। विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित कर उन्होंने इस चुनौतीपूर्ण अभियान को प्रभावी ढंग से पूरा किया।

वन भूमि से जुड़े लंबे समय से लंबित मामलों के समाधान में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। दक्षिण दिल्ली के वन क्षेत्रों की सीमांकन प्रक्रिया को पूरा कर उन्होंने वर्षों पुराने विवादों और अस्पष्टताओं को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया। इससे न केवल भूमि प्रबंधन व्यवस्था अधिक स्पष्ट हुई, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी मजबूती मिली। तेजी से बढ़ते शहरी दबाव के बीच हरित क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनके कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियों में माना जाता है।

उनकी कार्यशैली की सबसे बड़ी विशेषता आम नागरिकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता है। राजस्व अदालतों में वर्षों से लंबित मामलों और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए उन्होंने विशेष पहल की। नियमित समीक्षा और निगरानी के माध्यम से ऐसे मामलों को प्राथमिकता दी गई, जिससे लोगों को शीघ्र राहत मिली और लंबित प्रकरणों का बोझ भी कम हुआ। इससे लोगों के बीच शासन व्यवस्था के प्रति विश्वास मजबूत हुआ।

जनसेवाओं को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहा। विभिन्न सरकारी सेवाओं की ट्रैकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ कर उन्होंने जवाबदेही बढ़ाने का प्रयास किया। इससे नागरिकों को समय पर सेवाएं प्राप्त होने लगीं और प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी कम हुई। राजधानी जैसे बड़े प्रशासनिक क्षेत्र में इस प्रकार की व्यवस्था आम नागरिकों के लिए काफी राहतकारी साबित हुई।

दिल्ली में भीषण गर्मी के दौरान दिल्ली सरकार के हीट वेव एक्शन प्लान को प्रभावी ढंग से लागू करने में भी लक्ष्य सिंघल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गर्मी से लोगों को राहत देने, जरूरी व्यवस्थाओं की निगरानी करने और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए उन्होंने लगातार समीक्षा की। यह उनकी सक्रिय और परिस्थिति-आधारित कार्यशैली को दर्शाता है।

विकास परियोजनाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण भी स्पष्ट और परिणामोन्मुख रहा है। विभिन्न विभागों के साथ नियमित बैठकें कर उन्होंने परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया। इससे कई विकास कार्यों में तेजी आई और परियोजनाएं तय समय के भीतर पूरी हो सकीं।

दक्षिण दिल्ली से पहले लक्ष्य सिंघल ने नुब्रा घाटी में उप मंडल दंडाधिकारी के रूप में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। सीमावर्ती और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्र में कार्य करना किसी भी अधिकारी के लिए चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन उन्होंने वहां भी अपनी नेतृत्व क्षमता और जमीनी कार्यशैली से सकारात्मक प्रभाव छोड़ा।

नुब्रा में उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने और वर्षों पुराने भूमि विवादों के समाधान की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। कई गांवों में पहली बार व्यवस्थित राजस्व अभिलेख तैयार कराने की प्रक्रिया शुरू कराई गई, जो प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था। इससे स्थानीय लोगों को भूमि संबंधी अधिकारों और सरकारी प्रक्रियाओं में स्पष्टता मिली।

सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण नुब्रा में सेना, वायुसेना और सीमा सड़क संगठन जैसी एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखना भी अत्यंत आवश्यक था। लक्ष्य सिंघल ने इन संस्थाओं के साथ प्रभावी सहयोग स्थापित कर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के बीच मजबूत तालमेल विकसित किया। यह समन्वय विकास कार्यों और आपदा प्रबंधन दोनों में उपयोगी साबित हुआ।

पर्यटन और स्थानीय विकास को बढ़ावा देने के लिए भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण पहलें कीं। हुंदर सैंड ड्यून्स क्षेत्र के पुनर्विकास, पर्यटन सुविधाओं के विस्तार और स्थानीय बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयासों ने पर्यटन गतिविधियों को नई दिशा दी। इससे स्थानीय लोगों की आजीविका और रोजगार के अवसरों में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी उनका कार्य उल्लेखनीय रहा। फ्लैश फ्लड, पुल दुर्घटनाओं और अन्य आपात परिस्थितियों के दौरान उन्होंने त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित किए। समय पर निर्णय और बेहतर समन्वय के कारण कई संवेदनशील परिस्थितियों को प्रभावी ढंग से संभाला जा सका।

लक्ष्य सिंघल की सबसे बड़ी ताकत उनकी जमीनी कार्यशैली मानी जाती है। वे केवल निर्देश देने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि नियमित फील्ड विजिट और जनसंवाद के माध्यम से वास्तविक परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि जहां भी उन्होंने कार्य किया, वहां शासन व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला।

जनप्रिय

सस्टेनेबल गवर्नेंस, जनभागीदारी और संवेदनशीलता की नई पहचान

अस्मिता लाल (बागपत)

बागपत की जिलाधिकारी अस्मिता लाल आज उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक परिदृश्य में एक विशिष्ट पहचान रखती हैं। उनका नाम सुनते ही एक ऐसी अधिकारी का चित्र उभरता है जो न केवल कागजों पर योजनाएँ बनाती हैं, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने के लिए स्वयं आगे आती हैं। वर्ष 2015 बैच की उत्तर प्रदेश कैडर की इस आईएएस अधिकारी ने जनभागीदारी, पर्यावरण संरक्षण और सस्टेनेबल विकास को अपने प्रशासन का केंद्र बनाकर एक नया और प्रेरणादायक मॉडल प्रस्तुत किया है।

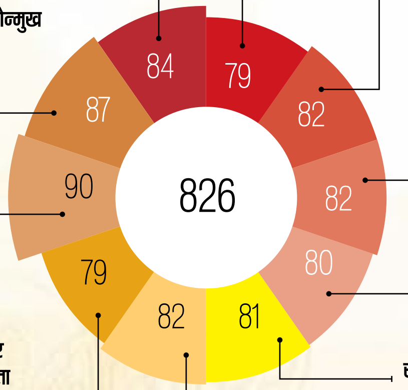

फेम इंडिया-एशिया पोस्ट के 'सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026' के वार्षिक सर्वे में प्रशासनिक अधिकारी अस्मिता लाल को 'जनप्रिय' श्रेणी में प्रमुख पाया गया है।

गाजियाबाद में मुख्य विकास अधिकारी के रूप में उनका कार्यकाल विशेष रूप से चर्चित रहा। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, बालिका शिक्षा, ग्रामीण स्वच्छता और पशु कल्याण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया। कोविड-19 महामारी के कठिन दौर में ऑक्सीजन उपलब्धता, जनजागरूकता और स्वास्थ्य सेवाओं के समन्वय में उनकी सक्रिय और निर्णायक भूमिका रही। गाजियाबाद को कोविड SOP के प्रभावी पालन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी उनके कार्यों को सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अडिशनल सीईओ के रूप में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।

अस्मिता लाल का वैचारिक और शैक्षणिक आधार अत्यंत सुदृढ़ रहा है। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। मनोविज्ञान की यह पृष्ठभूमि उन्हें मानवीय व्यवहार, सामाजिक संवेदनाओं और आम जन की मनःस्थिति को गहराई से समझने की क्षमता देती है, जो उनकी प्रशासनिक शैली में स्पष्ट रूप से झलकती है। इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पब्लिक पॉलिसी और मैनेजमेंट में परास्नातक किया। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से उनका अकादमिक जुड़ाव भी रहा, जिसने उनकी सामाजिक दृष्टि और नीति-निर्माण की समझ को और अधिक व्यापक एवं संवेदनशील बनाया।

छात्र जीवन से ही उनके भीतर समाज और जननीति को लेकर गहरी रुचि थी। उन्होंने प्रशासनिक सेवा को केवल एक प्रतिष्ठित करियर के रूप में नहीं, बल्कि समाज में स्थायी और सकारात्मक बदलाव लाने के साधन के रूप में अपनाया।

आईएएस सेवा में आने के बाद अस्मिता लाल ने अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया और हर जगह अपनी अलग छाप छोड़ी। उन्होंने अलीगढ़ में असिस्टेंट मैजिस्ट्रेट के रूप में जमीनी प्रशासन की बारीकियाँ सीखीं। मुरादाबाद में ज्वाइंट मैजिस्ट्रेट के तौर पर कार्य करने के बाद वे उत्तर प्रदेश सरकार में विशेष सचिव के पद पर भी रहीं।

जिलाधिकारी बागपत के रूप में अस्मिता लाल का कार्यकाल प्रशासनिक नवाचार और सस्टेनेबल गवर्नेंस का पर्याय बन चुका है। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि यदि सरकारी योजनाओं में जनभागीदारी और संवेदनशीलता जुड़ जाए, तो वे महज आदेश नहीं, सामाजिक आंदोलन का रूप ले लेती हैं।

उनकी सबसे चर्चित और अनूठी पहल है — "बर्तन बैंक"। इस पहल के तहत सामुदायिक और पारिवारिक आयोजनों में स्टील के बर्तनों की निःशुल्क व्यवस्था की गई, जिससे सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के उपयोग पर प्रभावी रोक लगी। पंचायतों और स्वयं सहायता समूहों को इसके संचालन से जोड़कर इसे एक जनभागीदारी आधारित मॉडल बनाया गया। इस पहल का सबसे बड़ा लाभ गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को मिला, जिन्हें समारोहों में होने वाले अनावश्यक खर्च से राहत मिली। साथ ही, गाँवों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता का एक नया वातावरण बना।

"ज़ीरो वेस्ट महोत्सव" उनकी दूरदर्शी सोच का एक और जीवंत उदाहरण है। इस पहल के अंतर्गत कचरे को संसाधन में बदलने की अवधारणा को व्यावहारिक रूप दिया गया। पुराने चप्पलों से चटाइयाँ, फूलों से अगरबत्ती और प्लास्टिक अपशिष्ट से उपयोगी वस्तुएँ तैयार कर "वेस्ट टू वेल्थ" के विचार को जमीनी स्तर पर साकार किया गया। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न हुए।

अस्मिता लाल की सबसे अभिनव और व्यापक चर्चा पाने वाली पहलों में "पुरा महादेव शिवरात्रि ज़ीरो वेस्ट मॉडल" भी शामिल है। धार्मिक आयोजनों में भारी मात्रा में उत्पन्न होने वाले कचरे को उन्होंने सर्कुलर आर्थिक मॉडल में परिवर्तित करने का सफल प्रयोग किया। इस अभियान में 450 किलोग्राम से अधिक फूल, लगभग एक टन जैविक कचरा और 700 किलोग्राम से अधिक प्लास्टिक का पुनः उपयोग किया गया। पूजा सामग्री को गौशालाओं तक पहुँचाकर उन्होंने धार्मिक आस्था और पर्यावरण चेतना के बीच एक सेतु का निर्माण किया — यह संदेश देते हुए कि आस्था और पर्यावरण एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं।

महिलाओं के स्वास्थ्य और सम्मान की दिशा में उनकी "नीरा" पहल विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही। यूनिसेफ और रेड क्रॉस के सहयोग से शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट के तहत महिलाओं के लिए पुनः उपयोगी सूती पैड्स को बढ़ावा दिया गया। इससे एक ओर प्लास्टिक अपशिष्ट में कमी आई और दूसरी ओर महिलाओं की गरिमा व स्वास्थ्य से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। स्वयं सहायता समूहों को इस पहल से जोड़कर महिलाओं को आजीविका के नए अवसर भी प्रदान किए गए।

अस्मिता लाल की प्रशासनिक शैली का सबसे मानवीय और प्रेरणादायक पहलू उनकी असाधारण संवेदनशीलता है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से नेत्रदान का संकल्प लेकर उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी जिलाधिकारी होने का गौरव प्राप्त किया, जिन्होंने अंगदान के प्रति समाज में व्यापक जागरूकता फैलाने की पहल की। वे फाइलों और बैठक कक्षों से निकलकर जनता के बीच जाती हैं, उनकी समस्याएँ सुनती हैं और मौके पर ही समाधान निकालने का प्रयास करती हैं। किसानों के बीच खतौनी वितरण केंद्र पर स्वयं बैठकर दस्तावेज़ वितरित करना उनकी इसी जनसरोकार वाली कार्यशैली का जीता-जागता प्रमाण है।

आज अस्मिता लाल उन युवा प्रशासनिक अधिकारियों में अग्रणी मानी जाती हैं, जिन्होंने यह साबित किया है कि वास्तविक प्रशासनिक उत्कृष्टता केवल योजनाओं के क्रियान्वयन में नहीं, बल्कि समाज में स्थायी और सार्थक बदलाव लाने में निहित है। बागपत में उनके कार्यों ने सस्टेनेबल, इनोवेटिव और पीपुल-सेंट्रिक गवर्नेंस का एक ठोस और अनुकरणीय मॉडल खड़ा किया है। उनकी यह प्रशासनिक यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो विकास, पर्यावरण और मानवीय संवेदनाओं के बीच संतुलन साधते हुए समाज को एक नई, बेहतर और टिकाऊ दिशा की ओर ले जाए।

उद्देश्यपूर्ण

विकास, नवाचार और जनविश्वास से नई पहचान गढ़ते अधिकारी

आदित्य रंजन (धनबाद)

2015 बैच के आईएएस अधिकारी आदित्य रंजन, जो इससे पहले सूचना प्रौद्योगिकी निदेशक के रूप में कार्यरत थे, आज झारखंड के उन युवा और ऊर्जावान प्रशासनिक अधिकारियों में गिने जाते हैं जिन्होंने प्रशासन को केवल सरकारी व्यवस्था तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जनभागीदारी, तकनीकी नवाचार और सतत विकास का माध्यम बना दिया। वर्तमान में धनबाद के उपायुक्त के रूप में कार्यरत आदित्य रंजन ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व, पारदर्शी कार्यशैली और जनकेंद्रित सोच से जिले के प्रशासनिक परिदृश्य को नई दिशा दी है।

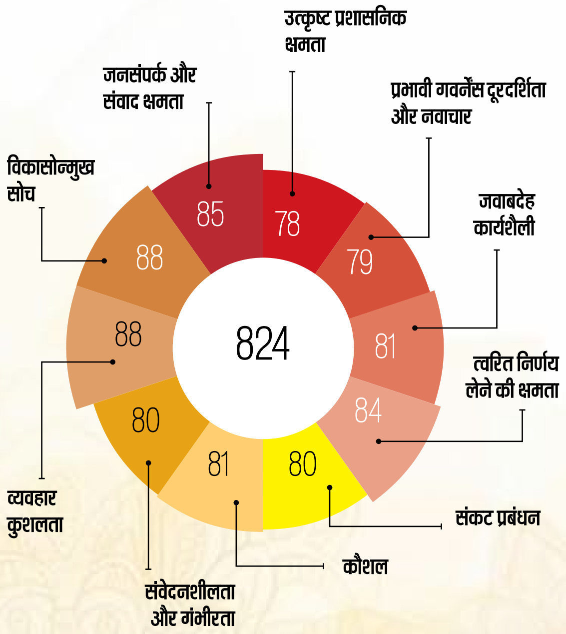

फेम इंडिया-एशिया पोस्ट के 'सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026' के वार्षिक सर्वे में प्रशासनिक अधिकारी आदित्य रंजन को 'उद्देश्यपूर्ण' श्रेणी में प्रमुख पाया गया है।

उनकी प्रशासनिक सोच का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वे विकास को केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं मानते, बल्कि उसे सामाजिक परिवर्तन का माध्यम समझते हैं। जनसहभागिता आधारित प्रशासन उनकी पहचान बन चुका है — वे जनता से संवाद को प्रशासन की सबसे बड़ी शक्ति मानते हैं। पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी नवाचार, युवाओं का सशक्तिकरण, महिला भागीदारी और जनसहयोग — इन सभी तत्वों को साथ लेकर चलने की उनकी शैली उन्हें विशिष्ट बनाती है। आदित्य रंजन उन प्रशासनिक अधिकारियों में शामिल हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि यदि इच्छाशक्ति स्पष्ट हो और दृष्टिकोण जनकेंद्रित हो, तो प्रशासन समाज में व्यापक और स्थायी परिवर्तन ला सकता है। आज धनबाद में विकास, पारदर्शिता और आधुनिक प्रशासन की जो नई पहचान बन रही है, उसमें आदित्य रंजन की निर्णायक भूमिका स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।

धनबाद, झारखंड का एक प्रमुख औद्योगिक और खनन-प्रधान जिला है, जहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 26 लाख से अधिक है। ऐसे जटिल और बहुआयामी चुनौतियों वाले जिले में प्रशासनिक जिम्मेदारी सँभालना स्वयं में एक बड़ी परीक्षा होती है। एक ओर शहरीकरण का दबाव, दूसरी ओर पर्यावरणीय चुनौतियाँ, जल संकट, विस्थापन, रोजगार और आधारभूत संरचना की आवश्यकताएं — इन सबके बीच आदित्य रंजन ने विकास और मानवीय संवेदनशीलता के बीच संतुलन स्थापित करने का उल्लेखनीय प्रयास किया है।

आदित्य रंजन की कार्यशैली का सबसे प्रमुख पहलू है दूरगामी सोच। वे केवल तात्कालिक समस्याओं के समाधान तक सीमित नहीं रहते, बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को आकार देते हैं। यही कारण है कि उनके नेतृत्व में धनबाद प्रशासन ने जल संरक्षण, तकनीकी सहयोग, शिक्षा, कौशल विकास और नागरिक सुविधाओं के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण पहलें शुरू कीं। जल सुरक्षा के क्षेत्र में उनकी "जल सेवा" पहल विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है, जिसमें जलाशयों के पुनर्जीवन, भूजल पुनर्भरण और सतत जल प्रबंधन पर केंद्रित व्यापक अभियान चलाया गया। इस पहल का उद्देश्य न केवल सभी के लिए 24 घंटे शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, और अन्य वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करना है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित जल संरचना भी तैयार करना है।

आदित्य रंजन ने तकनीक और शोध संस्थानों के सहयोग को भी प्रशासनिक विकास का महत्वपूर्ण आधार बनाया। आईआईटी (पूर्ववर्ती आईएसएम) धनबाद ने उन्हें धनबाद के 54वें उपायुक्त के रूप में उनकी साहसिक और पारदर्शी कार्यशैली के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ-साथ समाज के प्रति संवेदनशीलता उतनी ही आवश्यक है। सेवा, विनम्रता और दृढ़ता जैसे मूल्य जीवन की असली पूंजी हैं। प्रशासन और शैक्षणिक संस्थानों के बीच ऐसा समन्वय उनके आधुनिक प्रशासनिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। इस साझेदारी के माध्यम से जल प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, उद्यमिता और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में कई योजनाओं को गति मिली।

युवा सशक्तिकरण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भी उन्होंने उल्लेखनीय प्रयास किए। अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र से जुड़े कार्यक्रमों को प्रोत्साहित कर उन्होंने जिले के युवाओं में उद्यमिता और नवाचार की संस्कृति विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए। उनका मानना है कि किसी भी जिले का वास्तविक विकास तभी संभव है जब उसके युवा आत्मनिर्भर और सक्षम बनें।

धनबाद के झरिया क्षेत्र में पुनर्वास और विकास कार्यों को नई गति देना उनके प्रशासनिक कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। झरिया कोलफील्ड में लगभग दो सौ वर्षों के खनन इतिहास के कारण भूमिगत आग और भू-धंसान जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जिनसे वहाँ के लोगों का जीवन और स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है।

आदित्य रंजन ने झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण की प्रगति रिपोर्ट स्वयं प्रस्तुत की, जिसमें बेलगढ़िया और करमाटांड टाउनशिप में आधारभूत संरचना उन्नयन और सामुदायिक विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। बेलगढ़िया टाउनशिप में पूर्ण हो चुकी और आगामी परियोजनाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि पुनर्वास तभी पूर्ण माना जाएगा जब नई टाउनशिप में सड़क, परिवहन, अस्पताल, विद्यालय और पुलिस थाने जैसी सभी आवश्यक नागरिक सुविधाएं पूरी तरह क्रियाशील हो जाएं। फिलहाल, उन्होंने बेलगढ़िया में स्किल डेवलपमेंट और स्वरोजगार की कई योजनाएं शुरू करवायी हैं।

आदित्य रंजन के प्रयासों और बीसीसीएल की सीएसआर पहल के तहत बेलगढ़िया टाउनशिप में स्थानीय बेरोजगारों को चिन्हित कर पचास ई-रिक्शा बांटे गये हैं। इस योजना के अंतर्गत टाउनशिप में पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देंगे। पुनर्वास के साथ-साथ आजीविका सृजन पर भी विशेष ध्यान दिया गया — महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने, हस्तशिल्प गतिविधियों को पुनर्जीवित करने और स्थानीय व्यापारिक अवसरों के विकास जैसी पहलों ने विस्थापित परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

धनबाद जैसे औद्योगिक और घनी आबादी वाले जिले में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां अधिक जटिल हैं। इसे ध्यान में रखते हुए आदित्य रंजन ने स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और विभिन्न संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया। डिजिटल मॉनिटरिंग और नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी की गई।

आदित्य रंजन की दूरदृष्टि केवल वर्तमान तक सीमित नहीं है। उनके नेतृत्व में धनबाद में अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की आधारशिला रखी जा रही है — गया पुल, मतकुरिया फ्लाईओवर, महिला तकनीकी विश्वविद्यालय, नॉलेज सिटी, केंद्रीय विद्यालय परिसर, कृषि प्रशिक्षण केंद्र और आईआईटी (पूर्ववर्ती आईएसएम) धनबाद के दूसरे परिसर जैसी परियोजनाएं आने वाले समय में धनबाद को शिक्षा, नवाचार और आधुनिक आधारभूत संरचना के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित कर सकती हैं।

अग्रदूत

दूरदर्शी नेतृत्व, जन-केंद्रित प्रशासन और समावेशी विकास की मिसाल

कोमल मित्तल (मोहाली)

कोमल मित्तल की प्रशासनिक यात्रा में अनुभव की गहराई और विविधता दोनों हैं। उन्होंने मुकेरियां में उप-मंडल मजिस्ट्रेट के रूप में अपनी सेवा की शुरुआत की और जमीनी प्रशासन की बारीकियाँ बारीकी से सीखीं। यहीं से उनकी जनकेंद्रित कार्यशैली की नींव पड़ी, जो आगे चलकर उनकी प्रशासनिक पहचान का आधार बनी। इसके बाद मोहाली में ही उन्होंने कई पदों पर रहकर शहरी शासन, नागरिक सुधार और नियोजित विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए।

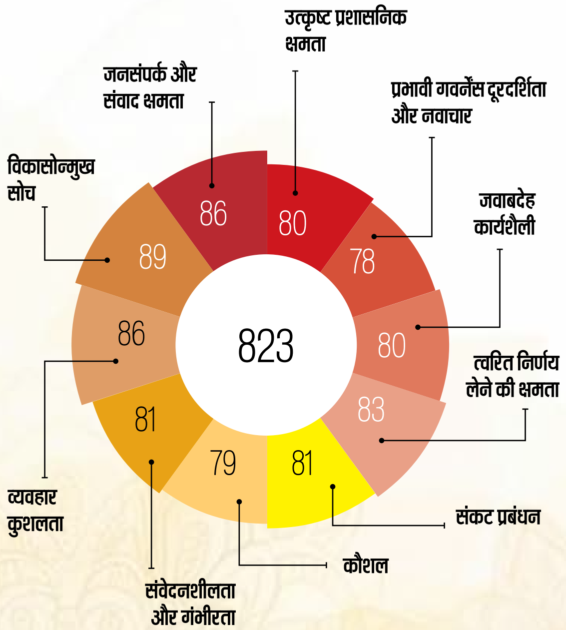

फेम इंडिया-एशिया पोस्ट के 'सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026' के वार्षिक सर्वे में प्रशासनिक अधिकारी कोमल मित्तल को 'अग्रदूत' श्रेणी में प्रमुख पाया गया है।

कोमल मित्तल की प्रशासनिक यात्रा यह सिद्ध करती है कि जब दक्षता, करुणा, नवाचार और नैतिकता एकसाथ आती हैं, तो प्रशासन केवल एक तंत्र नहीं, जनजीवन का स्थायी और विश्वसनीय हिस्सा बन जाता है। उनके नेतृत्व में शिक्षा, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, समावेशी विकास और नागरिककेंद्रित शासन के क्षेत्रों में जो परिवर्तन आए हैं, वे दीर्घकालिक, प्रेरणादायक और अनुकरणीय हैं। आज कोमल मित्तल उन प्रशासनिक अधिकारियों की अग्रिम पंक्ति में खड़ी हैं, जो यह विश्वास दिलाती हैं कि सार्वजनिक सेवा अभी भी सच्चे और गहरे अर्थों में समाज की सेवा कर सकती है — और यही उनकी सबसे बड़ी, सबसे स्थायी उपलब्धि है।

पंजाब के साहबजादा अजित सिंह नगर यानी मोहाली की डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल उन विरले प्रशासनिक अधिकारियों में से एक हैं, जिन्होंने सरकारी सेवा को केवल एक पद नहीं, बल्कि समाज को बदलने का एक सशक्त माध्यम बनाया है। 2014 बैच की पंजाब कैडर की आईएएस अधिकारी कोमल मित्तल अपनी दूरदर्शी सोच, पारदर्शी कार्यशैली और जनकेंद्रित प्रशासन के लिए पंजाब के सबसे सम्मानित और गतिशील प्रशासकों में गिनी जाती हैं। जिला प्रशासन, शिक्षा, सामाजिक कल्याण, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास जैसे अनेक क्षेत्रों में उनके योगदान ने हजारों जीवनों को प्रभावित किया है और सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता का एक नया मापदंड स्थापित किया है।

अमृतसर नगर निगम में अतिरिक्त आयुक्त के पद पर रहते हुए उन्होंने नगरीय प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनोन्मुखी बनाने की दिशा में ठोस प्रयास किए। पंजाब सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में उन्होंने नीति-निर्माण और प्रशासनिक सुधारों में सक्रिय योगदान दिया। होशियारपुर की डिप्टी कमिश्नर के रूप में उनका कार्यकाल विशेष रूप से चर्चित और उपलब्धिपूर्ण रहा, जहाँ उनकी अनेक अभिनव पहलों ने जिले को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। वर्तमान में वह मोहाली की डिप्टी कमिश्नर के रूप में प्रशासनिक उत्कृष्टता के नए आयाम स्थापित कर रही हैं।

कोमल मित्तल का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षा ही वह आधार है जिस पर समाज का स्थायी और समावेशी विकास संभव है। इसी सोच को जमीन पर उतारते हुए उन्होंने होशियारपुर में पंजाब की पहली डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की। यह पहल न केवल डिजिटल शिक्षा और ज्ञान तक पहुँच को सुलभ बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था, बल्कि युवाओं को आधुनिक तकनीक और सूचना की दुनिया से जोड़ने का एक प्रभावशाली माध्यम भी बना। ग्रामीण और शहरी, दोनों वर्गों के विद्यार्थियों को इस पहल से लाभ मिला। होशियारपुर जिला डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में एक अनुकरणीय उदाहरण बन गया, जिसे अन्य जिलों ने भी अपनाने की प्रेरणा ली।

पर्यावरण और कृषि के प्रति उनकी गहरी संवेदनशीलता उनकी प्रशासनिक पहचान का एक महत्वपूर्ण और विशिष्ट हिस्सा है। होशियारपुर में उन्होंने विद्यालयों में पर्यावरण और सस्टेनेबिलिटी से जुड़ी पहलों को बड़े पैमाने पर लागू किया। छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने और हरित जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। इन प्रयासों के फलस्वरूप होशियारपुर को प्रतिष्ठित "बेस्ट ग्रीन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड" से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार न केवल उनके अथक प्रयासों की स्वीकृति था, बल्कि यह संदेश भी था कि पर्यावरण चेतना को यदि शिक्षा और प्रशासन से जोड़ा जाए तो परिवर्तन न केवल संभव है, बल्कि स्थायी भी होता है।

टिकाऊ कृषि की दिशा में भी उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उन्होंने होशियारपुर जिले में फसल विविधीकरण और मूँगफली की खेती को बढ़ावा देकर किसानों को परंपरागत और एकरस फसल चक्र से बाहर निकलने का अवसर दिया। इस पहल ने किसानों की आजीविका को अधिक सुरक्षित और लाभकारी बनाने के साथ-साथ भूमि की दीर्घकालिक उत्पादकता को भी सुनिश्चित किया।

कोमल मित्तल का यह दृढ़ मानना है कि समाज का वास्तविक विकास तब तक अधूरा है जब तक महिलाएँ और बालिकाएँ उसमें समान और सक्रिय भागीदार न हों। इसी दृष्टिकोण के साथ उन्होंने बालिकाओं के लिए कौशल विकास, आत्मविश्वास निर्माण और नेतृत्व क्षमता को केंद्र में रखकर प्रशिक्षण एवं सशक्तिकरण शिविरों का बड़े पैमाने पर आयोजन किया। इन शिविरों ने न केवल लड़कियों में आत्मनिर्भरता की भावना जगाई, बल्कि उन्हें यह विश्वास भी दिलाया कि उनके सपने बड़े हो सकते हैं और उन्हें साकार करने की शक्ति उनके भीतर ही है।

समावेशी विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनकी "विंग्स" पहल में सबसे स्पष्ट और मार्मिक रूप से दिखती है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से दिव्यांग युवाओं के लिए बनाया गया, ताकि उनकी छुपी हुई प्रतिभा को पहचाना जा सके और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। इस पहल ने यह महत्वपूर्ण संदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशिष्ट क्षमता होती है और प्रशासन का दायित्व है कि वह हर नागरिक को उड़ान भरने के लिए आवश्यक वातावरण और अवसर उपलब्ध कराए।

कोमल मित्तल ने चुनाव प्रबंधन में भी अपनी प्रशासनिक कुशलता और निष्पक्षता का प्रमाण दिया। उनके कुशल नेतृत्व और सूक्ष्म प्रबंधन को देखते हुए पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें "बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर अवार्ड" से सम्मानित किया। यह पुरस्कार उनके पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी चुनाव प्रबंधन का प्रमाण है — एक ऐसा योगदान जो लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

मोहाली में डिप्टी कमिश्नर के रूप में उन्होंने नशे की गंभीर समस्या से लड़ने के लिए युवाओं को केंद्र में रखकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाए। उनका स्पष्ट मानना है कि यदि युवाओं को सही दिशा, उचित अवसर और सकारात्मक वातावरण मिले, तो वे नशे की दलदल से न केवल बाहर निकल सकते हैं, बल्कि समाज के निर्माण में भी अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। उनके इन प्रयासों ने जिले में एक नई उम्मीद और सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया है।

प्रशंसनीय

संघर्ष के बीच संवेदनशीलता, नवाचार और अदम्य प्रशासनिक संकल्प की कहानी

धरुन कुमार एस

(चुराचंदपुर)

मणिपुर के चुराचंदपुर के उपायुक्त धरुन कुमार एस उन अधिकारियों में से एक हैं जिनकी असली परीक्षा किसी शांत और सामान्य जिले में नहीं, बल्कि जातीय हिंसा और विस्थापन की पीड़ा से जूझते एक अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में हुई है। वर्ष 2019 बैच के मणिपुर कैडर के इस आईएएस अधिकारी ने प्रशासन की परिभाषा को एक नई गहराई और एक नया अर्थ दिया है — यह सिद्ध करते हुए कि जब परिस्थितियाँ सबसे कठिन हों, तभी एक सच्चे लोकसेवक की असली पहचान होती है।

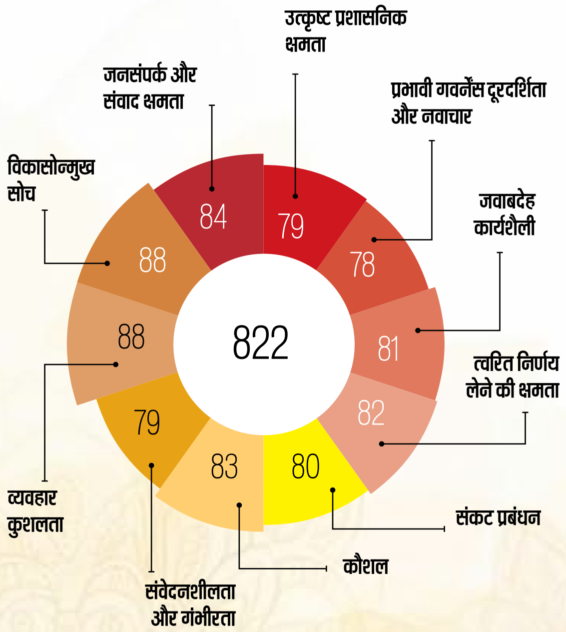

फेम इंडिया-एशिया पोस्ट के 'सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026' के वार्षिक सर्वे में प्रशासनिक अधिकारी धरुन कुमार एस को 'प्रशंसनीय' श्रेणी में प्रमुख पाया गया है।

धरुन कुमार एस की प्रशासनिक यात्रा यह सिद्ध करती है कि सच्चा नेतृत्व तब परखा जाता है जब परिस्थितियाँ सबसे विकट हों। एक युवा अभियंता से लोक प्रशासन और विधि के जानकार बनने तक, और फिर एक ऐसे जिले के कप्तान के रूप में जहाँ संघर्ष, विस्थापन और पुनर्निर्माण एक साथ चल रहे हों — यह यात्रा वास्तव में असाधारण है। उनकी संवेदनशीलता, उनका साहस और उनकी जनकेंद्रित सोच यह विश्वास दिलाती है कि संकट के सबसे गहरे अंधेरे में भी प्रशासन मानवता का उजला चेहरा बन सकता है — और यही उनकी सबसे बड़ी और स्थायी पहचान है।

तमिलनाडु में 3 जून 1994 को जन्मे धरुन कुमार एस की शैक्षणिक यात्रा विविधता और गहराई दोनों से भरी हुई है। उन्होंने वर्ष 2015 में इरोड स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी से विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। तकनीकी शिक्षा से अपनी यात्रा आरंभ करने के बाद उन्होंने वर्ष 2021 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से लोक प्रबंधन में परास्नातक किया और वर्ष 2022 में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से विधि में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। अभियांत्रिकी, सार्वजनिक नीति और विधि — तीनों क्षेत्रों की यह त्रिवेणी उनकी प्रशासनिक सोच को एक विशेष बहुआयामी दृष्टि देती है, जो उनके प्रत्येक निर्णय और कार्य में स्पष्ट रूप से झलकती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण कर मणिपुर कैडर में आने के बाद धरुन कुमार एस ने चुराचंदपुर जिले में ही विभिन्न क्षमताओं में अपनी सेवाएँ दीं। उन्होंने सहायक आयुक्त, खंड विकास अधिकारी लामका तथा लामका दक्षिण और उप-मंडल अधिकारी चुराचंदपुर के रूप में कार्य किया। इन विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने जिले की भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जटिलताओं को बारीकी से समझा। 12 जून 2023 को वे चुराचंदपुर के जिला कलेक्टर एवं उपायुक्त के पद पर नियुक्त हुए — और यह नियुक्ति ऐसे समय हुई जब मणिपुर जातीय हिंसा की भीषण आग में जल रहा था। जो जिला उन्होंने वर्षों से विभिन्न क्षमताओं में सेवा देते हुए गहराई से जाना था, उसी का भार अब उनके कंधों पर था — और उन्होंने यह दायित्व पूरी निष्ठा और साहस के साथ उठाया।

मई 2023 में मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा ने चुराचंदपुर जिले को सबसे अधिक प्रभावित किया। हजारों परिवार अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए और राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी। इस असाधारण और हृदयविदारक संकट में धरुन कुमार एस ने जो प्रशासनिक संवेदनशीलता प्रदर्शित की, वह न केवल उल्लेखनीय है बल्कि मणिपुर के प्रशासनिक इतिहास में अभूतपूर्व भी है। वे राज्य के पहले उपायुक्त बने जिन्होंने आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के राहत शिविर में एक रात बिताई। अतिरिक्त उपायुक्त थांगबोई गांगटे के साथ वे पुराने गेलमोल गाँव के राहत शिविर में रुके, शिविरवासियों के साथ भोजन किया और उन्हें कंबल सहित गर्म वस्त्र वितरित किए। यह कोई सांकेतिक दौरा नहीं था — यह एक संवेदनशील प्रशासक का अपने लोगों के दर्द को सच्चे मन से महसूस करने और उनके साथ खड़े रहने का प्रयास था। शिविरवासियों और स्वयंसेवकों ने इस अप्रत्याशित और मार्मिक भाव-भंगिमा के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की।

इसके साथ ही उन्होंने राहत कार्यों को जिला मुख्यालय की परिधि से आगे बढ़ाते हुए संगाईकोट और सैकोट खंड के दूरदराज के शिविरों तक विस्तारित किया। उनकी सक्रिय देखरेख में जिला प्रशासन ने स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से विभिन्न राहत शिविरों में विस्थापितों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया, ताकि वे स्वतंत्र रूप से आजीविका अर्जित करने में सक्षम हो सकें। जिले के इक्यासी राहत शिविरों में पंद्रह हजार से भी अधिक विस्थापितों के बीच खेल सामग्री के वितरण से लेकर उनके बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने तक — हर मोर्चे पर उनकी उपस्थिति और सक्रियता दिखी। हिंसा प्रभावित परिवारों के उन बच्चों को, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, सम्मानित करने की पहल यह दर्शाती है कि गहरे संकट के बीच भी उनका प्रशासन भविष्य की उम्मीद की लौ जलाए रखने में विश्वास रखता है।

धरुन कुमार एस की सबसे गौरवशाली उपलब्धियों में से एक वह है जो उन्होंने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान की। जब हजारों विस्थापित नागरिक अपने मताधिकार से वंचित होने की कगार पर थे, तब जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में उन्होंने अभूतपूर्व प्रयास किए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि जो लोग हिंसा के कारण अपने घरों से दूर राहत शिविरों में जी रहे थे, वे भी लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता दर्ज करा सकें। मतदाता भागीदारी बढ़ाने और विस्थापितों को मतदान का अवसर दिलाने के इन असाधारण प्रयासों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पंद्रहवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर "श्रेष्ठ निर्वाचन प्रचलन पुरस्कार" से सम्मानित किया। यह पुरस्कार इस बात का जीवंत प्रमाण है कि यदि अधिकारी में इच्छाशक्ति और संवेदनशीलता हो, तो संघर्षग्रस्त क्षेत्र में भी लोकतंत्र की जड़ें मजबूती से जमाई जा सकती हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उनके कार्यकाल में उल्लेखनीय प्रगति हुई। उनके प्रशासनिक हस्तक्षेप के कारण स्कूल से विद्यार्थियों के बाहर होने की दर में उल्लेखनीय कमी आई। हेंगलेप में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन और उद्घाटन उनके कार्यकाल की एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि रही, जिससे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच पहले से कहीं बेहतर हुई।

जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर उन्होंने युवाओं को उन आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया जो भारत के स्वाधीनता संग्राम में अग्रिम पंक्ति में खड़े थे। भगवान बिरसा मुंडा की डेढ़ सौवीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में चित्रकला, निबंध, कविता, प्रश्नोत्तरी और लोकनृत्य जैसी प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से उन्होंने जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहित करने का सार्थक प्रयास किया।

आइकॉन

संवेदनशील और जन-केंद्रित प्रशासन की सशक्त पहचान

रोसेटा मैरी कुर्बाह

(ईस्ट खासी हिल्स)

भारतीय प्रशासनिक सेवा में कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जिनकी पहचान केवल प्रशासनिक पदों से नहीं, बल्कि जनता के साथ उनके मानवीय जुड़ाव और जमीनी कार्यशैली से बनती है। असम-मेघालय कैडर की वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रोजेटा मेरी कुर्बाह उन्हीं अधिकारियों में शामिल हैं। राज्य सिविल सेवा से पदोन्नत होकर आईएएस में पहुंचीं रोजेटा मेरी कुर्बाह ने अपने लंबे प्रशासनिक अनुभव, शांत नेतृत्व और संवेदनशील कार्यशैली के माध्यम से मेघालय प्रशासन में एक अलग स्थान बनाया है।

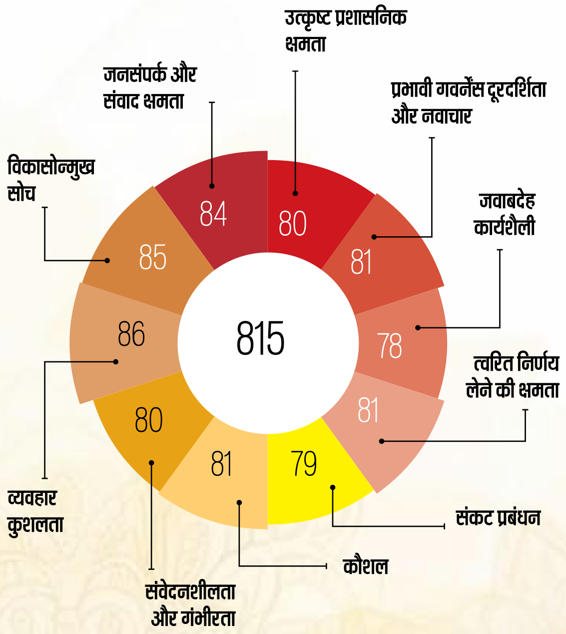

फेम इंडिया-एशिया पोस्ट के 'सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026' के वार्षिक सर्वे में प्रशासनिक अधिकारी रोसेटा मैरी कुर्बाह को 'आइकॉन' श्रेणी में प्रमुख पाया गया है।

रोजेटा मेरी कुर्बाह की यात्रा यह दर्शाती है कि प्रशासनिक उत्कृष्टता केवल बड़े पदों या चर्चित अभियानों से नहीं, बल्कि निरंतर जनसेवा, संवेदनशील नेतृत्व और जमीनी अनुभव से निर्मित होती है। राज्य सिविल सेवा से आईएएस तक का उनका सफर अनेक महिला अधिकारियों और युवा प्रशासकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने यह साबित किया है कि यदि प्रशासन में संवेदनशीलता, समर्पण और दूरदर्शिता हो तो शासन वास्तव में लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। मेघालय के प्रशासनिक इतिहास में उनका नाम एक ऐसी अधिकारी के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने पद की शक्ति से अधिक जनता के विश्वास को महत्व दिया।

वर्तमान में रोसेटा मैरी कुर्बाह ईस्ट खासी हिल्स जिले की उपायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। शिलॉन्ग जैसे प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जिले में उनका कार्यकाल सुशासन, चुनाव प्रबंधन और जनसहभागिता आधारित प्रशासन का उदाहरण माना जा रहा है।

सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार उनका आईएएस वर्ष 2010 बैच से संबंध है। राज्य सेवा में लंबे अनुभव ने उन्हें प्रशासन की जमीनी चुनौतियों को गहराई से समझने का अवसर दिया। यही कारण है कि उनकी कार्यशैली में व्यावहारिकता, सामुदायिक संवाद और स्थानीय परिस्थितियों की समझ स्पष्ट दिखाई देती है।

उन्होंने अपने प्रशासनिक करियर में मेघालय सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों में जिम्मेदारियां निभाईं। वे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सचिव रहीं, जहां उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया। इसके अलावा वे स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा सर्व शिक्षा अभियान (SSA) से भी जुड़ी रहीं। शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़े विभागों में उनकी भूमिका ने उन्हें समाज के विभिन्न वर्गों के साथ प्रत्यक्ष रूप से काम करने का अवसर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं, शिक्षा की चुनौतियों और स्वास्थ्य सेवाओं की सीमाओं को समझते हुए उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया।

मार्च 2023 में उन्हें ईस्ट खासी हिल्स जिले का उपायुक्त नियुक्त किया गया। ईस्ट खासी हिल्स मेघालय का सबसे महत्वपूर्ण जिला माना जाता है क्योंकि राज्य की राजधानी शिलॉन्ग इसी जिले में स्थित है। प्रशासनिक दृष्टि से यह जिला अत्यंत संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण माना जाता है। यहां राजनीतिक गतिविधियां, शहरी विकास, पर्यटन, शिक्षा संस्थान और सामाजिक विविधता प्रशासनिक जिम्मेदारियों को और अधिक जटिल बनाते हैं। ऐसे जिले में उपायुक्त के रूप में प्रभावी नेतृत्व देना किसी भी अधिकारी के लिए बड़ी चुनौती होती है।

रोज़ेटा मेरी कुर्बाह ने इस चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी को संतुलित और व्यवस्थित तरीके से निभाया। उनकी प्रशासनिक शैली की सबसे बड़ी विशेषता जनता के साथ संवाद और समन्वय आधारित कार्यप्रणाली रही। शिलॉन्ग और आसपास के क्षेत्रों में सामुदायिक संगठनों, स्थानीय निकायों और नागरिक समूहों के साथ उन्होंने सहयोगात्मक संबंध बनाए। यही कारण है कि स्थानीय स्तर पर उन्हें एक संवेदनशील और सुलभ अधिकारी के रूप में देखा गया। आम लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता ने उन्हें "जन-प्रिय DC" जैसी पहचान दिलाई, जो किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के लिए सबसे बड़ा सामाजिक सम्मान माना जा सकता है।

चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में उनके नेतृत्व को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिली। वर्ष 2026 में ईस्ट खासी हिल्स जिले को "Best Election District Award" से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार चुनाव प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में यह सम्मान प्रदान किया गया। यह उपलब्धि इसलिए महत्वपूर्ण मानी गई क्योंकि ईस्ट खासी हिल्स जैसे भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि से जटिल जिले में चुनाव संचालन एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती होता है।

रोज़ेटा मेरी कुर्बाह के नेतृत्व में मतदान केंद्रों की सुव्यवस्थित तैयारी, चुनाव कर्मियों की प्रभावी तैनाती और अंतिम छोर तक लॉजिस्टिक्स पहुंचाने का सफल मॉडल विकसित किया गया। बहुभाषी और विविध सामाजिक समूहों वाले जिले में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित चुनाव कराना प्रशासनिक दक्षता का बड़ा उदाहरण माना गया। इस उपलब्धि ने यह सिद्ध किया कि योजनाबद्ध रणनीति, टीमवर्क और सूक्ष्म प्रशासनिक निगरानी के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है।

उन्होंने मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता दी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उन्होंने ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन वैन को लॉन्च किया ताकि मतदाताओं को चुनाव प्रक्रिया और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के प्रति जागरूक किया जा सके। यह पहल चुनावी पारदर्शिता और मतदाता विश्वास बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी गई।

स्वास्थ्य और सामुदायिक विकास के क्षेत्र में भी उनकी सक्रिय भूमिका रही है। नवंबर 2023 में उन्होंने ईस्ट खासी हिल्स में "SAANS" कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य बच्चों के स्वास्थ्य और विशेष रूप से निमोनिया जैसी बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इसके अतिरिक्त वे आपदा प्रबंधन और पूर्व तैयारी संबंधी गतिविधियों में भी सक्रिय रहीं। वर्ष 2026 में मानसून पूर्व तैयारियों को लेकर आयोजित जिला स्तरीय बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया।

रोज़ेटा मेरी कुर्बाह की प्रशासनिक शैली केवल सरकारी आदेशों तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसमें मानवीय संवेदनशीलता का स्पष्ट समावेश दिखाई देता है। वे सामुदायिक भागीदारी को प्रशासन का महत्वपूर्ण आधार मानती हैं। पूर्वोत्तर भारत जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विविध क्षेत्र में यह दृष्टिकोण अत्यंत प्रभावी माना जाता है। स्थानीय समुदायों के साथ विश्वास आधारित संबंध बनाना उनकी प्रशासनिक सफलता का प्रमुख कारण रहा है।

उनकी कार्यशैली में शांति, संतुलन और संवाद की विशेष भूमिका दिखाई देती है। वे प्रशासनिक निर्णयों में कठोरता के बजाय सहभागिता और समझदारी को प्राथमिकता देती हैं। यही कारण है कि वे केवल एक प्रशासनिक अधिकारी नहीं बल्कि जनता और शासन के बीच विश्वास का सेतु बनकर उभरी हैं।

कुशल प्रबंधक

संघर्ष, साधना और सेवा की असाधारण प्रशासनिक यात्रा

विशाल मिश्रा (रुद्र प्रयाग)

उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी विशाल मिश्र उन प्रशासकों में से हैं जिनकी कहानी केवल एक सफल अधिकारी की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने सीमित साधनों, कठिन परिस्थितियों और निरंतर असफलताओं को अपनी ताकत बनाया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जन्मे और अपनी प्रारंभिक शिक्षा फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ में पाने वाले विशाल की जीवन यात्रा यह सिद्ध करती है कि दृढ़ संकल्प और परिश्रम से हर लक्ष्य संभव है।

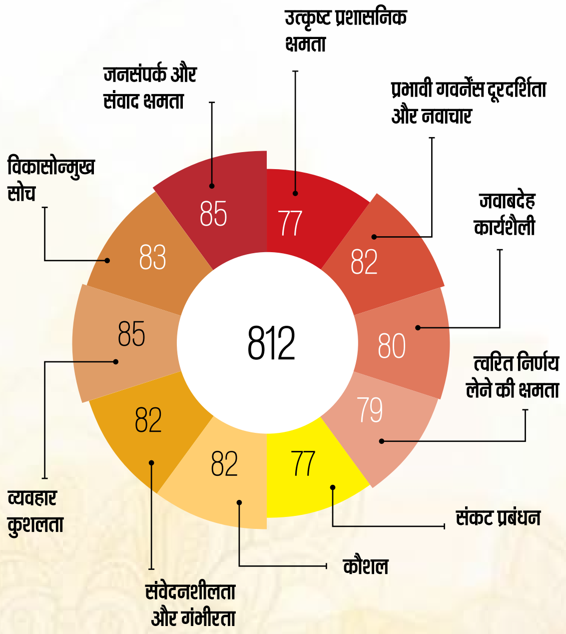

फेम इंडिया-एशिया पोस्ट के 'सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026' के वार्षिक सर्वे में प्रशासनिक अधिकारी विशाल मिश्रा को 'कुशल प्रबंधक' श्रेणी में प्रमुख पाया गया है।

विशाल मिश्र की इस यात्रा में उनके परिवार की भूमिका अविभाज्य है। उनके बड़े भाई ने उनकी तैयारी के वर्षों में उनका मार्गदर्शन किया और जीवनयापन का सहारा दिया। उनकी पत्नी शांडिली उनके सबसे कठिन समय में उनकी शक्ति रही हैं। जब वे एक साथ दो-तीन पदों की जिम्मेदारियाँ सँभाल रहे थे, तब परिवार की यह थाती ही उनका संबल थी। उनकी दो वर्षीया पुत्री वरदा उनके जीवन की वह खुशी है जो हर थकान को दूर कर देती है।

विशाल मिश्र की कहानी हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों और बड़े सपनों के बीच अपना रास्ता बना रहा है। यह कहानी यह बताती है कि भाषा, पृष्ठभूमि या असफलताएँ किसी को नहीं रोक सकतीं — यदि भीतर संकल्प हो, तो हर रुकावट एक सीढ़ी बन जाती है।

विशाल का बचपन उनके पिता हरि प्रसाद मिश्र के साथ फतेहगढ़ में बीता, जो वहाँ राजकीय इंटर कॉलेज में अंग्रेजी के प्रवक्ता थे। सरस्वती बाल विद्या मंदिर फतेहगढ़ से प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद पिता के कानपुर स्थानांतरण पर उनकी स्कूली शिक्षा वहाँ जारी हुई। दसवीं बोर्ड परीक्षा में उन्होंने उत्तर प्रदेश बोर्ड से सत्तहत्तर प्रतिशत अंक प्राप्त किए और इसके बाद बीएनएसडी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज में प्रवेश लिया। वहाँ उन्होंने हिंदी माध्यम में पढ़ाई करते हुए अंग्रेजी माध्यम की पाठ्य पुस्तकों से अपनी तैयारी की — और इस दृढ़निश्चय ने उन्हें बारहवीं में पचासी प्रतिशत अंक दिलाए। यह उनके चरित्र का वह पहलू है जो आगे भी बार-बार सामने आता है — कठिन रास्ता चुनना और उसे पूरे मनोयोग से पूरा करना।

इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए विशाल कोटा-राजस्थान गए, किंतु नई जलवायु में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। माता-पिता ने उन्हें वापस बुलाया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे डटे रहे और उत्तर प्रदेश राज्य तकनीकी प्रवेश परीक्षा में राज्य के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग कॉलेज हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर में सिविल इंजीनियरिंग में प्रवेश पाया। वर्ष 2012 में उन्होंने पचासी प्रतिशत अंकों के साथ यह डिग्री पूरी की। इसके बाद उन्होंने स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में आईआईटी कानपुर में जल संसाधन और हाइड्रॉलिक्स में एम टेक में प्रवेश लिया। वर्ष 2014 में उन्होंने साढ़े नौ के सीजीपीए के साथ यह डिग्री पूरी की यहीं से यूपीएससी की तैयारी का विचार अंकुरित हुआ।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा उनके लिए भी एक चुनौतीपूर्ण यात्रा रही। पहले प्रयास में वर्ष 2015 में उन्होंने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों उत्तीर्ण कर साक्षात्कार तक का सफर तय किया, किंतु फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। दूसरे प्रयास में वर्ष 2016 में भी यही हुआ — कुछ अंकों की कमी फिर आड़े आ गई। हालांकि निराशा हुई, लेकिन विशाल ने हार नहीं मानी। तीसरे प्रयास में उन्होंने समाजशास्त्र को वैकल्पिक विषय के रूप में रखते हुए वर्ष 2017 की सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक उनचास प्राप्त की और भारतीय प्रशासनिक सेवा में चुने गए। यह तीन प्रयासों की कहानी केवल व्यक्तिगत सफलता की नहीं, उस अदम्य जिजीविषा की कहानी है जो उनके पूरे जीवन का मूल स्वर है।

सेवा में आने के बाद विशाल मिश्र ने लगातार विविध और चुनौतीपूर्ण पदों पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। प्रारंभिक प्रशिक्षण काल में अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर में जमीनी प्रशासन सीखने के दौरान उनका जुड़ाव कोसी नदी पुनरुज्जीवन परियोजना से रहा — एक सफल जल संरक्षण प्रयोग जो उत्तराखंड हिमालय में नदी को नया जीवन देने का प्रयास था। इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि होने के कारण जल संसाधन, शहरी विकास और ग्रामीण अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में उनकी समझ और दृष्टि गहरी रही।

रुद्रपुर में उप-मंडल मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करने के बाद वे रुद्रपुर नगर निगम के नगर आयुक्त बने। इसके बाद उन्हें उधम सिंह नगर का मुख्य विकास अधिकारी और साथ ही रुद्रपुर नगर निगम का आयुक्त — दोनों उत्तरदायित्व एक साथ सौंपे गए। यह दोहरी जिम्मेदारी उनकी प्रशासनिक क्षमता और विश्वसनीयता का प्रमाण थी। इसके बाद हल्द्वानी नगर निगम के नगर आयुक्त के रूप में उन्होंने शहरी शासन और नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वर्ष 2024 के अंत में उन्हें गढ़वाल मंडल विकास निगम का प्रबंध निदेशक और जल जीवन मिशन का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया। इसके साथ ही जून 2025 में उन्हें नमामि गंगे परियोजना का परियोजना निदेशक भी बनाया गया। ये तीनों उत्तरदायित्व एक साथ सँभालना उनकी असाधारण कार्यक्षमता और समर्पण को दर्शाता है। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों तक स्वच्छ पेयजल पहुँचाने और नमामि गंगे के तहत गंगा की अविरलता और निर्मलता सुनिश्चित करने जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में उनका योगदान उनकी इंजीनियरिंग दृष्टि और प्रशासनिक कुशलता के संगम का जीवंत उदाहरण है।

विशाल मिश्रा ने जल क्षेत्र में नीतिगत सुधारों एवं प्रभावी जल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत शोधित जल के सुरक्षित पुनः उपयोग संबंधी नीति के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त, उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालन एवं मेंटेनेंस नीति के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे ग्रामीण पेयजल योजनाओं के दीर्घकालिक एवं सतत संचालन को सुनिश्चित करने में सहायता मिली।

फरवरी 2026 में उन्हें रुद्रप्रयाग का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया — एक ऐसा जिला जो केदारनाथ और बदरीनाथ धाम जैसे देश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थस्थलों का प्रवेशद्वार है। यहाँ उन्होंने तुरंत ही केदारनाथ धाम यात्रा की हेलीपैड सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत निरीक्षण किया, अग्नि सुरक्षा मानकों की समीक्षा की और हेलीसेवाओं के लिए उड़ानों की संख्या सीमित कर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की। इसके साथ ही हेलीपैड पर स्वयं सहायता समूहों के लिए विक्रय केंद्र स्थापित कर उन्होंने स्थानीय महिलाओं और समुदायों की आजीविका को तीर्थाटन से जोड़ने का सराहनीय प्रयास किया।

संवेदनशील

संवेदनशील

जनसेवा, नवाचार और सुशासन का सशक्त चेहरा

डॉ. गौरव कुमार सिंह

(रायपुर)

डॉ. गौरव कुमार सिंह आज भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन चुनिंदा अधिकारियों में गिने जाते हैं जिन्होंने प्रशासन को केवल सरकारी व्यवस्था तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जनभागीदारी, नवाचार और सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम बना दिया। वर्ष 2013 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी गौरव कुमार सिंह वर्तमान में रायपुर के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। उनकी प्रशासनिक शैली तकनीक, संवेदनशीलता, जवाबदेही और परिणाम आधारित कार्यप्रणाली का सशक्त उदाहरण मानी जाती है।

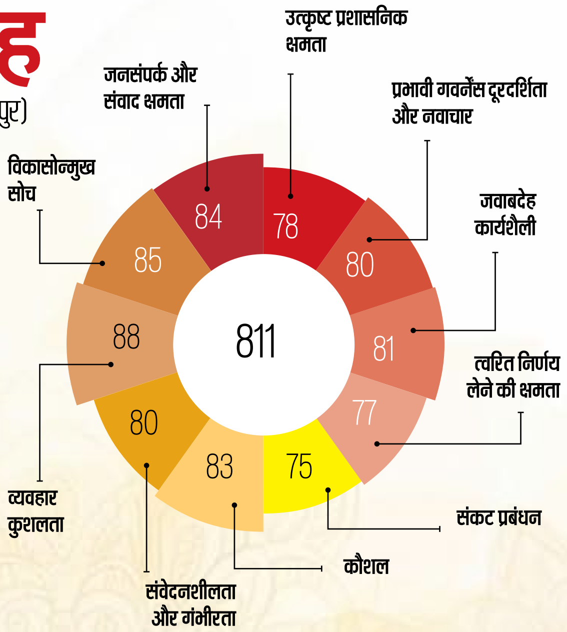

फेम इंडिया-एशिया पोस्ट के 'सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026' के वार्षिक सर्वे में प्रशासनिक अधिकारी गौरव कुमार सिंह को 'संवेदनशील' श्रेणी में प्रमुख पाया गया है।

डॉ. गौरव कुमार सिंह संकट प्रबंधन में भी अत्यंत सक्षम अधिकारी माने जाते हैं। कोविड महामारी, आगजनी की घटनाओं और बोरवेल रेस्क्यू ऑपरेशन जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उन्होंने तेज निर्णय क्षमता और मानवीय दृष्टिकोण का परिचय दिया। उनकी कार्यशैली का सबसे प्रेरणादायक पक्ष यह है कि वे प्रशासन को केवल नियंत्रण का माध्यम नहीं, बल्कि समाज निर्माण का सशक्त साधन मानते हैं। उनके नेतृत्व में योजनाएँ केवल सरकारी आँकड़े नहीं बनतीं, बल्कि लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाती हैं। आज डॉ. गौरव कुमार सिंह एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में स्थापित हो चुके हैं जिनकी पहचान नवाचार, जनसंवेदनशीलता और परिणाम आधारित कार्यशैली से होती है। उनका जीवन और कार्य यह संदेश देता है कि यदि प्रशासनिक इच्छाशक्ति मजबूत हो, तो शासन व्यवस्था समाज में व्यापक और स्थायी परिवर्तन ला सकती है।

उत्तर प्रदेश के हरदोई में जन्मे डॉ. सिंह ने केएनआईटी सुल्तानपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तथा बाद में आईआईटी दिल्ली से एमटेक और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उच्च शिक्षा और निजी क्षेत्र के आकर्षक अवसरों के बावजूद उन्होंने जनसेवा को अपना लक्ष्य बनाया और यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2013 में अखिल भारतीय स्तर पर 190वीं रैंक प्राप्त कर भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित हुए।

डॉ. गौरव कुमार सिंह की पहचान एक ऐसे अधिकारी के रूप में बनी है जो जमीनी स्तर पर उतरकर समस्याओं का समाधान करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से लेकर राज्य की राजधानी तक हर जगह अपनी अलग प्रशासनिक छाप छोड़ी है।

दंतेवाड़ा जैसे नक्सल प्रभावित जिले में उन्होंने 'यूपीएससी मेंटरशिप मॉडल' शुरू किया, जिसके माध्यम से आदिवासी युवाओं को सिविल सेवा जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी के लिए मार्गदर्शन दिया गया। यह पहल राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी और अनेक युवाओं के लिए प्रेरणा साबित हुई।

दंतेवाड़ा में ही उन्होंने 'प्रोजेक्ट कड़कनाथ', 'प्रोजेक्ट शक्ति गारमेंट' और 'प्रोजेक्ट बीपीओ' जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय युवाओं और महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। आदिवासी संस्कृति और परंपरा को राष्ट्रीय मंच देने के लिए अंतरराष्ट्रीय ट्राइबल फेस्टिवल और समिट का आयोजन भी कराया गया, जिसने जिले को नई पहचान दिलाई।

सुरजपुर के कलेक्टर के रूप में उनका कार्यकाल भी अत्यंत प्रभावशाली रहा। कोविड महामारी के कठिन समय में उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कराए, स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया और राहत कार्यों को गाँव-गाँव तक पहुँचाया। 'प्रशासन तुहर द्वार' और 'जन संवाद' जैसी पहलों के माध्यम से सरकारी सेवाओं को सीधे लोगों के घर तक पहुँचाने का प्रयास किया गया।

मूंगेली और बालोद में भी उन्होंने शिक्षा, खेल, संस्कृति और जनसंवाद को नई दिशा दी। '100 जन चौपाल' जैसी पहलें यह दर्शाती हैं कि वे जनता से सीधे संवाद में विश्वास रखते हैं। वहीं कला केंद्रों और आधुनिक पुस्तकालयों की स्थापना के माध्यम से युवाओं को रचनात्मक मंच प्रदान किया गया।

वर्तमान में रायपुर कलेक्टर के रूप में डॉ. गौरव कुमार सिंह ने प्रशासनिक नवाचारों की नई मिसाल स्थापित की है। उनके नेतृत्व में 'चलो कुछ अच्छा करते हैं' अभियान के अंतर्गत 100 से अधिक नवाचारी परियोजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, कौशल विकास और सुशासन जैसे अनेक क्षेत्रों को प्रभावित कर रही हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में 'प्रोजेक्ट धड़कन', 'प्रोजेक्ट रक्षा', 'प्रोजेक्ट सुरक्षा' और 'प्रोजेक्ट दृष्टि' जैसी पहलों के माध्यम से हजारों बच्चों और नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की गईं। होंठ-तालु विकृति से पीड़ित बच्चों के लिए 'प्रोजेक्ट जिंदगी मुस्कुराएगी' तथा थैलेसीमिया रोगियों के लिए 'प्रोजेक्ट जीवन' जैसी योजनाओं ने स्वास्थ्य सेवाओं में मानवीय संवेदनशीलता का नया उदाहरण प्रस्तुत किया। 'प्रोजेक्ट हेल्दी लाइफस्टाइल क्लीनिक' और 'हर घर मूंगा' जैसी पहलों ने जनस्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई। दिव्यांगजनों के लिए 'प्रोजेक्ट दिव्यांग गैराज' विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा, जिसके अंतर्गत व्हीलचेयर, कृत्रिम अंग और श्रवण यंत्र जैसे सहायक उपकरणों की निःशुल्क मरम्मत एवं रखरखाव की व्यवस्था की गई।

शिक्षा और युवा सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी उनके कार्य अत्यंत प्रभावशाली रहे हैं। 'प्रोजेक्ट अनुभव' के माध्यम से यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अनेक विद्यार्थियों का चयन हुआ। 'प्रोजेक्ट अंतरिक्ष' के तहत छत्तीसगढ़ की पहली स्पेस लैब स्थापित की गई। वहीं 'प्रोजेक्ट युवा 2.0' के माध्यम से हजारों युवाओं को आईटी, नर्सिंग और उद्यमिता का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

डॉ. सिंह ने प्रशासन को तकनीक से जोड़कर सुशासन की नई परिभाषा भी दी। 'प्रोजेक्ट 24×7 कॉल सेंटर', 'मोर रायपुर ऐप', 'प्रोजेक्ट समाधान', 'प्रोजेक्ट सरल' और 'सुशासन एक्सप्रेस' जैसी पहलों ने सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, तेज और नागरिकों के लिए सुलभ बनाया। इन पहलों के माध्यम से लाखों लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया गया।

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में 'लखपति दीदी', 'बिजनेस दीदी', 'पिंक दीदी' और 'प्रोजेक्ट उद्यमी' जैसी योजनाओं ने हजारों महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से 'प्रोजेक्ट अजा' को राष्ट्रीय स्तर पर ईटी गॉवटेक 2026 सम्मान प्राप्त हुआ।

पर्यावरण संरक्षण और जल संवर्धन के क्षेत्र में 'प्रोजेक्ट ग्रीन पालना', 'हरियर पाठशाला', 'प्रोजेक्ट अमृत' और 'प्रोजेक्ट रचना' जैसी पहलों ने जनभागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को सामाजिक आंदोलन का रूप दिया। अपशिष्ट फ्लेक्स बैनरों को रीसाइकिल करने की पहल ने पर्यावरणीय जागरूकता को नई दिशा दी। जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए रायपुर को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी प्राप्त हुआ।

सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में 'प्रोजेक्ट दधीचि' ने अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाई, जबकि 'प्रोजेक्ट क्षय मित्र' ने टीबी रोगियों को सामुदायिक पोषण सहयोग उपलब्ध कराया। 'आओ बांटें खुशियाँ' अभियान के माध्यम से प्रशासनिक संवेदनशीलता को सामाजिक सहभागिता से जोड़ा गया। वहीं 'प्रोजेक्ट आरंभ' के अंतर्गत स्थापित 120-सीटर स्टार्टअप इनक्यूबेशन सेंटर ने युवाओं में उद्यमिता को प्रोत्साहित किया।

उत्कृष्ट

नवाचार, संवेदनशीलता और जनसेवा का प्रेरक प्रशासनिक चेहरा

अंकित कुमार सिंह

(डूंगरपुर, वर्तमान फलोदी)

मूल रूप से उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले अंकित कुमार सिंह ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रवेश किया। तकनीकी पृष्ठभूमि से आने वाले अंकित कुमार सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक्स में बी.टेक. की शिक्षा प्राप्त की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई ने उनमें विश्लेषण क्षमता और समस्याओं को व्यावहारिक ढंग से हल करने की सोच विकसित की, जिसका प्रभाव उनकी प्रशासनिक कार्यशैली में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।

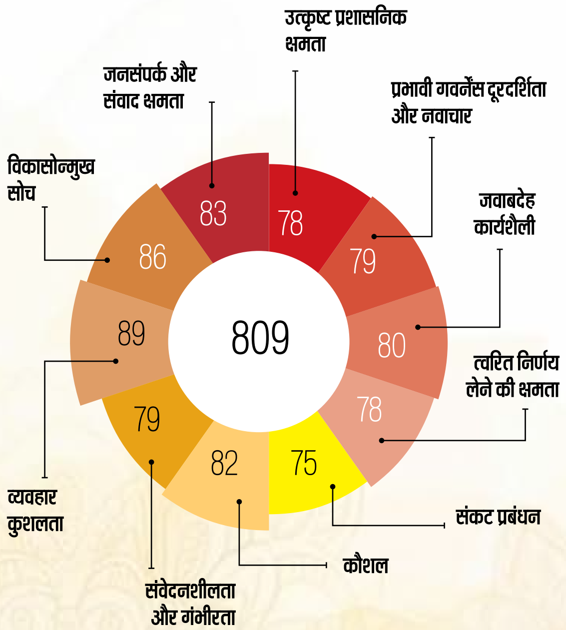

फेम इंडिया-एशिया पोस्ट के 'सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026' के वार्षिक सर्वे में प्रशासनिक अधिकारी अंकित कुमार सिंह को 'उत्कृष्ट' श्रेणी में प्रमुख पाया गया है।

फलौदी जिले में वर्तमान कार्यकाल के दौरान भी उनसे काफी अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण फलौदी में जल प्रबंधन, ग्रामीण विकास, रोजगार और आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी चुनौतियां हैं। प्रशासनिक हलकों में माना जा रहा है कि अंकित कुमार सिंह अपने अनुभव और नवाचारों के माध्यम से यहां भी विकास की नई मिसाल स्थापित करेंगे। उनके निजी जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी अंजलि राजौरिया भी आईएएस अधिकारी हैं और राजस्थान प्रशासनिक सेवा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं। यह प्रशासनिक दंपति युवा अधिकारियों के लिए प्रेरणा माना जाता है।

अंकित कुमार सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन अधिकारियों में शामिल हैं जिन्होंने अपने कार्यों से यह साबित किया है कि प्रशासन केवल सरकारी व्यवस्था चलाने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज में वास्तविक बदलाव लाने की शक्ति भी है। राजस्थान कैडर के 2014 बैच के आईएएस अधिकारी अंकित कुमार सिंह आज एक संवेदनशील, नवाचारी और परिणाम देने वाले अधिकारी के रूप में पहचाने जाते हैं। वर्तमान में वे राजस्थान के फलौदी जिले में जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और करौली जैसे महत्वपूर्ण जिलों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और हर स्थान पर अपने कार्यों की गहरी छाप छोड़ चुके हैं।

करीब 12 वर्षों की प्रशासनिक सेवा में उन्होंने राजस्थान के विभिन्न जिलों में काम किया है। उनकी पहचान ऐसे अधिकारी के रूप में बनी है जो योजनाओं को केवल कागजों तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्हें अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कई बार यह उल्लेख किया गया कि अंकित कुमार सिंह फील्ड विजिट, जनसंवाद और जमीनी स्तर पर निगरानी को सबसे अधिक महत्व देते हैं।

उनकी प्रशासनिक क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्हें लगातार राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2024 में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उन्हें दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। यह सम्मान अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया था।

यह अंकित कुमार सिंह का तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार था। इससे पहले वे बांसवाड़ा जिले में कलेक्टर रहते हुए राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त कर चुके थे। वहीं करौली जिले में एमएसएमई क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए उन्हें राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार मिला। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को विशेष रूप से रेखांकित किया गया कि वे जिन-जिन जिलों में कलेक्टर रहे, वहां उन्होंने नवाचारों के माध्यम से नई पहचान बनाई और राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किए। यह उपलब्धि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के लिए बेहद दुर्लभ मानी जाती है।

डूंगरपुर जिले में दिव्यांगजनों के लिए उनका "नो वन लेफ्ट बिहाइंड" अभियान विशेष रूप से चर्चा में रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मिशन का उद्देश्य था कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति सरकारी योजनाओं और सुविधाओं से वंचित न रहे। इस अभियान के तहत जिले के सभी 10 ब्लॉकों में विशेष शिविर लगाए गए, जहां दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र, उपकरण, पेंशन और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया।

अंकित कुमार सिंह ने दिव्यांगजनों के लिए घर-घर राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी शुरू करवाई। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले कई लोग प्रशासनिक कार्यालयों तक नहीं पहुंच पाते थे, इसलिए उन्होंने प्रशासन को लोगों तक पहुंचाने का मॉडल अपनाया। स्थानीय समाचार पत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी इस पहल को "संवेदनशील प्रशासन का उत्कृष्ट उदाहरण" बताया गया।

लोकतंत्र में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष अभियान चलाया। उनके प्रयासों से जिले में दिव्यांग मतदाताओं का लगभग शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित हुआ। चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासनिक हलकों में इस पहल की काफी सराहना हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह अभियान राजस्थान में दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने का प्रेरक मॉडल बना।

रोजगार और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भी उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए। राजीविका योजना के माध्यम से दिव्यांगजनों के 228 स्वयं सहायता समूह बनाए गए। इन समूहों के जरिए दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा गया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसे सामाजिक समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया गया।

मनरेगा योजना में दिव्यांगजनों की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी उन्होंने विशेष प्रयास किए। उनके नेतृत्व में 6,895 दिव्यांगजन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में पंजीकृत हुए, जो पूरे राजस्थान में सबसे अधिक संख्या थी। इतना ही नहीं, दिव्यांगजनों के लिए दो लाख से अधिक मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया और लगभग 4.25 करोड़ रुपये मजदूरी के रूप में वितरित किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स में इसे "राजस्थान का रिकॉर्ड प्रदर्शन" बताया गया। बांसवाड़ा जिले में जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए उनके कार्य भी काफी चर्चित रहे। राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिलने के बाद कई समाचार माध्यमों ने लिखा कि अंकित कुमार सिंह ने जल संरक्षण को जनभागीदारी से जोड़ा। उन्होंने वर्षा जल संरक्षण, जल संरचनाओं के पुनर्जीवन और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जागरूकता अभियान चलाकर इसे एक जनआंदोलन का रूप दिया।

इसी प्रकार करौली जिले में उन्होंने एमएसएमई और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई नवाचारी कदम उठाए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनके प्रयासों से छोटे उद्यमियों और स्थानीय युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए। उनकी कार्यशैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे प्रशासन को मानवीय दृष्टिकोण से देखते हैं। वे आम लोगों की समस्याओं को सुनने, मौके पर जाकर स्थिति समझने और त्वरित समाधान देने में विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि जनता के बीच उनकी छवि एक सुलभ, संवेदनशील और कर्मठ अधिकारी की बनी हुई है।

आज अंकित कुमार सिंह उन अधिकारियों में गिने जाते हैं जिन्होंने यह सिद्ध किया है कि यदि प्रशासनिक इच्छाशक्ति मजबूत हो और कार्य के प्रति संवेदनशीलता हो, तो सरकारी योजनाएं वास्तव में लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। उनकी उपलब्धियां और कार्यशैली आने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।

सराहनीय

मोरीगांव की जिलाधिकारी अनामिका तिवारी ने अपने जनकेंद्रित दृष्टिकोण, सक्रिय प्रशासनिक शैली और विकासोन्मुख सोच से जिले में नई ऊर्जा का संचार किया है। बाढ़ प्रभावित और सामाजिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों वाले मोरीगांव में उन्होंने प्रशासन को लोगों के बीच पहुँचाने का निरंतर प्रयास किया। उनका मानना है कि विकास तभी सार्थक होता है जब उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।

मोरीगांव की विकासोन्मुख जिलाधिकारी

अनामिका तिवारी (मोरीगांव)

उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यक्रमों को विशेष गति मिली। उन्होंने विद्यालयों की नियमित मॉनिटरिंग, पोषण अभियानों और जनजागरूकता कार्यक्रमों को मजबूत किया। महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने तथा ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास से जोड़ने की दिशा में भी प्रभावी पहल की गई।

बाढ़ प्रबंधन और आपदा राहत कार्यों में उनकी तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता विशेष रूप से सराही गई। उन्होंने प्रशासनिक टीमों को क्षेत्रीय स्तर पर अधिक सक्रिय बनाकर राहत कार्यों को समयबद्ध और प्रभावी बनाया।

अनामिका तिवारी की कार्यशैली की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सहजता और जनसंवाद क्षमता है। वे प्रशासन को केवल आदेश देने वाली व्यवस्था नहीं, बल्कि समाज के साथ साझेदारी का माध्यम मानती हैं। यही कारण है कि मोरीगांव में विकास योजनाओं के साथ-साथ जनता का प्रशासन पर विश्वास भी लगातार मजबूत हुआ है।

लखनऊ के जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर उन अधिकारियों में गिने जाते हैं जिन्होंने आधुनिक प्रशासनिक दृष्टिकोण और प्रभावी प्रबंधन क्षमता के माध्यम से राजधानी लखनऊ के विकास को नई गति दी है। उनकी कार्यशैली तकनीक, पारदर्शिता और जनसहभागिता पर आधारित रही है।

लखनऊ को आधुनिक प्रशासनिक मॉडल की ओर ले जाते अधिकारी

विशाख जी अय्यर (लखनऊ)

राजधानी होने के कारण लखनऊ की प्रशासनिक चुनौतियाँ अत्यंत व्यापक हैं। यातायात प्रबंधन, स्वच्छता, शहरी आधारभूत संरचना, नागरिक सुविधाएँ और पर्यावरण संरक्षण जैसे अनेक क्षेत्रों में विशाख जी अय्यर ने प्रभावी समन्वय स्थापित किया। उन्होंने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और डिजिटल प्रशासन को गति देकर नागरिक सेवाओं को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया।

उनके नेतृत्व में जनसुनवाई और शिकायत निवारण व्यवस्था को अधिक सक्रिय बनाया गया, जिससे लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो सके। वे नियमित फील्ड निरीक्षण और जमीनी स्तर की मॉनिटरिंग को प्रशासनिक दक्षता का सबसे महत्वपूर्ण आधार मानते हैं।

विशाख जी अय्यर ने राजधानी के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्वरूप को संरक्षित रखते हुए आधुनिक विकास को आगे बढ़ाने पर भी विशेष बल दिया। उनकी कार्यशैली में अनुशासन और संवेदनशीलता का संतुलन स्पष्ट दिखाई देता है। यही कारण है कि वे जनता और प्रशासन दोनों के बीच एक प्रभावशाली और भरोसेमंद अधिकारी के रूप में स्थापित हुए हैं।

सराहनीय

एनटीआर के जिलाधिकारी जी. लक्ष्मीशा ने अपने प्रभावी प्रशासनिक कौशल और परिणामोन्मुख कार्यशैली से जिले में विकास और सुशासन को नई दिशा दी है। वे उन अधिकारियों में गिने जाते हैं जो योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं।

एनटीआर जिले में सुशासन और विकास के संवाहक

जी. लक्ष्मीशा (एनटीआर जिला)

उनके नेतृत्व में प्रशासनिक पारदर्शिता और तकनीक आधारित सेवा वितरण को मजबूत किया गया। उन्होंने नागरिक सेवाओं को अधिक सरल और सुलभ बनाने के लिए डिजिटल प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा दिया। राजस्व प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग कर योजनाओं के क्रियान्वयन में गति लाई गई।

ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्रीय स्तर पर अधिक सक्रिय रहने के निर्देश दिए। महिला स्वयं सहायता समूहों, युवाओं के कौशल विकास और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों पर भी विशेष ध्यान दिया गया।

जी. लक्ष्मीशा की प्रशासनिक शैली की सबसे बड़ी विशेषता उनका संतुलित दृष्टिकोण है। वे कठोर प्रशासनिक अनुशासन के साथ मानवीय संवेदनशीलता को भी समान महत्व देते हैं। यही कारण है कि एनटीआर जिले में विकास कार्यों के साथ-साथ प्रशासन के प्रति जनता का भरोसा भी मजबूत हुआ है।

सुंदरगढ़ के जिलाधिकारी सुभंकर मोहापात्र ने आदिवासी बहुल जिले में विकास और सामाजिक समावेशन को नई दिशा देने का उल्लेखनीय कार्य किया है। सुंदरगढ़ प्राकृतिक संसाधनों और खनिज संपदा से समृद्ध होने के बावजूद लंबे समय तक कई सामाजिक और आधारभूत चुनौतियों से जूझता रहा है। ऐसे जिले में उन्होंने विकास को जनभागीदारी और प्रशासनिक संवेदनशीलता से जोड़ने का प्रयास किया।

सुंदरगढ़ में समावेशी विकास के प्रेरक

सुभंकर मोहापात्र (सुंदरगढ़)

उनके नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और ग्रामीण आधारभूत संरचना को मजबूत करने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण पहलें हुईं। उन्होंने आदिवासी समुदायों तक सरकारी योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक तंत्र को अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाया।

सुंदरगढ़ देश में हॉकी प्रतिभाओं की भूमि के रूप में भी प्रसिद्ध है। इस पहचान को मजबूत करने के लिए उन्होंने खेल और युवा विकास को विशेष प्राथमिकता दी। महिला सशक्तिकरण, पेयजल उपलब्धता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी उनके नेतृत्व में कई सकारात्मक प्रयास किए गए।

सुभंकर मोहापात्र की कार्यशैली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे विकास को केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं मानते, बल्कि उसे सामाजिक परिवर्तन का माध्यम समझते हैं। उनकी संवेदनशीलता और जमीनी समझ ने सुंदरगढ़ में प्रशासन के प्रति विश्वास और सहभागिता दोनों को नई मजबूती प्रदान की है।

FAME INDIA fi

सर्वश्रेष्ठ
जिलाधिकारी 2026

सराहनीय

उडुपी की जिलाधिकारी स्वरूपा टीके ने अपनी शांत, प्रभावी और जनकेंद्रित प्रशासनिक शैली से जिले में विकास और सुशासन की नई पहचान स्थापित की है। तटीय क्षेत्र होने के कारण उडुपी प्राकृतिक सौंदर्य, धार्मिक पर्यटन और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके साथ-साथ यहाँ पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन और शहरी विस्तार जैसी चुनौतियाँ भी मौजूद हैं। स्वरूपा टीके ने इन चुनौतियों को दूरदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ संभालने का प्रयास किया।

उडुपी में जनसंवेदनशील प्रशासन की सशक्त पहचान

स्वरूपा टी के (उडुपी)

उनके नेतृत्व में प्रशासन ने तटीय सुरक्षा, मानसून पूर्व तैयारियों और आपदा प्रबंधन व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाया। भारी वर्षा और समुद्री प्रभाव वाले क्षेत्रों में राहत एवं बचाव तंत्र को सक्रिय और प्रभावी बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को प्रशासनिक प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए हरित पहल और स्वच्छता अभियानों को भी गति दी।

महिला सशक्तिकरण और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूहों तथा ग्रामीण आजीविका कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया गया। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए भी नियमित निरीक्षण और जनसंवाद आधारित कार्यप्रणाली अपनाई गई।

स्वरूपा टीके की प्रशासनिक शैली की सबसे बड़ी विशेषता उनकी सहजता और जनता से संवाद की क्षमता है। यही कारण है कि उडुपी में प्रशासन के प्रति जनता का भरोसा और सहयोग लगातार मजबूत हुआ है।

हावड़ा की जिलाधिकारी पी. दीपाप प्रिया ने अपने प्रभावी प्रशासनिक नेतृत्व और जनसंवेदनशील दृष्टिकोण से जिले के विकास को नई दिशा प्रदान की है। औद्योगिक, व्यावसायिक और अत्यधिक आबादी वाले जिले हावड़ा में प्रशासनिक चुनौतियाँ हमेशा जटिल रही हैं। यातायात दबाव, शहरी आधारभूत संरचना, स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवाएँ और नागरिक सुविधाओं के समुचित प्रबंधन के लिए मजबूत प्रशासनिक समन्वय की आवश्यकता होती है।

हावड़ा में आधुनिक और मानवीय प्रशासन का चेहरा

पी. दीपाप प्रिया (हावड़ा)

पी. दीपाप प्रिया ने प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए। उनके नेतृत्व में शहरी सेवाओं के आधुनिकीकरण, शिकायत निवारण प्रणाली को मजबूत करने और जनसुनवाई व्यवस्था को अधिक सक्रिय बनाने पर विशेष बल दिया गया। उन्होंने विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर विकास परियोजनाओं को गति प्रदान की।

स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र में भी उनके नेतृत्व में कई प्रभावी पहलें हुईं। नागरिक सुविधाओं को अधिक व्यवस्थित बनाने और शहरी जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए आधारभूत ढाँचे को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया। साथ ही, महिलाओं और कमजोर वर्गों से जुड़े कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को भी प्राथमिकता दी गई।

पी. दीपाप प्रिया की कार्यशैली की सबसे बड़ी विशेषता उनकी संवेदनशीलता और जनसुलभ व्यवहार है। यही कारण है कि हावड़ा में विकास और जनविश्वास दोनों को नई मजबूती मिली है।

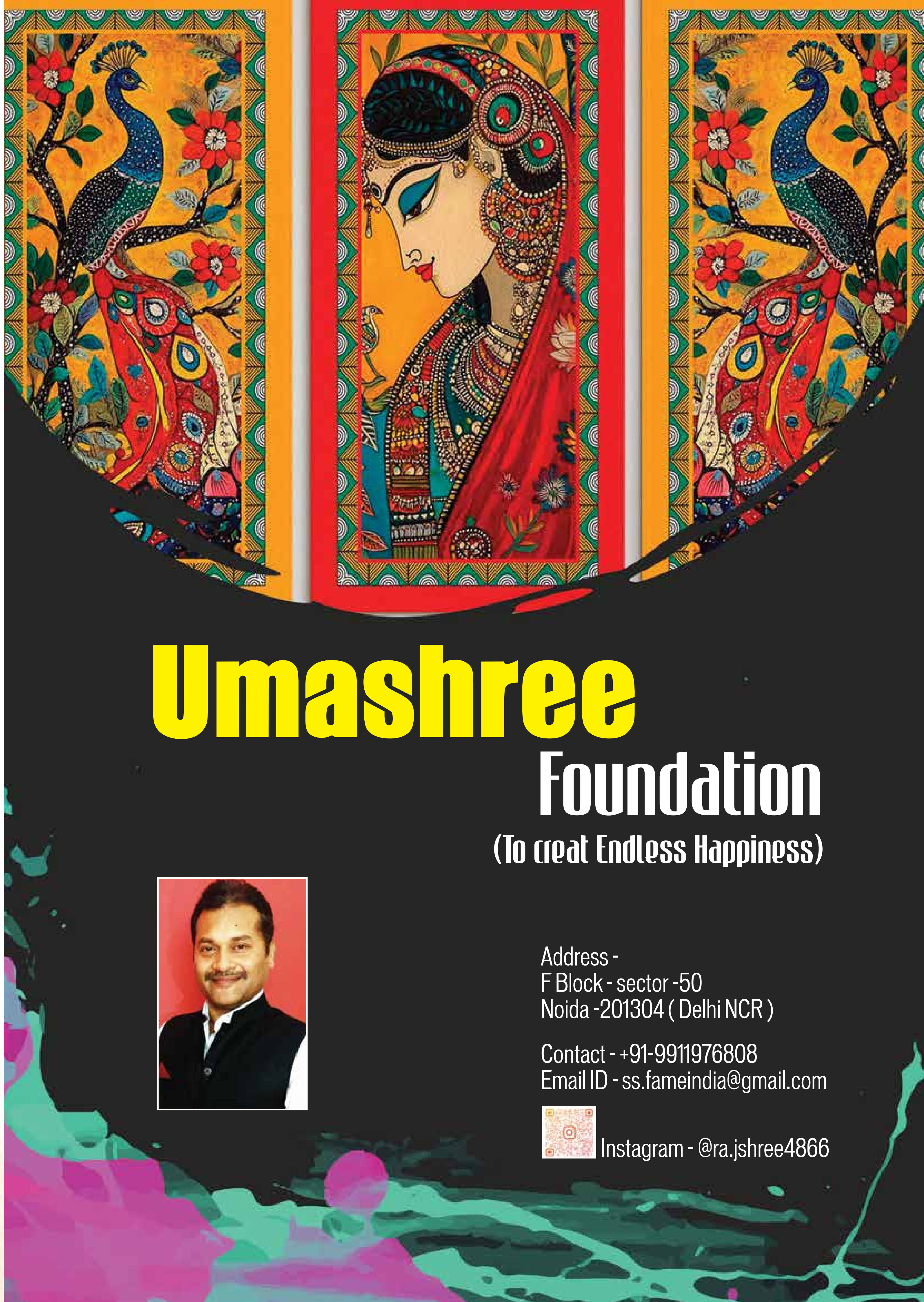

आउट ऑफ द बॉक्स

अब एक नजर उन अफसरों पर जो अब तो जिलाधिकारी नहीं हैं, लेकिन कुछ महीनों पूर्व तक अपने कार्यकाल में अपने जिले की कायापलट कर इतिहास में नाम दर्ज करा चुके हैं।

बुवेनेश्वरी सुरियन ने वाशिम की जिलाधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान यह सिद्ध कर दिखाया कि यदि प्रशासन दूरदर्शिता और नवाचार के साथ कार्य करे, तो एक साधारण जिला भी राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना सकता है। उनके नेतृत्व में वाशिम ने देश में "ऑर्गेनिक चिया हब" के रूप में पहचान बनाई। पारंपरिक फसलों पर निर्भर किसानों को अधिक आय और कम जल उपयोग वाली खेती से जोड़ने के उद्देश्य से उन्होंने चिया सीड की खेती को बढ़ावा दिया। प्रारंभ में सीमित क्षेत्र में शुरू हुई यह पहल कुछ ही वर्षों में हजारों किसानों तक पहुँच गई।

एक साधारण से जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली चमत्कारी अधिकारी

बुवेनेश्वरी सुरियन (वाशिम, महाराष्ट्र)

आज आठ हजार से अधिक किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। चिया खेती ने न केवल किसानों की आय में वृद्धि की, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और टिकाऊ कृषि मॉडल को भी मजबूती दी।

उन्होंने किसानों को नई फसल के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यशालाएँ, फील्ड डेमोंस्ट्रेशन और स्थानीय भाषा में तकनीकी मार्गदर्शिकाएँ तैयार कराईं। साथ ही, विपणन व्यवस्था को मजबूत करते हुए स्थानीय कृषि मंडियों में चिया व्यापार की व्यवस्था विकसित की गई, जिससे किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके।

बुवेनेश्वरी सुरियन की कार्यशैली की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि वे विकास को केवल सरकारी योजना नहीं, बल्कि जनभागीदारी आधारित सामाजिक परिवर्तन मानती थीं। उनके नेतृत्व में वाशिम केवल कृषि उत्पादन का केंद्र नहीं बना, बल्कि नवाचार और किसान आत्मनिर्भरता का प्रेरणादायी मॉडल बनकर उभरा।

तरित कांति चकमा ने गोमती के जिलाधिकारी एवं कलेक्टर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान प्रशासनिक नवाचार, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और समग्र विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। उनके नेतृत्व में गोमती जिला वर्ष 2024 के लिए "समग्र जिला विकास" श्रेणी में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित हुआ। यह सम्मान स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिविल सेवा दिवस 2025 पर प्रदान किया गया।

सुशासन, संवेदनशीलता और समग्र विकास का नाम

तरित कांति चकमा (गोमती, त्रिपुरा)

गोमती जिले में उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य, पोषण, ग्रामीण विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना, मिशन इंद्रधनुष और आधारभूत सेवाओं के क्रियान्वयन को नई गति मिली। प्रशासनिक पारदर्शिता और योजनाओं की समयबद्ध मॉनिटरिंग के कारण जिला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया।

उन्होंने स्थानीय आजीविका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी प्रभावी पहलें कीं। विशेष रूप से अनानास प्रसंस्करण इकाइयों और ग्रामीण उत्पादों को बढ़ावा देकर किसानों और स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। आकांक्षी क्षेत्रों में जनभागीदारी आधारित विकास मॉडल को लागू करने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही।

बाद में उन्हें त्रिपुरा रुरल लाइवलिहुड मिशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया, जहाँ उन्होंने "प्रोजेक्ट त्रिप्ती" जैसी योजनाओं के माध्यम से अत्यंत गरीब परिवारों की आजीविका सुधारने की दिशा में कार्य किया। इस परियोजना को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

आउट ऑफ द बॉक्स

असम-मेघालय कैडर के 2018 बैच के आईएएस अधिकारी अभिलाष बरनवाल ने मेघालय के चुनौतीपूर्ण जिलों में काम करते हुए यह सिद्ध किया है कि सुशासन का सबसे प्रभावी रूप वही है जो लोगों की भाषा और संस्कृति से जुड़ा हो। झारखंड से आने वाले इस युवा अधिकारी ने प्रशासन को तकनीक, स्थानीय संवाद और जनभागीदारी के माध्यम से नई पहचान दी।

नवाचार, भाषा-संवेदनशीलता और समावेशी विकास के अनूठे प्रणेता

अभिलाष बरनवाल (री भोई)

ईस्ट जयंतिया हिल्स के उपायुक्त के रूप में उन्होंने महसूस किया कि अधिकांश ग्रामीण नागरिक सरकारी योजनाओं से इसलिए वंचित रह जाते हैं क्योंकि जानकारी उनकी मातृभाषा में उपलब्ध नहीं होती। इसका समाधान उन्होंने "डीसी ईस्ट जयंतिया हिल्स" नामक पनार भाषा के पॉडकास्ट के रूप में निकाला। इस पहल के माध्यम से सरकारी योजनाओं, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी सरल स्थानीय भाषा में लोगों तक पहुँचाई गई। यह पॉडकास्ट विभिन्न डिजिटल मंचों और आकाशवाणी के माध्यम से दूरदराज के गाँवों तक पहुँचा।

उन्होंने "का लावेई" नामक डिजिटल शिक्षा परियोजना भी शुरू की, जिसका उद्देश्य स्थानीय बच्चों को उनकी भाषाई पृष्ठभूमि के अनुरूप आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। बाद में री-भोई के उपायुक्त के रूप में उन्होंने प्रशासन को "हर दरवाजे तक पहुँचाने" की अवधारणा पर काम किया। सार्वजनिक सेवाओं की पारदर्शिता, जिला ब्रांड निर्माण और स्वयं सहायता समूहों को बाजार से जोड़ने की उनकी पहल ने जिले के विकास को नई दिशा दी। आज अभिलाष बरनवाल को देश के सबसे नवोन्मेषी युवा अधिकारियों में गिना जाता है, जिनकी कार्यशैली भाषाई संवेदनशीलता, समावेशी विकास और पारदर्शी प्रशासन पर आधारित है।

अरविंद विजयन ने गुजरात में पाटन के जिला कलेक्टर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान संवेदनशील प्रशासन, सामाजिक संतुलन और प्रभावी सुशासन की उल्लेखनीय मिसाल प्रस्तुत की। वर्ष 2014 बैच के इस आईएएस अधिकारी ने जिले में प्रशासन को केवल सरकारी तंत्र तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जनविश्वास और सामाजिक समन्वय का माध्यम बनाया।

संवेदनशील प्रशासन और सुशासन की सशक्त मिसाल

अरविंद विजयन

उनके कार्यकाल की सबसे चर्चित उपलब्धियों में से एक थी कनोसान गाँव में सामाजिक तनाव की स्थिति को अत्यंत संतुलित और शांतिपूर्ण ढंग से संभालना। एक दलित दुकानदार के बहिष्कार से उत्पन्न संवेदनशील परिस्थिति में उन्होंने ऐसा समाधान निकाला जिससे सामाजिक शांति भी बनी रही और सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी प्रभावित नहीं हुई। प्रशासन ने प्रभावित ग्रामीणों के राशन कार्ड पड़ोसी गाँव से जोड़ दिए, जिससे बिना टकराव के व्यवस्था सुचारु रूप से चलती रही। यह निर्णय उनकी व्यावहारिक सोच और सामाजिक संवेदनशीलता का उदाहरण माना गया।

चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में भी उन्होंने गुजरात के "सर्वश्रेष्ठ जिला निर्वाचन अधिकारी" का सम्मान प्राप्त किया। उन्होंने जिले के दूरदराज क्षेत्रों तक शिक्षा, पेयजल, बिजली और आवश्यक सरकारी सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। उनकी प्रभावी कार्यशैली और प्रशासनिक दक्षता को देखते हुए बाद में उन्हें गांधीनगर स्थानांतरित कर गुजरात इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, जहाँ वे डिजिटल प्रशासन और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में नई भूमिका निभा रहे हैं।

सर्वश्रेष्ठ
जिलाधिकारी 2026

फेम इंडिया द्वारा 'सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारी 2026' सर्वेक्षण का प्राथमिक परिणाम

आंध्र प्रदेश
1- ए. तमीम अंसारिया (गुंटूर)
2- जी. लक्ष्मीशा (एनटीआर जिला)
3- डीके बालाजी (कृष्णा)

असम
1- अनामिका तिवारी (मोरीगांव)
2- बिक्रम कैरी (डिब्रूगढ़)
3- सुमित सत्तावन (तिनसुकिया)
4- स्वप्नील पॉल (कामरूप मेट्रोपॉलिटन)

उत्तर प्रदेश
1- अंजनी कुमार सिंह (मैनपुरी)
2- अस्मिता लाल (बागपत)
3- अविनाश सिंह (बरेली)
4- राजेंद्र पेंसिया (संभल)
5- रविन्द्र कुमार (आजमगढ़)
6- विजय कुमार सिंह (मेरठ)
7- विशाख जी अय्यर (लखनऊ)
8- सत्येंद्र कुमार (वाराणसी)

उत्तराखंड
1- नितिन सिंह भदौरिया (ऊधम सिंह नगर)
2- प्रशांत आर्य (उत्तरकाशी)
3- मयूर दीक्षित (हरिद्वार)
4- ललित मोहन रयाल (नैनीताल)
5- विशाल मिश्रा (रुद्रप्रयाग)

ओडिशा
1- अमृत रुतुराज (खोरधा)
2- दत्तात्रेय भाऊसाहेब शिंदे (कटक)
3- वी. कीर्ति वासन (गंजाम)
4- सुभंकर मोहापात्र (सुंदरगढ़)

कर्नाटक
1- जगदीश जी (बेंगलुरु अर्बन)
2- दर्शन एच वी (दक्षिण कन्नड़)
3- स्वरूपा टीके (उडुपी)

केरल
1- अनु कुमारी (तिरुवनंतपुरम)
2- जी. प्रियंका (कोच्चि)
3- प्रेम कृष्णन एस (पथानमथिट्टा)

छत्तीसगढ़
1- गौरव कुमार सिंह (रायपुर)
2- दिव्या उमेश मिश्रा (बालोद)
3- संबित मिश्रा (बीजापुर)

झारखंड
1- आदित्य रंजन (धनबाद)
2- दिनेश कुमार यादव (गढ़वा)
3- मंजूनाथ भजन्त्री (रांची)
4- रवि आनंद (जामताड़ा)
5- आर. रेनिता (खूंटी)
6- हेमंत सती (साहिबगंज)

गुजरात
1- तेजस परमार (सूरत)
2- डॉ.. ओमप्रकाश (राजकोट)

तमिलनाडु
1- डी. स्नेहा (कांचीपुरम)
2- पवनकुमार जी गिरियप्पनवार (कोयंबटूर)

तेलंगाना
1- मिक्किलिनेनी मनु चौधरी (मेदचल-मल्काजगिरी)
2- हरिचंदना दासरी (हैदराबाद)
3- सी. नारायण रेड्डी (रंगारेड्डी)

त्रिपुरा
1- चांदनी चंद्रन (नॉर्थ त्रिपुरा)
2- रिंकू लाथर (गोमती)
3- विशाल कुमार (वेस्ट त्रिपुरा)

प. बंगाल
1- पी. दीपप प्रिया (हावड़ा)
2- पोन्नामबलम एस (पश्चिम बर्धमान)
3- हरिशंकर पैनिकर (दार्जिलिंग)
4- शिल्पा गौरसिरिया (उत्तर 24 परगना)

पंजाब
1- आशिका जैन (होशियारपुर)
2- कोमल मित्तल (मोहाली)
3- दीपशिखा शर्मा (फिरोजपुर)
4- हिमांशु अग्रवाल (जालंधर)

बिहार
1-आनंद शर्मा (मधुबनी)
2- उदिता सिंह (रोहतास)
3- दीपेश कुमार (सहरसा)
4- डॉ. थियागराजन एस.एम. (पटना)
5- वैभव श्रीवास्तव (सारण)
6- विवेक रंजन मैत्रेय (सीवान)
7- शशांक शुभंकर (गया)
8- सुब्रत कुमार सेन (मुजफ्फरपुर)

मणिपुर
1- धरुन कुमार एस (चुराचंदपुर)
2- मयांग्लाम्बम राजकुमार (इम्फाल वेस्ट)

मध्य प्रदेश
1- कौशलेंद्र विक्रम सिंह (भोपाल)
2- रजनी सिंह (नरसिंहपुर)
3- राघवेंद्र सिंह (जबलपुर)
4- सतीश कुमार एस (सतना)
5- शिवम वर्मा (इंदौर)

महाराष्ट्र
1- अमोल जगन्नाथ येडगे (कोल्हापुर)
2- आयुष प्रसाद (नासिक)
3- जितेंद्र डूडी (पुणे)
4- किशन नारायणराव जावले (रायगढ़)
5- सौरभ कटियार (मुंबई उपनगरीय)

मेघालय
1- अभिनव कुमार सिंह (वेस्ट जयंतिया)
2- विभोर अग्रवाल (वेस्ट गारो हिल्स)
3- रोसेटा मैरी कुर्बह (ईस्ट खासी हिल्स)

राजस्थान
1- अंकित (डूंगरपुर)
2- अलोक रंजन (चित्तौड़गढ़)
3- अरुण गर्ग (झुंझुनूं)
4- जितेंद्र कुमार सोनी (जयपुर)
5- टीना डाबी (बाड़मेर)

हरियाणा
1- अजय कुमार (गुरुग्राम)
2- आयुष सिन्हा (फरीदाबाद)
3- नेहा सिंह (सोनीपत)
4- सतपाल शर्मा (पंचकुला)

हिमाचल प्रदेश
1- अनुपम कश्यप (शिमला)
2- अपूर्व देवगन (मंडी)
3- गंधर्वा राठौड़ (हमीरपुर)
4- मनमोहन शर्मा (सोलन)
5- हेमराज बैरवा (कांगड़ा)

एजीएमयूटी कैडर
1- अंकित यादव (नॉर्थ गोआ)
2- लक्ष्य सिंघल (दक्षिण दिल्ली)
3- मेकला चैतन्य प्रसाद (दक्षिण-पश्चिम दिल्ली)
4- विशाखा यादव (कुरुंग कुमे, अरुणाचल)
5- सलोनी राय (उधमपुर/ उत्तरी दिल्ली)
6- सनी कुमार सिंह (नई दिल्ली)

इस प्रक्रिया के अंतर्गत सभी चयनित अधिकारियों का मूल्यांकन एक विस्तृत स्टेकहोल्डर सर्वे के माध्यम से किया गया है, जिसमें उन्हें अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक श्रेणी से एक प्रमुख और लोकप्रिय जिलाधिकारी का चयन कर उन्हें फेम इंडिया के विशेष अंक में स्थान दिया जा रहा है।

इंपैक्ट फीचर

देश के हिन्दू तीर्थ स्थलों में बिहार के मधुबनी जिला मुख्यालय के निकट मंगरौनी गांव स्थित एकादश रुद्र महादेव का अलग ही महत्व है. ये महत्व इसलिये भी बढ़ जाता है कि यह अपने आप में दुनिया में अनोखी जगह है , जहां एक साथ शिव के विभिन्न रूपों 11 शिवलिंगों का दर्शन व पूजन का अवसर मिलता है. यहां शिव 11 रूपों महादेव , शिव , रुद्र , शंकर , नील लोहित , ईशान , विजय , भीम देवदेवा , भदोद्भव एवं कपालिश्च के दर्शन का सौभाग्य शिव भक्तों को विशेष तौर पर मिलता है.

मधुबनी में स्थापित है एकादश रुद्र महादेव का दुर्लभ मंदिर

इसके अलावा इस एकादश रुद्र मंदिर परिसर में विष्णु के विभिन्न अवतारों, श्री विद्या यंत्र, विष्णुपद गया क्षेत्र, महाकाल, महाकाली, गणेश सरस्वती आदि साथ ही आम एवं महुआ का आलिंगन-बद्ध वृक्ष, भगवान शिव, पार्वती, महा-लक्ष्मी, महा-सरस्वती यंत्र, विष्णु-पादुका आदि के भी दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है.

इस परिसर स्थित पीपल वृक्ष का भी तांत्रिक महत्तम अलग ही है. कहते हैं कि इसके स्पर्श मात्र से भूत प्रेत के प्रभाव से लोगों को मुक्ति मिल जाती है. वहीं श्री विद्या यंत्र के दर्शन व पूजन से लक्ष्मी एवं सरस्वती दोनों की कृपा बनी रहती है.

सोमवार के दिन यहां भंडारे का आयोजन किया जाता है, इस दिन यहां रुद्राभिषेक एवं षोडषोपचार पूजन करते हैं तो उनकी इच्छित मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं. पंडित जी बताते हैं कि यहां एक ही शक्ति-वेदी पर स्थापित शिव के सभी एकादश रुद्र लिंग रूपों में 10 मई से 21 मई 2000 ई. के बीच विभिन्न तरह की आकृतियां उभर आयीं.

1 महादेव – विगत 30 जुलाई 2001 को अर्द्ध-नारीश्वर का रूप प्रकट हुआ है. कामाख्या माई का ये भव्य रूप है. पांचवें सोमवारी के दिन गणेश जी गर्भ में प्रकट हुए. शिवलिंग पर ये रूप स्पष्ट नजर आती है.

2 शिव – प्रभु श्री राम ने कहा था कि मैं ही शिव हूं. इस लिंग में सिंहासन का चित्र उभरा है, जो प्रभु श्री राम का सिंहासन दर्शाता है.

3 रुद्र – भय को हराने वाले इस लिंग में बजरंगबली पहाड़ लेकर उड़ रहे है बड़ा ही अद्भुत चित्र प्रकट हुआ है.

4 शंकर – गीता के दसवें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं ही शंकर हूं. इस लिंग में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, बांसुरी और बाजूबंध स्पष्ट दृष्टिकोण होता है.

5 नील लोहित– जब महादेव ने विषपान किया था, तब उनका नाम नील लोहित पड़ गया था. इस लिंग में सांप एवं ऊँ का अक्षर प्रकट हुआ है.

6 ईशान – हिमालय पर निवास करने वाले महादेव जिसे केदारनाथ कहते हैं विगत नौ जुलाई 2001 सावन के पहले सोमवार को राजराजेश्वरी का रूप प्रकट हुआ.

7 विजय – इस शिवलिंग में छवि बन रही है जिस कारण आकृति अस्पष्ट है.

8 भीम – महादेव का एक रूप भी है. इस शिवलिंग में गदा की छवि उभर कर सामने आयी है. गदा का डंडा अभी धीरे-धीरे प्रकट हो रहा है.

9 देवादेव – ये लिंग सूर्य का रूप है. इस शिवलिंग में गदा के नीचे दो भागों से सूर्य की किरणें फूटकर शीर्ष में मिल रही है.

10 भवोद्भव – इस लिंग में उमा शंकर की आकृति प्रकट हुई है. दोनों आकृतियां धीरे-धीरे बढ़ रही है.

11 कपालिश्च– महादेव का एक रूप बजरंगबली है. बजरंगबली ब्रह्मचारी थे, इसलिये संभवतः इस लिंग में कोई चित्र नहीं उभर रहा है.

> कांची पीठ के शंकराचार्य जयेन्द्र सरस्वती, बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल व अधीक्षण पुरातत्व-विद डॉ. फणीकांत मिश्र आदि आये तो यहां शिव के एकादश रुद्र का अलौकिक रूप देख भाव विह्वल हो गये. उन्होंने कहा कि ये अपने आप में धार्मिक दृष्टिकोण से अद्वितीय पूजन व तीर्थ स्थल है.

किसी दिन ये शिवलिंग अपने आप पूरा लाल हो जायेगा.

बाबा जी का कहना है कि सभी शिव भक्तों को मात्र एक बार आकर इन शिवलिंगों उभरी हुई आकृतियों को देखे तो पता लगेगा कि ऐसे शिवलिंग विश्व में कहीं भी नहीं हैं

गौरतलब है कि प्रसिद्ध तांत्रिक पंडित मुनीश्वर झा ने 1953 ई. में यहां शिव मंदिर की स्थापना की थी. इस मंदिर में स्थापित सभी शिवलिंग काले ग्रेनाइट पत्थर के बने हुए हैं जिनका प्रत्येक सोमवार शाम को दूध, दही, घी, मधु, पंचामृत, चंदन आदि से स्नान होता है. श्रृंगार के लिये विशेष तौर पर कोलकाता से कमल के फूल मंगाये जाते हैं. प्रधान पुजारी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पितरों का पिंडदान करने नहीं गया नहीं जा पाते उनके लिये यहां गया क्षेत्र बना है जहां पिण्डदान कर मुक्ति पायी जाती है.

11th EDITION
Organized By
Madurai District Tiny &
Small Scale Industries Association
MADITSSIA
BOOK YOUR STALL NOW
99622 20666
80980 98700
73389 96593
MADITSSIA'S
PRINT N PACK
2026
PRINTING & PACKAGING FAIR
24 | 25 | 26
JULY 2026
IDA-SCUDDER TRADE CENTRE
Velammal Medical College Campus, Madurai
SUPPORTED BY:
Ministry of MSME, Govt. of India
UDYAM-TN-03-0020707
FaMe TN
SIPCOT
TMB
sidbi
Canon
EPSON
KONICA MINOLTA
JK PAPER LTD.
TNPL
Makers of Eco Friendly Paper
SPONSORED BY
JAYASHREE
SPUN BOND
KOSAMBE PRIVATE LIMITED
GREEN POWERS
ADHIS
Prakash Green Energy
LASER DIE MFG CO.
thandora
UniPackaging Solutions
BMC PACKAGING

फेम इंडिया–एशिया पोस्ट सर्वे

देश के सर्वश्रेष्ठ लोकसभा सांसदों का चयन

भारत विश्व का सबसे बड़ा और सबसे सशक्त लोकतंत्र है। यहां की लोकतांत्रिक परंपराएं, संसदीय मर्यादाएं और जनप्रतिनिधित्व की व्यवस्था पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का विषय रही हैं। भारतीय संसद केवल कानून बनाने की संस्था नहीं, बल्कि देश की आकांक्षाओं, उम्मीदों और भविष्य की दिशा तय करने वाला सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच है। संसद में बैठने वाले सांसद जनता की आवाज़ बनकर राष्ट्रीय नीतियों, विकास योजनाओं, बजट, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक संतुलन को मजबूत करते हैं। ऐसे में सांसदों की सक्रियता, ईमानदारी, जवाबदेही और दूरदर्शिता लोकतंत्र की मजबूती के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाती है।

इन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों और सकारात्मक जनप्रतिनिधित्व को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से फेम इंडिया मैगज़ीन अपने आगामी अंक में देश के "सर्वश्रेष्ठ लोकसभा सांसद" सर्वेक्षण को प्रकाशित करने जा रही है। यह सर्वे प्रतिष्ठित सर्वे एजेंसी एशिया पोस्ट सर्वे के सहयोग से किया जा रहा है। इस व्यापक सर्वेक्षण में देशभर के उन सांसदों का मूल्यांकन किया जा रहा है जिन्होंने संसदीय कार्यों, जनसरोकारों, विकास योजनाओं, सामाजिक प्रतिबद्धता और प्रभावी नेतृत्व के माध्यम से उल्लेखनीय कार्य किए हैं।

फेम इंडिया पिछले कई वर्षों से समाज में सकारात्मक पत्रकारिता को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रहा है। पत्रिका का उद्देश्य केवल समाचार प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि उन व्यक्तित्वों और संस्थाओं को सामने लाना भी है जो अपने कार्यों से समाज और राष्ट्र निर्माण में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। फेम इंडिया मैगज़ीन लगातार विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सर्वे और रेटिंग के माध्यम से राष्ट्रीय पहचान दिलाने का प्रयास करती रही है। इसी कड़ी में इससे पहले भी श्रेष्ठ सांसद, लोकप्रिय जिलाधिकारी, असरदार ब्यूरोक्रेट्स, उम्दा विधायक और अन्य जनसेवा से जुड़े व्यक्तित्वों पर व्यापक सर्वे प्रकाशित किए जा चुके हैं।

फेम इंडिया–एशिया पोस्ट द्वारा किया जा रहा यह सर्वे केवल लोकप्रियता तक सीमित नहीं है, बल्कि सांसदों के समग्र कार्यों और जनहित में निभाई गई उनकी भूमिका का बहुआयामी आकलन है। सर्वे में सांसदों की संसदीय उपस्थिति, बहसों में सहभागिता, जनहित के मुद्दों को उठाने की क्षमता, क्षेत्रीय विकास कार्य, जनता से संवाद, सामाजिक छवि, जवाबदेही, नवाचार, विकासवादी सोच और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को आधार बनाया जा रहा है। इसके साथ ही जनता, बुद्धिजीवियों, सामाजिक संगठनों, पत्रकारों तथा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की राय को भी सर्वे का हिस्सा बनाया गया है।

फेम इंडिया मैगज़ीन का मानना है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जनप्रतिनिधियों के सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों को समाज के सामने लाया जाएगा। वर्तमान समय में जहां नकारात्मक खबरें अधिक चर्चा में रहती हैं, वहीं ऐसे सांसद भी हैं जो चुपचाप अपने क्षेत्र और देश के विकास के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। इन जनप्रतिनिधियों की पहचान और उनके योगदान को सम्मान देना एक स्वस्थ लोकतांत्रिक संस्कृति का हिस्सा है। यही कारण है कि फेम इंडिया ने एक बार फिर श्रेष्ठता को सम्मान देने की अपनी सामाजिक परंपरा को आगे बढ़ाया है।

सर्वेक्षण में विशेष रूप से उन सांसदों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जिन्होंने संसदीय गरिमा बनाए रखते हुए विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, युवा कल्याण, ग्रामीण विकास, आधारभूत संरचना, सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय पहल की है। इसके अतिरिक्त ऐसे सांसदों को भी प्राथमिकता दी जा रही है जिन्होंने संकट के समय जनता के बीच रहकर संवेदनशीलता और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया।

फेम इंडिया मैगज़ीन के अनुसार, लोकतंत्र में जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच विश्वास का रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण होता है। सांसद केवल राजनीतिक प्रतिनिधि नहीं, बल्कि समाज और सरकार के बीच एक मजबूत सेतु होते हैं। उनकी सक्रियता और संवेदनशीलता देश के विकास की गति को प्रभावित करती है। ऐसे में बेहतर कार्य करने वाले सांसदों को सामने लाना और उनके कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना समाज के लिए प्रेरणादायक साबित हो सकता है।

यह सर्वे देश की लोकतांत्रिक चेतना को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है। फेम इंडिया का उद्देश्य राजनीति में सकारात्मकता, जवाबदेही और विकासोन्मुख सोच को प्रोत्साहित करना है ताकि जनप्रतिनिधियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण बने और लोकतंत्र अधिक सशक्त हो सके।

फेम इंडिया और एशिया पोस्ट की टीम द्वारा सर्वेक्षण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है तथा इसके परिणाम आगामी जुलाई अंक में प्रकाशित किए जाएंगे। इस विशेषांक में चयनित सांसदों के कार्यों, उपलब्धियों और जनसेवा से जुड़े प्रयासों को विस्तार से प्रस्तुत किया जाएगा ताकि देश की जनता उन जनप्रतिनिधियों को बेहतर ढंग से जान सके जो वास्तव में लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं।

फेम इंडिया का मानना है कि "सोच बदलने से ही समाज बदलता है" और सकारात्मक कार्यों को सम्मान देना एक स्वस्थ राष्ट्र निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यही प्रयास इस सर्वेक्षण के माध्यम से भी किया जा रहा है।

शक्ति से समृद्धि

नारी
उत्तर प्रदेश
के विकास
की धुरी

नवनिर्माण के
9
वर्ष

सुरक्षा से समझौता नहीं
सभी थानों में 'मिशन शक्ति' केंद्र

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
26.81 लाख+
बेटियां सशक्त

निराश्रित महिलाओं को पेंशन

लखपति दीदी योजना
18.55 लाख+
महिलाएं बनीं लखपति

महिला श्रम बल भागीदारी
13% से बढ़कर 36%

1 करोड़+
ग्रामीण महिलाएं बनीं आत्मनिर्भर

मेधावी छात्राओं को स्कूटी का उपहार

कामकाजी महिलाओं के लिए
श्रमजीवी महिला छात्रावास

महिला उद्यमी क्रेडिट कार्ड
ब्याज मुक्त ऋण

10,400+
स्टार्ट-अप का नेतृत्व

विकास की गति अपार-डबल इंजन सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

UPGovtOfficial | CMOUttarpradesh | CMOfficeUP